{ विश्वास वही रफ्तार नई }

बालाघाट
गुरुवार 08 अक्टूबर 2026
अश्विन कृष्ण 12 विक्रम सम्वत 2083
वर्ष 17, अंक 18
पृष्ठ 12
मूल्य ₹ 7.00

PMG पद्मेश मीडिया समूह का प्रकाशन

बालाघाट एक्सप्रेस

हिन्दी दैनिक

सेंसेक्स	-	72,382.47
निफ्टी	-	22,555.75
सोना	-	1,57,755
चांदी	-	2,35,000
डॉलर	-	96.33

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

खास खबर

उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को पैरोल

जयपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को पैरोल देने के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 20 दिन की पैरोल पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरे राज्य में दोषी होने पर राजस्थान हाईकोर्ट से मिली पैरोल रोकी नहीं जा सकती है। आसाराम की पैरोल को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने ने साफ किया कि 3 अगस्त को जारी किए गए 20 दिन की पैरोल के आदेश पर अब तक अमल क्यों नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने ने सरकार को आदेश की पालना करते हुए आसाराम की रिहाई और इसकी अनुपालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

अमूल और देवभोग घी जानलेवा?

रायपुर। राजधानी में बिक रहे घी की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अलग-अलग इलाकों से घी के 12 नमूने लेकर जांच के लिए भोपाल की प्रयोगशाला भेजे थे। मंगलवार को मिली रिपोर्ट में छह नमूने निर्धारित खाद्य मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इनमें अमूल, देवभोग, कीर्ति गोल्ड, वचन, देसी घी धौलपुर और वास्तु एगमार्क घी शामिल हैं। जांच में इन नमूनों में लेड की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक मिली है। रिपोर्ट के अनुसार घी में लेड की मानक सीमा 0.02 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम तय है, जबकि अमूल में 0.037, देवभोग में 0.035, देसी घी धौलपुर में 0.043, वचन में 0.161, कीर्ति गोल्ड में 0.192 और वास्तु एगमार्क में 0.154 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम लेड पाया गया। खास तौर पर कीर्ति गोल्ड में मानक से करीब 10 गुना अधिक लेड मिला है। विभाग ने रायपुर के अलग-अलग क्षेत्रों से ये नमूने लिए थे। रिपोर्ट सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि, केवल इस जांच के आधार पर किसी उत्पाद को 'जानलेवा' कहना उचित नहीं होगा।

पतंजलि ने वापस लिया 50 करोड़ का मानहानि केस

इंदौर। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने भाजपा सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर 50 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा वापस ले लिया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कंपनी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया है और अब वे इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इसके बाद पतंजलि ने मुकदमा वापस लेने की अनुमति मांगी। यह विवाद नवंबर 2022 में शुरू हुआ था। बृजभूषण ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान पतंजलि के घी की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। उनके बयान के बाद पतंजलि ने आरोप लगाया था कि टिप्पणियों से कंपनी की ब्रांड छवि, शेयर मूल्य और व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुंचा है।

कुछ ना कहना

एसआईआर पर रार- मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे तक आंदोलन करने को विपक्ष तैयार...जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के दौरान राहुल-प्रियंका समेत कई नेता हिरासत में

ज्ञानेश के इस्तीफे पर घमासान, सड़क पर संग्राम

नई दिल्ली। एसआईआर रोकने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया ब्लॉक का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। जंतर-मंतर पर धरना देने के लिए इंडिया ब्लॉक के सांसद बस में सवार होकर रवाना हुए तो पुलिस बल ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। इंडिया गठबंधन के सांसदों की बस से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ उतरते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि क्या यह कोई तरीका है? आप देख सकते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर प्रयंका गांधी ने सडक़ पर लेटकर धरना शुरू कर दिया।

कुछ देर मान-मनौव्वल के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके बाद कई नेताओं और सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस के जवानों ने प्रियंका गांधी वाड्रा को जंतर-मंतर के पास उस जगह से हटा दिया, जहां इंडिया गठबंधन के सांसदों को प्रदर्शन स्थल की ओर आगे बढऩे से रोका गया था। इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हिरासत में लिए जाने के वक्त आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि उन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। इसके लिए ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और पीएम मोदी सभी जिम्मेदार हैं। हमने वर्षों से ऐसे दृश्य नहीं देखे थे। यह बर्बरता की हद है। आप सभी बेनकाब हो चुके हैं। आप सभी कायर हैं। विपक्ष का यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहा है। विपक्षी दल एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बडिय़ों का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों का जवाब मिलना चाहिए और ज्ञानेश कुमार को पद से इस्तीफा देना चाहिए।

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 10 अक्टूबर से प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को बोल रही है कि दिल्ली पहुंचकर पत्थरबाजी करो। लाठियां चलाओ। क्या सरकार देश में गृहयुद्ध चाहती है? हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि सुधर जाइए। देश का युवा जवाबदेही मांग रहा है। पिछली गलती को मत दोहराइए। दरअसल, दिल्ली के प्रेस क्लब में कॉकरोच जनता पार्टी और लेफ्ट के छात्र संगठनों ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आगे कहा कि ज्ञानेश कुमार को सिर्फ हटाया न जाए उन पर केस भी हो और उन्हें सजा मिले। एक स्वतंत्र कमेटी उनकी और उनके फैसलों की जांच करे। 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए प्रदर्शन करने वाली है। 20 जून से 25 जुलाई तक कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए 36 दिन तक दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर बैठे थे। सौरव दास ने कहा कि दिल्ली पुलिस के मेल पुलिसकर्मी फीमेल प्रदर्शनकारियों से बदसलूकी कर रहे हैं। ऐसे कोई भी दरिंदे जो दिल्ली पुलिस में हैं, जिन्हें पैसों से भर्ती किया गया है उन्हें छोडऩा नहीं है। सौरव दास ने कहा कि जब हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे तब पुलिस ने बर्बरता की।

सांसदों को पीट रही है पुलिस- प्रियंका

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ये लोग चुनाव आयुक्त से मिलने की गुहार

लगाने वाले सांसदों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। वे सांसदों को पीट रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने मुझे जगह-जगह खरोंच दिया है। उन्होंने हमें जमीन पर पटक दिया है। अब हम यहां से नहीं हटेंगे। चाहे वे अपने बल वापस बुला लें, मैं यहां से नहीं हटूंगी।

वे गुंडागर्दी का ले रहे सहारा- रेणुका चौधरी

इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि वे (केंद्र सरकार) गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हैं। हम डरेंगे नहीं। हम देश के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं।

पुलिस कर रही मारपीट और लाठीचार्ज-महुआ मोइत्रा

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों

के साथ कितनी क्रूरता से पेश आ रही है। ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा। हमारी गलती क्या है? दिल्ली पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ इतनी बेरहमी से मारपीट और लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है? सांसदों को जंतर-मंतर तक पहुंचने से क्यों रोका जा रहा है? आखिर यहां क्या हो रहा है?

एफआईआर मेरे लिए मेडल- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा है कि उनके खिलाफ

45 एफआईआर दर्ज हैं और वह इनसे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि यह संख्या 100 तक पहुंचे। राहुल गांधी ने 100 एफआईआर को मेडल की तरह बताया और कहा कि वह इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे।

महाराष्ट्र में पैर नहीं रखने देंगे- हर्षवर्धन सपकाल

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी करके भाजपा को चुनाव जिताने में मदद की है, यह अब स्पष्ट हो गया है। देशभर में वोट चोर ज्ञानेश कुमार और उनके आका मोदी-शाह के खिलाफ भारी आक्रोश है। इसी वजह से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने उप्र और छग के कार्यक्रम रद्द किए हैं।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले फैसले की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट

आयुक्तों के नियुक्ति पैनल से सीजेपी को हटाने का मामला, सुनवाई कर रहे जजों में सहमति नहीं थी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े अपने फैसले की फिर से जांच करेगा। 23 सितंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने के मुद्दे पर अलग-अलग राय दी थी। जस्टिस दत्ता ने कहा था कि मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की जरूरत नहीं है। वहीं, जस्टिस शर्मा ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का समर्थन किया था। लेकिन इस फैसले पर अर्जी में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को लेकर पक्षपात की आशंका जताई गई है। उनके बेटे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्टैंडिंग काउंसिल हैं।

पूरा मामला 2023 के केंद्र सरकार के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा था चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा फैसला बदला था। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने अर्जी रखी थी। बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं।

2023 के में बदला नियुक्ति का कानून

2023 से पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संसद का कोई अलग कानून नहीं था। केंद्र सरकार (कैबिनेट) अपनी पसंद के नाम तय करती थी और राष्ट्रपति की मंजूरी से उनकी सीधी नियुक्ति हो जाती थी, यानी पूरा फैसला अकेले सरकार का होता था। 2023 के बाद क्संसद ने नया कानून बनाया, जिसके तहत 3 सदस्यों की चयन समिति तय की गई। अब इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री मिलकर नाम तय करते हैं, जिससे नियुक्ति में विपक्ष की भागीदारी तो जुड़ी, लेकिन सरकार के पास 2 सदस्यों का बहुमत बना रहा।

मिथुन चक्रवर्ती को कैबिनेट मंत्री का दर्जा, पश्चिम बंगाल सरकार ने बनाया सांस्कृतिक सलाहकार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मिथुन चक्रवर्ती को बड़ी जिम्मेदारी दी है। राज्य सरकार ने उन्हें सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग का सांस्कृतिक सलाहकार नियुक्त किया है। इसके साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है, जब पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद सांस्कृतिक और फिल्म क्षेत्र को लेकर कई अहम पहल की जा रही हैं। मिथुन चक्रवर्ती लंबे समय से बंगाली और हिंदी सिनेमा से जुड़े रहे हैं और राज्य के सांस्कृतिक क्षेत्र में उनकी मजबूत पहचान है। सितंबर में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में उत्तम कुमार फिल्म सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मिथुन चक्रवर्ती को राज्य सरकार का सांस्कृतिक सलाहकार बनाए जाने की घोषणा की थी।

मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियानों में भी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी के समर्थन में प्रचार किया था। ऐसे में उनकी नियुक्ति को राजनीतिक और सांस्कृतिक, दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि मिथुन चक्रवर्ती के अनुभव और फिल्म जगत में उनकी व्यापक पहचान का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में किया जा सकेगा।

संवैधानिक पाप करने वालों को चुनाव चिन्ह क्यों- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। शिवसेना के चुनाव चिन्ह विवाद पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि दल-बदल को संविधान के तहत 'संवैधानिक पाप' माना जाता है, तो ऐसे मामलों में शामिल लोगों को चुनाव चिन्ह का लाभ क्यों दिया जाए? सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि मामला केवल धनुष-बाण चुनाव चिन्ह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि चुनाव चिन्ह आवंटित करते समय विधायकों की संख्या को कितना महत्व दिया जाना चाहिए। खासकर तब, जब उन्हीं विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी कार्यवाही लंबित हो। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि संगठनात्मक समर्थन को बहुमत का सुरक्षित आधार कैसे माना जा सकता है। मामला शिवसेना में विभाजन के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन से जुड़ा है। सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के सवालों से संकेत मिलता है कि वह चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया और उसके संवैधानिक प्रभावों की गहराई से समीक्षा कर रहा है।

राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जमा करने होंगे दो करोड़

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अभिनेता राजपाल यादव को निर्देश दिया है कि वह चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता को देय रकम में से 2 करोड़ रुपये 13 अक्टूबर तक जमा करें। कोर्ट ने साफ कहा कि रकम जमा किए जाने के बाद ही वह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजपाल यादव की याचिका पर विचार करेगा। राजपाल यादव आज खुद कोर्ट में मौजूद थे और अपने साथ 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेकर पहुंचे थे। बाकी 85 लाख रुपये 13 अक्टूबर तक उनकी संपत्ति के खरीदार के जरिए जमा किए जाने हैं, जो राजपाल के साथ कोर्ट में मौजूद था।

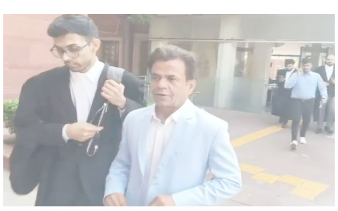

बार-बार मोहलत देना मजबूरी नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि उनकी सजा बढ़ाई भी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि अब तक जो बार-बार मोहलत दी गई, उसका मकसद सिर्फ यही था कि शिकायतकर्ता को उसका पैसा मिल सके। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की, कानून का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने साफ किया कि रकम जमा कराने का आदेश इसलिए दिया गया है ताकि शिकायतकर्ता के पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हालांकि, अदालत ने कहा कि राजपाल यादव का अब तक का आचरण उसे संतुष्ट नहीं करता।

अता पता लापता फिल्म का जिक्र आया तो कोर्ट में छा गई हल्की मुस्कान

आदेश पारित करने के बाद पीठ और राजपाल यादव के बीच कुछ हल्की-फुल्की बातचीत भी हुई। राजपाल ने अपनी फिल्म अता पता लापता से हुए आर्थिक नुकसान का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि फिल्म की वजह से उन्हें करीब 200 से 250 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और फिल्म के निर्माता भी घाटे में रहे। इसी दौरान सीजेआई ने मजाकिया अंदाज में फिल्म के नाम को राजपाल यादव के मौजूदा हालात से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, आपकी फिल्म की तरह आपका पैसा भी अता पता लापता है, गायब। अदालत की इस टिप्पणी पर माहौल कुछ हल्का हो गया।

महंगाई बढ़ी, अब कर्ज लेना और चुकाना महंगा

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की तीन दिवसीय मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बैठक के नतीजे आ गए हैं। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करते हुए लोन लेने वालों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है और इसमें 25 बीपीएस का इजाफा करते हुए इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले करीब चार साल से ये 5.25 पर स्थिर था। केंद्रीय बैंक के इस फैसले से होम लोन या कार लोन लेने वाले ग्राहकों पर ईएमआई का बोझ बढ़ सकता है। महंगाई और बढऩे वाली है, ये तो तय है। साथ में बैंकों से कर्ज लेना भी महंगा होने वाला है। ये बातें रिजर्व बैंक की हैं।

रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेता है। फॉर्मूला ये है कि रिजर्व बैंक महंगा कर्ज बैंको को देगा तो बैंक और महंगा कर्ज लोगों को देंगे, तो लोग कम कर्ज लेंगे, तो खर्च भी कम करेंगे। खर्च कम करेंगे तो महंगाई काबू में रहेगी। रिजर्व बैंक कह रहा कि इस साल महंगाई दर 5.0 प्रतिशत से बढक़र 5.2 प्रतिशत हो सकती है। आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की तीन दिन चली बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज 7 अक्टूबर को नई ब्याज दरों की जानकारी दी। साथ में ये भी कहा है कि आने वाले कुछ महीनों में रेपो बढ़ तो सकता है, लेकिन घटेगा नहीं।

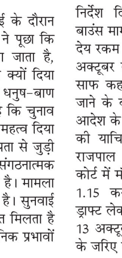

फिलहाल ब्याज दरें घटने का रास्ता बंद

आरबीआई ने अपना रुख बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' कर दिया है। यानी, फिलहाल ब्याज दरों में कटौती का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। आने वाली बैठकों में रिजर्व बैंक या तो दरों को जैसा है वैसा ही रखेगा, या फिर जरूरत पडऩे पर इन्हें और बढ़ा सकता है। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि 0.25 प्रतिशत की यह बढ़ोतरी तो उम्मीद के मुताबिक ही थी, लेकिन असली बात नीति में हुआ बदलाव है। इससे साफ जाहिर होता है कि रिजर्व बैंक के लिए अब सबसे पहला काम महंगाई पर काबू पाना है। कोटक महिंद्रा बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट उपासना भारद्वाज का मानना है कि आने वाले समय में ब्याज दरों में 0.25 से 0.50 प्रतिशत की और बढ़ोतरी हो सकती है। डीबीएस बैंक की सीनियर इकोनॉमिस्ट राधिका राव का कहना है कि यह बदलाव दर्शाता है कि आरबीआई महंगाई के रिस्क को जड़ पकडऩे से रोकना चाहता है।

वेस्ट एशिया संघर्ष और कच्चे तेल की कीमतों का असर

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वेस्ट एशिया संघर्ष और कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की।

बंगाल एसआईआर : जजों ने गिनाई चुनाव आयोग के पोर्टल की कमियां, कहा

न नोटिस, न सुनवाई और न वापस जोड़ सकते नाम

कोलकाता । पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। उनकी अपील सुनने के लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। लेकिन, उन्हीं ट्रिब्यूनल जजों का कहना है कि चुनाव आयोग का पोर्टल काम नहीं कर रहा है। एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से हटे नामों की अपील सुन रहे सभी 19 जजों का आरोप है कि पोर्टल में कई जरूरी सुविधाएं ही नहीं हैं। इसकी वजह से नोटिस भेजने से लेकर सुनवाई और डिलीट हुए नामों को दोबारा जोडऩे तक का काम प्रभावित हो रहा है।

जजों ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने पोर्टल की कई कमियां गिनाई हैं। 11 अगस्त को ट्रिब्यूनल के जजों ने अपनी शिकायतें चुनाव आयोग और

कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी थीं। जजों के मुताबिक, पोर्टल में कई जरूरी सुविधाएं नहीं हैं। पोर्टल की कमियों की वजह से ट्रिब्यूनल के लिए अपीलों की सुनवाई और उनका निपटारा करना मुश्किल है। अगर अपील में लगे दस्तावेज अधूरे हैं या और कागजात चाहिए तो पोर्टल पर उन्हें सुरक्षित रखने या अपलोड करने का कोई सिस्टम नहीं है। अगर जज वीडियो कॉल से सुनवाई करना चाहें, तो पोर्टल में ये सुविधा ही नहीं है।अगर जज फैसला करें कि किसी का नाम फिर से डालना है, तो पोर्टल पर ये काम नहीं हो पाता। अपील करने वाले व्यक्ति को ट्रिब्यूनल के फैसले की कॉपी डाउनलोड करने का विकल्प नहीं है।

पहले भी की शिकायत

ये सारी शिकायतें अगस्त में हुई बैठक में उठाई। ट्रिब्यूनल के जजों ने चुनाव आयोग और कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये दिक्कतें बताई थीं। वैसे ये शिकायतें नई नहीं हैं। 22 मई में भी एक जज ने पत्र लिखकर कहा था कि नोटिस भेजने का सिस्टम न होने से काम बहुत धीमा चल रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाए थे कि चुनाव आयोग गलत आंकड़े दे रहा है।

स्वामित्व योजना पर पटवारियों का फूटा गुस्सा, ऑनलाइन कार्यों का किया बहिष्कार

सरकारी व्हाट्सऐप ग्रुप भी छोड़ेंगे पटवारी, 8-9 अक्टूबर सामूहिक अवकाश के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

पदमेश न्यूज। बालाघाट। स्वामित्व योजना को लेकर पटवारियों और शासन के बीच चल रहा विवाद अब आंदोलन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पटवारियों के खिलाफ सेवा समाप्ति, निलंबन और अन्य दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के विरोध में पटवारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। बालाघाट पटवारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर देवास सहित अन्य जिलों में की गई कार्रवाई तत्काल वापस लेने की मांग की है। संघ के पदाधिकारियों अरुण बिरनवार और गिरधारी भगत का कहना है कि स्वामित्व योजना में पटवारियों को विक्रेता की भूमिका दिए जाने पर पहले ही आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन शासन ने उनकी बात पर गंभीरता से विचार करने के बजाय योजना में काम नहीं करने वाले पटवारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी।

पटवारी पदाधिकारियों ने कहा कि स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी कई विधिक और व्यवहारिक दिक्कतों से शासन को पहले ही अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद देवास जिले में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 सहित अन्य कार्यों को आधार बनाकर पटवारियों की सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी निलंबन और दूसरी दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है। संघ का कहना है कि किसी योजना के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक परेशानियों का समाधान बातचीत से होना चाहिए, न कि सीधे पटवारियों को दंडित करके। कार्रवाई से प्रदेशभर के पटवारियों में नाराजगी बढ़ गई है और अब यह विरोध जिला स्तर से निकलकर प्रदेशव्यापी आंदोलन का रूप लेने की तैयारी में है। संघ ने शासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि 8 अक्टूबर से बालाघाट जिले के पटवारी शासन के ऑनलाइन कार्यों से दूरी बनाएंगे। इसके साथ ही शासकीय व्हाट्सऐप ग्रुपों से भी पटवारी स्वयं को अलग कर लेंगे। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि यह आंदोलन का पहला चरण होगा। यदि इस दौरान भी सेवा समाप्ति, निलंबन और अन्य दंडात्मक कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पटवारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और प्रदेश संगठन के निर्णय के अनुसार आगे की रणनीति पर अमल किया जाएगा। पटवारी संघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि यदि 7 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो 8 और 9 अक्टूबर को प्रदेशभर के पटवारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन राजस्व कार्यों से पूरी तरह विरत रहने के साथ शासकीय व्हाट्सऐप समूहों से भी दूरी बनाई जाएगी। संघ ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि इसके बाद भी शासन ने मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो बिना किसी पूर्व सूचना के टोटल शटडाउन और अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाया जा सकता है। पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि भविष्य में प्रदेश के किसी भी जिले में पटवारियों के खिलाफ इसी तरह की

सेवा समाप्ति, निलंबन या दंडात्मक कार्रवाई की गई तो संगठन इसे स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में प्रदेशभर के पटवारी एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। संघ ने प्रशासन से देवास सहित अन्य जिलों में की गई कार्रवाई तत्काल वापस लेने और स्वामित्व योजना से जुड़ी समस्याओं पर पटवारी संगठनों के साथ चर्चा कर व्यावहारिक समाधान निकालने की मांग की है। अब मामला शासन और पटवारी संगठन के बीच सीधे टकराव की स्थिति में पहुंचता दिखाई दे रहा है। एक ओर सरकार राजस्व कार्यों और स्वामित्व योजना को समयसीमा में पूरा कराने के लिए सख्ती बरत रही है, वहीं पटवारी संगठन कार्रवाई के विरोध में कामकाज रोकने की तैयारी में है। यदि दोनों पक्षों के बीच समय रहते सहमति नहीं बनती है तो इसका असर ऑनलाइन राजस्व सेवाओं के साथ आम नागरिकों से जुड़े कई कामों पर पड़ सकता है। अब देखना यह है कि 7 अक्टूबर की शाम तक शासन पटवारियों की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई वापस करता है या फिर 8 अक्टूबर से प्रदेशभर में राजस्व कामकाज पर आंदोलन की छाया पड़ती है।

नर्सींग नाले पर पुलिया नहीं बनी तो चुनाव बहिष्कार!

वर्षों की अनदेखी से भड़के ग्रामीण, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

पदमेश न्यूज। बालाघाट। किरनापुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बुढ़ी के ग्राम मराठा बुढ़ी से खोड़सिवनी टोला के बीच नर्सींग नाले पर उच्चस्तरीय पुलिया निर्माण की मांग अब ग्रामीणों के लिए केवल विकास का मुद्दा नहीं, बल्कि सुरक्षा और जीवन से जुड़ा सवाल बन चुकी है। वर्षों से पुलिया निर्माण की मांग किए जाने के बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। बारिश के दिनों में नर्सींग नाला उफान पर आते ही दोनों क्षेत्रों के बीच आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। सबसे अधिक

परेशानी स्कूली बच्चों, किसानों और रोजमर्रा के काम से आने-जाने वाले ग्रामीणों को उठानी पड़ती है। ग्रामीणों का दावा है कि नाले को पार करने के दौरान अब तक चार लोगों के बहने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, बावजूद इसके प्रशासन की ओर से स्थायी समाधान नहीं किया गया है।

पुलिया निर्माण की मांग को लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य दुर्गेश बिसेन सहित क्षेत्र के ग्रामीणों ने प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण राजेंद्र ने बताया कि नसिंग नाले पर उच्चस्तरीय पुलिया बनाने की मांग कोई नई नहीं है। कई वर्षों से ग्रामीण इस समस्या को लेकर अधिकारियों और प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार आश्वासन देकर मामला शांत कर दिया जाता है। बारिश शुरू होते ही वही पुरानी समस्या फिर सामने खड़ी हो जाती है। नाला उफान पर आने के बाद ग्रामीणों का संपर्क प्रभावित होने के साथ बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक यहां स्थायी पुलिया का निर्माण नहीं होगा, तब तक हर बारिश में दुर्घटना का खतरा बना रहेगा। ग्रामीणों ने अब प्रशासन को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि पुलिया निर्माण की दिशा में जल्द ठोस पहल नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के साथ आगामी चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लेने पर मजबूर होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से समस्या झेलने के बाद भी यदि उनकी मूलभूत मांग पूरी नहीं होती है तो चुनाव के समय नेताओं और जनप्रतिनिधियों से सवाल किया जाएगा कि जब वोट मांगने गांव तक पहुंचा जा सकता है, तो बारिश के दिनों में ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए पुलिया क्यों नहीं बनाई जा सकती। राजेंद्र ने कहा कि ग्रामीण विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिससे बारिश के दौरान बच्चों और ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नाला पार न करना पड़े। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले को केवल कागजी कार्रवाई और आश्वासन तक सीमित न रखते हुए नसिंग नाले का तत्काल स्थल निरीक्षण कराया जाए और उच्चस्तरीय पुलिया निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाए। उनका कहना है कि यह मार्ग आसपास के गांवों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है और पुलिया बनने से ग्रामीणों को वर्षभर सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। अब ग्रामीणों की चेतावनी के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। यदि इस बार भी मांग को नजरअंदाज किया गया तो चुनाव बहिष्कार की चेतावनी आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है।

विष्णुधाम में 25 अक्टूबर से गूंजेगी हनुमंत कथा, 205 फीट हनुमान प्रतिमा के महासंकल्प को मिलेगी नई दिशा

13 अक्टूबर तक दुर्गा पंडाल प्रतियोगिता में पंजीयन, नगरीय-ग्रामीण श्रेणियों में समितियों को मिलेगा सम्मान

पदमेश न्यूज। बालाघाट। भरवेली के समीप ग्राम हीरापुर स्थित श्री सिद्धपीठ विष्णुधाम मंदिर में 25 से 29 अक्टूबर तक श्री हनुमंत कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट द्वारा हनुमान जी महाराज की विश्व की सबसे ऊंची 205 फीट प्रतिमा स्थापना एवं भव्य मंदिर निर्माण के महासंकल्प को लेकर धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला शुरू की जा रही

है। ट्रस्ट अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी ने 7 अक्टूबर को स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि श्री हनुमंत कथा का वाचन श्री बागेश्वर धाम सरकार पं. धीरेन्द्र शास्त्री के कृपापात्र आचार्य रोहित रिछारिया द्वारा प्रतिदिन दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक किया जाएगा। कथा के शुभारंभ अवसर पर 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी।

उन्होंने बताया कि कलश यात्रा के बाद धार्मिक संगोष्ठी का आयोजन होगा तथा दोपहर 1 बजे नवरात्रि मां दुर्गा पंडाल प्रतियोगिता में विजेता समितियों को पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किया जाएगा। शाम 7 बजे सुंदरकांड का आयोजन होगा और शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं को विशेष अमृत खीर प्रसाद वितरित किया जाएगा। वहीं 26 से 29 अक्टूबर तक प्रतिदिन दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक हनुमंत कथा होगी। कथा के बाद श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था रहेगी तथा श्री हनुमान अंश मूवी का प्रसारण भी किया जाएगा। इसी आयोजन के तहत श्री सिद्धपीठ विष्णुधाम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जिलेभर के दुर्गा पंडालों के लिए भव्य नवरात्रि मां दुर्गा पंडाल प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली दुर्गा समितियों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 101 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है और समितियां 13 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकती हैं। प्रतियोगिता में मां दुर्गा की प्रतिमा की भव्यता, स्वरूप, कलात्मकता एवं धार्मिक भाव के साथ पंडाल की साज-सज्जा, रचनात्मकता, विषय-वस्तु एवं सुंदरता को आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा पंडाल परिसर की स्वच्छता, अनुशासन, व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए सकारात्मक एवं भक्तिमय वातावरण का भी मूल्यांकन किया जाएगा। किरण भाई त्रिवेदी ने कहा कि इन आयोजनों का उद्देश्य केवल धार्मिक कार्यक्रम करना नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का संरक्षण, धार्मिक चेतना का विस्तार तथा भक्ति और सेवा की भावना को जन-जन तक पहुंचाना है। साथ ही जिले की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करने के लिए भी यह आयोजन महत्वपूर्ण है। पत्रकार वार्ता के दौरान अनिल बिसेन, नरेन्द्र जी महाराज, अमरसिंह धानेश्वर मंदिर के पुजारी, डब्बूलाल नागेश्वर, आशीष साहू, संतोष अर्जुनवार सहित आयोजन समिति के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

पॉलीटेक्निक में दिखी विद्यार्थियों की तकनीकी प्रतिभा, 100 से अधिक मॉडल व प्रोटोटाइप प्रदर्शित

स्थानीय समस्याओं के तकनीकी समाधान पर केंद्रित रही जिला स्तरीय प्रदर्शनी

पदमेश न्यूज। बालाघाट। विद्यार्थियों की तकनीकी प्रतिभा, नवाचार और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सेवा संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत बुधवार 7 अक्टूबर को शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, बालाघाट में जिला स्तरीय तकनीकी मॉडल एवं प्रोटोटाइप प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कलेक्टर कुमार सत्यम के मार्गदर्शन में आयोजित यह प्रदर्शनी शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय एवं सतपुड़ा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक, बालाघाट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बालाघाट-सिवनी लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती भारती पारधी रहीं। इस अवसर पर अन्य जनप्रतिनिधि, सतपुड़ा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक के प्राचार्य एवं डायरेक्टर, जनभागीदारी समिति के सदस्य, विभिन्न महाविद्यालयों से आए विषय विशेषज्ञ एवं निर्णायक, शिक्षक, मेंटर्स, प्रतिभागी विद्यार्थी तथा मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद श्रीमती भारती पारधी ने संस्थान परिसर में मां सरस्वती की पूजा-अर्चना तथा 'एक पौधा मां के नाम' अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कर किया।

स्थानीय समस्याओं के समाधान पर केंद्रित रहे मॉडल

प्रदर्शनी का मुख्य विषय 'स्थानीय समस्याओं के तकनीकी समाधान हेतु नवाचार एवं तकनीकी मॉडल/प्रोटोटाइप निर्माण' रखा गया। इसमें विद्यार्थियों ने कृषि, जल प्रबंधन, सुरक्षा, ऑटोमेशन, स्मार्ट तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े नवाचारों को प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी में विभिन्न स्तरों से 100 से अधिक मॉडल एवं प्रोटोटाइप प्रदर्शित किए गए। इन्हें विद्यालय स्तर, आईटीआई स्तर, पॉलीटेक्निक स्तर, इंजीनियरिंग कॉलेज स्तर तथा राज्य स्तर पर चयनित मॉडल एवं नवाचार की पांच प्रमुख श्रेणियों में रखा गया। विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों ने विज्ञान एवं तकनीक आधारित प्रारंभिक नवाचार प्रस्तुत किए, जबकि आईटीआई स्तर पर व्यावहारिक एवं ट्रेड आधारित मॉडल प्रदर्शित किए गए। पॉलीटेक्निक विद्यार्थियों ने कृषि, जल प्रबंधन और ऑटोमेशन से संबंधित प्रोटोटाइप तैयार किए। इंजीनियरिंग कॉलेज स्तर पर ढ्ढश्रझ एवं ऑटोमेशन आधारित उन्नत तकनीकी मॉडल प्रदर्शित किए गए।

राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत और पेटेंट प्राप्त प्रोजेक्ट भी प्रदर्शित

प्रदर्शनी का विशेष आकर्षण शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालाघाट के चार ऐसे प्रोजेक्ट रहे, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं तथा जिनका पेटेंट भी कराया जा चुका है। इसके अलावा ऑटोमैटिक इरिगेशन सिस्टम, स्मार्ट वाटर पंप, सोलर ट्रैकर, एक्सीडेंट डिटेक्शन सिस्टम सहित कृषि, जल संरक्षण, सुरक्षा एवं स्मार्ट गवर्नेंस से जुड़े कई उपयोगी प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए गए। इन मॉडलों के माध्यम से विद्यार्थियों ने यह प्रदर्शित किया कि तकनीकी शिक्षा को स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़कर समाजोपयोगी समाधान विकसित किए जा सकते हैं। उत्कृष्ट मॉडलों को आगे इन्क्यूबेशन सेंटर एवं तकनीकी मेंटरिंग के माध्यम से व्यावहारिक और सामाजिक उपयोग के लिए विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।

सांसद ने विद्यार्थियों से जानी मॉडलों की कार्यप्रणाली

सांसद श्रीमती भारती पारधी ने प्रदर्शनी में विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए तकनीकी मॉडल एवं प्रोटोटाइप का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यार्थियों से उनके मॉडल की कार्यप्रणाली, उपयोगिता तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान में उसकी भूमिका के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि तकनीकी शिक्षा के साथ नवाचार, रचनात्मक सोच और समाजोपयोगी तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देना आवश्यक है। विद्यार्थियों को अपने ज्ञान एवं तकनीकी कौशल का उपयोग समाज और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए करना चाहिए।

इस अवसर पर शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय के प्राचार्य श्री आर.एम. सोनवे ने संस्था के इतिहास एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संस्था की स्थापना वर्ष 1962 में दानवीर मानेकजी मेरवानजी (मुलनाजी) द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि एवं भवन में 'ओपन डोर पॉलिसी' के अंतर्गत हुई थी। वर्तमान में संस्था में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तथा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य श्री आर.एम. सोनवे ने अतिथियों, निर्णायक मंडल, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी जिला बालाघाट म.प्र.

क्रमांक/7643/अति.कले./वि./पंजी/2026-27

बालाघाट दिनांक 23/09/2026

आम सूचना

हिन्दू विवाह रजिस्ट्रेशन नियम 1984 के नियम (1) 4 के अंतर्गत प्रारूप एक में विवाह के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदकगण श्री राजेश चौरे पिता श्री अनंतराम चौरे उम्र 52 वर्ष जाति महार निवासी वार्ड नंबर 08 आमाटोला (पांढरवानी) तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट म.प्र. एवं आवेदिका श्रीमती भीमकला चौरे पिता श्री रामदास चौहान उम्र 45 वर्ष जाति महार निवासी फुटारा पोस्ट लावनी तहसील खैरलांजी जिला बालाघाट म.प्र. ने उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें उन्हे विवाह पंजीयन जारी किया जाना है। विवाह पंजीयन हेतु सुनवाई दिनांक 22/10/2026 को नियत की गई है।

अत: उक्त विवाह पंजीयन के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह सुनवाई दिनांक 22/10/2026 तक न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी बालाघाट के समक्ष न्यायालयीन समय प्रात: 10 बजे उपस्थित होकर अपनी आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत करें नियत समयावधि के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अपर कलेक्टर
एवं रजिस्ट्रार हिन्दू विवाह
जिला बालाघाट म.प्र.

बारबेड वायर (कांटेदार तार) एवं चेन लिंक जाली उचित दाम पर उपलब्ध
लघु उद्योग निगम भोपाल से संबद्ध

निर्माता
तिरूपति इंजीनियरिंग वर्क्स
मयूर टॉकिज के सामने हनुमान चौक, बालाघाट
फोन:- 07632-243531
मो:- 8989976858, 9425139998

रेत परिवहन को लेकर वनरक्षक और ट्रैक्टर चालक आमने-सामने-दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट

वनरक्षक संतोष धुर्वे ने शासकीय कार्रवाई में बाधा, जातिसूचक गाली-गलौज व मारपीट करने का लगाया आरोप, शहजादा खान ने वनरक्षक पर पैसे मांगने- डंडे से हमला करने और धमकी देने की शिकायत की

पदमेश न्यूज। बालाघाट। मलाजखंड थाना क्षेत्र के ग्राम टिंगीपुर के बाहीटोला में रेत परिवहन को लेकर वन विभाग के वनरक्षक और ट्रैक्टर चालक पक्ष के बीच विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। घटना 6 अक्टूबर की शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है। मामले में वनरक्षक संतोष कुमार धुर्वे तथा दूसरे पक्ष के शहजाद खान ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मलाजखंड पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वनरक्षक की शिकायत-रेत परिवहन रोकने पर किया हमला

वनरक्षक संतोष कुमार धुर्वे ग्राम गढ़ी निवासी मलाजखंड थाना क्षेत्र में आने वाले वन विभाग के देवरी बीट के प्रभारी हैं। 6 अक्टूबर को संतोष धुर्वे वन क्षेत्र में गश्ती पर थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि वन क्षेत्र से होकर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में रेत का परिवहन किया जा रहा है ।सूचना मिलने पर संतोष धुर्वे सुरक्षा कर्मी रामेश्वर धुर्वे और सुरेश टेकाम के साथ बाहीटोला टिंगीपुर पहुंचे। वहां एक नीले रंग के ट्रैक्टर में रेत भरी हुई मिली। ट्रैक्टर को रोककर चालक से पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम साजिद खान पिता अब्दुल सफीक खान ग्राम भीमजोरी निवासी बताया। वनरक्षक संतोष कुमार धुर्वे ने रेत परिवहन से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर साजिद खान कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद उसे बताया गया कि रेत के अवैध परिवहन के कारण ट्रैक्टर की जप्ती की कार्रवाई की जाएगी ।शिकायत के मुताबिक यह सुनते ही साजिद खान ने ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरी रेत मौके पर खाली कर दी और ट्रैक्टर लेकर वहां से जाने का प्रयास करने लगा। वनरक्षक संतोष धुर्वे ने उसे ट्रैक्टर बंद कर नीचे उतरने के लिए कहा। साजिद के ट्रैक्टर से नीचे उतरने के बाद उसने किसी व्यक्ति को फोन किया। कुछ देर बाद एक अन्य व्यक्ति मौके पर पहुंचा ।संतोष धुर्वे का आरोप है कि उक्त व्यक्ति ने बिना कुछ पूछे उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। जातिसूचक गाली-गलौज करने, कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारने और हाथ-मुक्कों से मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद साजिद खान और उसके साथी ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान शहजादा ने धमकी देते हुए कहा कि वे पहले भी दो-तीन बार जेल जा चुके हैं और एक बार और जेल जाना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। दोनों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी ।संतोष धुर्वे ने घटना के दौरान डायल-112 को सूचना दे दी थी।

डायल 112 के पहुंचने के पहले ट्रैक्टर ट्राली और मोबाइल लेकर हुए फरार

डायल 112 के मौके पर पहुंचने से पहले साजिद खान और उसका साथी शहजाद खान ट्रैक्टर लेकर वहां से फरार हो गए ।शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना का वीडियो बना रहे वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व बैहर सामान्य के वाहन चालक राजकुमार ताराम का मोबाइल भी छीन लिया गया ।घटना के बाद संतोष धुर्वे ने विभागीय अधिकारियों को सूचना दी। जानकारी मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। बाद में डायल-112 के माध्यम से संतोष धुर्वे को मलाजखंड थाना लाया गया, जहां उन्होंने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।

वनरक्षक की शिकायत पर इन धाराओं में मामला

मलाजखंड पुलिस ने संतोष कुमार धुर्वे की शिकायत पर साजिद खान पिता अब्दुल सफीक खान और शहजादा खान पिता अब्दुल सफीक खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(बी), 115(2), 132, 3(5), 351(3) तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) और 3(2)(1a) के तहत मामला दर्ज किया है।

शहजाद खान की शिकायत-भाई का ट्रैक्टर रोककर पैसों की मांग की

दूसरी ओर ग्राम भीमजोरी निवासी शहजादा खान ने भी मलाजखंड थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शहजादा खान ड्राइवरी का काम करते है। 6 अक्टूबर की शाम करीब 5 बजे वह अपने घर पर थे। इसी दौरान उसके छोटे भाई साजिद खान ने फोन कर बताया कि बाहीटोला में मंदिर के पास फॉरेस्ट विभाग के संतोष धुर्वे ने उसका ट्रैक्टर रोक लिया है। फोन आने के बाद वह मोटरसाइकिल से बाहीटोला पहुंचा। वहां उसने अपने भाई साजिद खान को वनरक्षक संतोष धुर्वे के पास खड़ा देखा। उसने संतोष धुर्वे से अपने भाई को रोकने का कारण पूछा। शिकायत के मुताबिक वनरक्षक ने आरोप लगाया कि वे लोग नदी से रेत निकालकर बेचने का काम करते हैं। शहजाद का आरोप है कि इसी दौरान संतोष धुर्वे ने उससे पैसों की मांग की। पैसे देने से मना करने पर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। विवाद के दौरान संतोष धुर्वे ने कथित रूप से गाली-गलौज शुरू कर दी। शहजादा खान ने गाली देने से मना किया तो वनरक्षक ने उसके साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी। संतोष धुर्वे ने हाथ में रखे डंडे से उसके सिर के दाहिने हिस्से पर वार किया। जिससे सिर में चोट आई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने दौड़कर बीच-बचाव किया। विवाद शांत होने के बाद संतोष धुर्वे ने दोबारा ट्रैक्टर इधर आने पर जान से खत्म करने की धमकी दी और वहां से चले गए ।इसके बाद शहजाद खान अपने भाई साजिद खान के साथ मलाजखंड थाना पहुंचा और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शहजाद को उपचार एवं मेडिकल परीक्षण के लिए बिरसा अस्पताल भेजा ।मलाजखंड पुलिस ने शहजाद खान की शिकायत पर वनरक्षक संतोष कुमार धुर्वे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 296(बी) और 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया है।

दोनों पक्षों के आरोपों की जांच में जुटी पुलिस

रेत परिवहन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस जांच का विषय बन गया है। एक ओर वनरक्षक ने अवैध रेत परिवहन रोकने के दौरान शासकीय कार्य में बाधा डालने, मारपीट, जातिसूचक गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर शहजादा खान ने वनरक्षक पर पैसे मांगने, गाली-गलौज, मारपीट, डंडे से हमला करने और धमकी देने के आरोप लगाए हैं ।पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। अब पुलिस मेडिकल रिपोर्ट, घटनास्थल की परिस्थितियों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान तथा घटना से जुड़े अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

कान्हा में उपचाराधीन मादा बाघ शावक की मौत

डेढ़ माह से वन्य प्राणी उपचार केंद्र में चल रहा था इलाज

पोस्टमार्टम के बाद जांच के लिए भेजे गए जैविक नमूने

पदमेश न्यूज। बालाघाट। कान्हा टाइगर रिजर्व

के मुक्की परिक्षेत्र स्थित वन्य प्राणी उपचार केंद्र में उपचाराधीन एक मादा बाघ शावक की 6 अक्टूबर को मौत हो गई। बाघ शावक को करीब डेढ़ माह पूर्व वन क्षेत्र में अकेले और अत्यंत कमजोर अवस्था में पाया गया था। इसके बाद वन विभाग द्वारा उसकी जीवन रक्षा और स्वास्थ्य सुधार के लिए लगातार उपचार एवं निगरानी की जा रही थी। चिकित्सकीय प्रयासों के बावजूद शावक की जान नहीं बचाई जा सकी।

26 अगस्त को अकेली और कमजोर मिली थी शावक

जानकारी के अनुसार 26 अगस्त को गश्ती दल ने वन क्षेत्र में एक मादा बाघ शावक को अकेले और अत्यंत कमजोर शारीरिक अवस्था में देखा था। स्थिति को देखते हुए वन विभाग ने उसे रेस्क्यू कर मुक्की स्थित वन्य प्राणी उपचार केंद्र पहुंचाया। 27 अगस्त से वन्य प्राणी चिकित्सा विशेषज्ञों की निगरानी में उसका उपचार शुरू किया गया। करीब डेढ़ माह तक उपचार और चिकित्सकीय देखरेख के बाद भी 6 अक्टूबर को उसकी मृत्यु हो गई।

NTCA की SOP के तहत हुआ पोस्टमार्टम

बाघ शावक की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मानक संचालन प्रक्रिया के तहत 7 अक्टूबर को शव परीक्षण किया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व के वन्य प्राणी चिकित्सा अधिकारी एवं बैहर के पशु चिकित्सक द्वारा संयुक्त रूप से पोस्टमार्टम किया गया ।शव परीक्षण के दौरान आवश्यक शारीरिक अंगों एवं जैविक नमूनों को फोरेंसिक और पैथोलॉजिकल जांच के लिए जबलपुर स्थित प्रयोगशाला भेजा गया है। अधिकारियों के अनुसार, प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही बाघ शावक की मृत्यु के वास्तविक कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

शवदाह की कार्रवाई भी की गई

पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार बाघ शावक के शवदाह की कार्रवाई भी संपन्न की गई। पूरी प्रक्रिया के दौरान वन विभाग द्वारा निर्धारित नियमों एवं NTCA की गाइडलाइन का पालन किया गया ।शव परीक्षण एवं शवदाह की कार्रवाई के दौरान कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक, उपसंचालक (कोर), सहायक संचालक (हालोन), मुक्की परिक्षेत्र अधिकारी, NTCA प्रतिनिधि रंजीत सत्रसुलय, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होगा मौत का कारण

वन विभाग के अनुसार, मादा बाघ शावक को जब पाया गया था, तब उसकी शारीरिक स्थिति बेहद कमजोर थी। फिलहाल उसकी मृत्यु के निश्चित कारण को लेकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है। जबलपुर प्रयोगशाला से प्राप्त होने वाली फोरेंसिक एवं पैथोलॉजिकल जांच रिपोर्ट के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के बाद फिर जुटीं रसोइया बहनें, बोलीं मौखिक आश्वासन नहीं, लिखित समाधान चाहिए

चार महीने से मानदेय अटका, खाद्यान्न में कटौती का आरोप, अब रसोइया बहनों ने आर-पार की लड़ाई का किया ऐलान, स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बंद होने का दावा, विभाग की चुप्पी पर उठे सवाल

पदमेश न्यूज। बालाघाट। जिले में स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने वाली रसोइया बहनों की मानदेय और खाद्यान्न से जुड़ी परेशानी खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। चार महीने से मानदेय नहीं मिलने, खाद्यान्न में कटौती और भोजन पकाने के लिए पर्याप्त एलपीजी गैस उपलब्ध नहीं होने का आरोप लगाते हुए रसोइया संगठन ने अब अपना आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। एक दिन पहले करीब 60 से 70 रसोइया बहनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में नारेबाजी कर विरोध जताया था। नायब तहसीलदार छवि पंत की समझाइश के बाद महिलाएं वहां से लौट गई थीं। उन्हें मौखिक रूप से करीब 10 दिन में समस्या के निराकरण का भरोसा दिया गया था और बैंक खातों की केवाईसी सहित आवश्यक बैंकिंग प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई थी। लेकिन रसोइया संगठन ने साफ कर दिया कि केवल मौखिक आश्वासन के आधार पर आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।

7 अक्टूबर को अर्पित सेवा संस्थान में दोबारा जुटीं रसोइया बहनों ने संगठन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। जिला अध्यक्ष हेमलता पंचेश्वर ने कहा कि उन्हें एक दिन पहले केवल मौखिक आश्वासन दिया गया था, जबकि चार महीने से मानदेय का भुगतान लंबित है। उनका कहना है कि जब तक बकाया मानदेय और खाद्यान्न से जुड़ी समस्याओं का स्पष्ट समाधान नहीं होता, तब तक रसोइया बहनें स्कूलों में वापस जाकर मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्कूलों में बीते कुछ दिनों से ही भोजन बनना बंद कर दिया है और जिले के अधिकांश स्कूलों में बच्चों को मध्यान्ह भोजन नहीं मिल पाने की

स्थिति बनी हुई है। इसके बावजूद संबंधित विभाग के अधिकारी रसोइया बहनों की समस्याओं को गंभीरता से लेते नजर नहीं आ रहे हैं। रसोइया संगठन का कहना है कि समस्या केवल मानदेय तक सीमित नहीं है। खाद्यान्न की उपलब्धता और उसमें कथित कटौती के साथ भोजन बनाने के लिए पर्याप्त गैस तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ऐसे में रसोइया बहनों के सामने एक तरफ घर चलाने का संकट है तो दूसरी ओर स्कूल में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी। हेमलता पंचेश्वर ने कहा कि यदि सरकार और विभाग को लगता है कि इतने कम मानदेय में काम करने वाली रसोइया बहनें महीनों तक बिना भुगतान के काम करती रहेंगी तो यह उनकी मजबूरी का फायदा उठाने जैसा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अब केवल समझाइश से आंदोलन खत्म नहीं होगा और जल्द ही जिले में बड़े प्रदर्शन की रणनीति तैयार की जाएगी। इधर केंद्रीय मध्यान्ह भोजन रसोईया संगठन के पदाधिकारी देवनाथ पंचेश्वर ने भी विभागीय व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि रसोइया पहले ही बेहद कम मानदेय पर काम कर रही हैं और यदि वही मानदेय समय पर नहीं मिलेगा तो उनके लिए काम करना मुश्किल है। संगठन ने जिला पंचायत स्तर पर भी अपनी समस्याएं रखी थीं, लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि एक दिन पहले कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के बाद भी रसोइया बहनों को लिखित आश्वासन नहीं दिया गया, इसलिए अब आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि संगठन जल्द ही जिले के अलग-अलग विधायकों और सांसदों से मुलाकात कर अपनी समस्याएं उनके सामने रखेगा। देवनाथ पंचेश्वर ने कहा कि यदि इसके बाद भी सरकार और प्रशासन ने रसोइया बहनों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया तो जिले में आने वाले शासन-प्रशासन के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और प्रभारी मंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए विरोध का रास्ता अपनाया जाएगा। उनका कहना है कि रसोइया बहनों के सामने ऐसी स्थिति है कि उनके पास घर चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है और स्कूलों में बच्चों के भोजन के लिए भी पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसे में वे आखिर किस तरह अपनी जिम्मेदारी निभाएं। संगठन ने सवाल उठाया कि जब सरकार आमजन की समस्याओं को सुनने के लिए उनके घर तक पहुंचने की बात कर रही है, तो फिर स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाली इन महिलाओं की महीनों पुरानी समस्या पर विभागीय स्तर पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अब रसोइया संगठनों के अलग-अलग स्तर पर आंदोलन में उतरने से स्कूलों में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था पर संकट गहराने की आशंका है। एक संगठन जिला स्तर पर पहले से अनिश्चितकालीन धरना दे रहा है, जबकि दूसरे संगठन भी आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। यदि जल्द ही मानदेय, खाद्यान्न और गैस की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और व्यापक होने के साथ इसका सीधा असर स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मध्यान्ह भोजन पर पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन रसोइया बहनों के भरोसे हजारों बच्चों के लिए रोज भोजन तैयार होता है, जब वही चार महीने से अपने मानदेय के लिए आंदोलन करने को मजबूर हैं, तो उनकी सुध आखिर कौन लेगा?

राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर बालाघाट कांग्रेस में उबाल, पंजवानी बोले मोदी का फूंका पुतला

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जताया विरोध, जमकर की नारेबाजी, पुलिस की मौजूदगी में हुआ पुतला दहन

पदमेश न्यूज। बालाघाट। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को बालाघाट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश खुलकर सड़कों पर दिखाई दिया। जिला कांग्रेस कार्यालय में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला जुलूस के रूप में हनुमान चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी और राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जैसे नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने बताया कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय से रैली निकाली और हनुमान चौक पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान कोतवाली पुलिस और यातायात पुलिस का बल मौके पर मौजूद रहा। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने और पुतला अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन तब तक पुतला लगभग पूरी तरह जल चुका था। इसके बाद नगर पालिका कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर जलते पुतले को बुझाया। पुतला दहन के दौरान कुछ समय के लिए हनुमान चौक क्षेत्र में माहौल गरमा गया। पुलिस बल की मौजूदगी के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को मौके से हटाया और यातायात व्यवस्था सामान्य कराई। इस दौरान श्याम पंजवानी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र और संविधान को

कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से लगातार मिलने का समय मांग रहे थे, लेकिन उन्हें मिलने तक का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसी व्यक्तिगत मुद्दे को लेकर नहीं, बल्कि करोड़ों मतदाताओं के अधिकार और उनके वोट की सुरक्षा का सवाल लेकर चुनाव आयोग के सामने खड़े हैं। पंजवानी ने कहा कि विपक्ष को संविधान ने जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए सवाल पूछने का अधिकार दिया है, लेकिन सवालों का जवाब देने के बजाय राहुल गांधी की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह दिल्ली को छावनी में तब्दील कर राहुल गांधी की गिरफ्तारी की गई, वह लोकतंत्र के लिए गंभीर और चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाने और फॉर्म-6 में किए गए बदलाव को लेकर भी सवाल उठाए। पंजवानी ने कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची में बदलाव और पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने से जुड़े सवालों का जवाब चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को देना चाहिए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और मतदाता के अधिकारों की रक्षा के लिए है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जनता के वोट के अधिकार के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी से कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। सरकार जितना विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास करेगी, कांग्रेस उतनी ही मजबूती से अपनी आवाज बुलंद करेगी। प्रदर्शन में अनूप सिंह बैस, भीम फुलसुंगे, श्याम पंजवानी, वाहीद अल्ला रखा, जीतू बर्वे, शिवम शर्मा, शिवम विश्वकर्मा, शानू राय, रामसिंह भाटिया, डॉ. अमर बिसेन, एडवोकेट निखिल गौतम, डॉ. मुकेश वरकड़े, डॉ. दुर्गा वरकड़े, श्रीकृष्ण डिंगरू, नीटू कौशल, मधु चौकसे, पूजा, प्रतीक जैन, सीमा सिंह, पंकज बौद्ध, ऋषभ सहारे, पुष्पलता कुड़वार, शीला नगपुरे, संतोष बाहैश्वर, रिजवान खान, साजिद खान, राजू बॉस सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में शिक्षक-अभिभावक सम्मेलन आयोजित

पदमेश न्यूज। बालाघाट। शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय, बालाघाट में 7 अक्टूबर 2026 को प्राचार्य डॉ. निधि ठाकुर की अध्यक्षता एवं आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के तत्वावधान में शिक्षक-अभिभावक समिति द्वारा शिक्षक-अभिभावक

सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य छात्राओं की शैक्षणिक प्रगति, उपस्थिति, अनुशासन एवं सर्वांगीण विकास को लेकर शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संवाद स्थापित करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना एवं दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। समिति संयोजक डॉ. प्रियंक चौबे ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। विभिन्न संकायों के विभागाध्यक्षों एवं प्राध्यापकों ने महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, छात्रवृत्ति, शोध, युवा उत्सव, नैक मूल्यांकन, भारतीय ज्ञान परंपरा, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी अभिभावकों को दी। इस अवसर पर अभिभावक मोहरलाल पारधी, गणेश पारधी एवं मानक सिंह लिल्हारे ने अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किए। प्राचार्य डॉ. निधि ठाकुर ने अभिभावकों का स्वागत करते हुए छात्राओं के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं एवं भविष्य के अवसरों की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन सुश्री प्रीति उइके ने किया। आयोजन में समिति सदस्य जीवन मसराम एवं श्रीमती दीप्ति गढ़पाले सहित महाविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ का सराहनीय सहयोग रहा।

आस-पास की खबरें

उत्कृष्ट विद्यालय में योग एवं ध्यान योगाभ्यास सेवा संकल्प अभियान के तहत योग सत्र का हुआ आयोजन

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। सेवा संकल्प अभियान गत 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 के तहत विभिन्न विकासखंड में आयोजित किया जा रहा है। जिला खेल अधिकारी राहुल बारेसा ने कहा कि युवाओं को योग, खेलों

से जोड़ने और प्रोत्साहित करने के लिए फिट इंडिया खेल सत्र के साथ-साथ योग गतिविधि में योगाभ्यास योग एवं ध्यान सत्रसेवा संकल्प अभियान के तहत खिलाड़ी युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली और मानसिक एकाग्रता के लिए योग सत्र आयोजित कर योगाभ्यास करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में लालबर्रा विकासखण्ड स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा में गत दिवस सेवा संकल्प अभियान और योग सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं और खिलाड़ियों में शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वहीं विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों को योगासन, प्राणायाम और ध्यान का प्रशिक्षण दिया गया। जिससे नियमित योगाभ्यास से शारीरिक सक्रियता, एकाग्रता और सकारात्मक सोच विकसित होती है। सभी विद्यालय स्टाफ, छात्र-छात्राएं, युवा खिलाड़ियों ने इस योग सत्र में बढ़ चढ़कर योगाभ्यास किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत योग एवं ध्यान के माध्यम से लोगों को स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य सेवा और जनभागीदारी के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा लोगों को अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करने के लिए प्रेरित करना है। योग शरीर को सक्रिय और स्वस्थ रखने के साथ मानसिक शांति, एकाग्रता और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने में सहायक है। आगे कहा कि नियमित योगाभ्यास और ध्यान से व्यक्ति अपनी दिनचर्या को अधिक अनुशासित और संतुलित बना सकता है। इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा के प्राचार्य सनत दुबे, आयुष विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारी, योग प्रभारी, ब्लॉक युवा समन्वयक लालबर्रा लव पटेल नगपुरे, ब्रजेश पंचेश्वर सहित विद्यार्थी उपस्थित रहे।

प्रशासनिक उपेक्षा की भेंट चढ़ी माइनर नहर, टेल एरिया के किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच रहा पानी

खारी से बुट्टा ह. माइनर नहर जर्जर और झाड़ियों से पटी, बजट न होने का बहाना बना रहा विभाग

रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। लालबर्रा।

वैनगंगा मुख्य बड़ी नहर से जुड़ी खारी-बुट्टा हजारी माइनर नहर के जर्जर होने और उसमें उगी घनी झाड़ियों-कचरे के कारण क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शासन द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई यह नहर देखरेख के अभाव में औचित्यहीन साबित हो रही है। पानी न मिलने से सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल प्रभावित हो रही है, जिससे क्षेत्र के किसानों में जल संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर गहरा रोष व्याप्त है। जबकि लंबे समय से क्षेत्रीय किसानों के द्वारा जल संसाधन विभाग से जगह-जगह से टूट-फुट चुकी माइनर नहर का मरम्मत या फिर सीमेन्टीकरण करने एवं झाड़ियों की सफाई करवाने की मांग कर रहे है। लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा इस समस्या की ओर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। इस तरह से प्रशासनिक उपेक्षा की भेंट चढ़ गई है खारी से बुट्टा ह. माइनर नहर। अगर प्रशासन के द्वारा बरसात के पूर्व ही नहर का मरम्मत कार्य एवं घनी झाडियों की साफ-सफाई करवा दी जाती तो उक्त समस्या उत्पन्न नही होती। लेकिन वर्तमान में नहर जर्जर होने के कारण बुट्टा ह. सहित अन्य ग्रामों के टेल क्षेत्र तक पानी नही पहुंचने से उनकी फसल प्रभावित हो रही है, जिससे किसान परेशान है।

सिंचित क्षेत्र के तहत टैक्स देने के बाद भी सैकड़ों एकड़ में खड़ी धान की फसल पानी के अभाव में हो रही प्रभावित, किसानों में रोष व्याप्त

क्षतिग्रस्त नहर और कचरा बनी सबसे बड़ी बाधा

आपकों बता दे कि वैनगंगा बड़ी नहर के माइनर खारी से बुट्टा हजारी तक कच्ची नहर बनी हुई है जो जगह-जगह से टूट-फुट चुकी हैं। साथ ही झाड़िया भी उग आई है जिस कारण से बुट्टा ह. तक नहर का पानी नही पहुंच पा रहा है। जबकि लंबे समय से इस क्षेत्र के किसानों के द्वारा जल संसाधन विभाग से माइनर नहर का सीमेन्टीकरण करने की मांग कर रहे है। लेकिन कोई ध्यान नही दिया जा रहा है, जिस कारण से वर्तमान में नहर जर्जर हो चुकी है और अत्यधिक घास एवं कचरा जमा होने के कारण माइनर नहर में पानी छोड़ने के बाद टेल एरिया में पानी नही पहुंचने से फसल प्रभावित हो रही है। अगर सिंचाई के लिए पानी नही मिलेगा तो उनकी फसल प्रभावित हो सकती है एवं फसल उत्पादन कम होने पर उन्हे आर्थिक परेशानियों से जुझना पड़ेगा। वहीं किसानों का कहना है कि खारी से बुट्टा हजारी तक बनी यह कच्ची माइनर नहर जगह-जगह से क्षतिग्रस्त एवं टूट-फूट चुकी है। नहर में अत्यधिक घास-फूस उग आने से पानी अवरूध्द हो रहा है। परिणामस्वरूप विभाग द्वारा मुख्य नहर से पानी छोड़े जाने के बावजूद टेल एरिया (अंतिम छोर) में स्थित बुट्टा हजारी सहित अन्य गांवों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वर्तमान में खेत में खड़ी हल्की प्रजाति की धान पककर तैयार होने की स्थिति में है, जबकि भारी प्रजाति की धान गर्भ (गाभा) अवस्था में है। इस चरण में फसलों के लिए पानी बेहद जरूरी है। यदि समय पर सिंचाई नहीं हुई तो फसल उत्पादन में भारी गिरावट आयेगी, जिससे किसानों को आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ेगा।

टैक्स देने के बावजूद विभाग की अनदेखी

किसानों ने बताया कि वे हर वर्ष अनुबंध (एग्रीमेंट) के आधार पर नियमित रूप से सिंचाई कर का भुगतान करते हैं। इसके बावजूद उन्हें पानी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। जबकि किसानों के द्वारा लंबे समय से इस माइनर नहर का सीमेंटीकरण कराने तथा तत्काल मरम्मत व साफ-सफाई की मांग कर रहे हैं। किन्तु जल संसाधन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हर बार बजट का अभाव बताकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। क्षेत्रीय किसानों ने जल संसाधन विभाग एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल नहर की मरम्मत करवाई जाये और झाड़ियों व कचरे की सफाई करवाकर टेल एरिया तक पानी पहुंचाये ताकि किसानों की गाढ़ी कमाई से लगाई गई फसल को बर्बाद होने से बचाया जा सके।

पानी नही पहुंचने से फसल हो रही खराब - बाबूलाल

किसान बाबूलाल टेंभरे ने बताया कि खेतों में धान की फसल लगी हुई है लेकिन खारी से बुट्टा ह. माइनर नहर क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण टेल एरिया तक नहर का पानी नही पहुंच पा रहा है, जिससे फसल प्रभावित हो रही है। जबकि वर्तमान में हल्की प्रजाति की धान की फसल पकने के कगार पर है एवं भारी प्रजाति की धान गर्भ में है। जिनमें पानी की अति आवश्यक है, अगर पानी नही मिलेगा तो काफी नुकसान होने की आशंका है। श्री टेंभरे ने बताया कि नहर की समस्या से कई बार जल संसाधन विभाग को अवगत करवा दिया गया है लेकिन कोई ध्यान नही दिया जा रहा है जिससे किसानों में रोष व्याप्त है।

नहर का मरम्मत एवं घनी झाड़ियों की सफाई करवाये प्रशासन - चंद्रकिशोर

बुट्टा ह. सरपंच चंद्रकिशोर बघेल ने बताया कि वैनगंगा मुख्य नहर की खारी से बुट्टा ह. माइनर नहर के पानी से सैकड़ों एकड़ खेती की सिंचाई होती है, लेकिन नहर जर्जर हो जाने के कारण बुट्टा ह. तक पानी नही पहुंच पा रहा है, ऐसी स्थिति में किसान बेहद परेशान है, जबकि इस समस्या से विभाग को अवगत करवा दिये है। लेकिन वे हर समय बजट का बहाना बनाते है, जबकि उनकी जवाबदारी है कि नहर का मरम्मत कार्य करवाकर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाये क्योंकि किसान एग्रीमेंट के आधार पर टैक्स देते है। श्री बघेल ने बताया कि सिंचाई के लिए पानी नही मिलने पर फसल को काफी नुकसान हो सकता है इसलिए जल संसाधन विभाग से मांग है कि खारी से बुट्टा ह. माइनर नहर का मरम्मत एवं घनी झाड़ियों की सफाई करवाये ताकि नहर का पानी टेल क्षेत्र तक पहुंच सके।

गोला फेंक, तार गोला फेंक में ऋषभ नामदेव का हुआ चयन

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। 70 वीं राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता में एथलेटिक्स में गोला

फेंक व तार गोला फेंक दोनों स्पर्धा में अन्दर 19 वर्ष बालक वर्ग में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा का बालक ऋषभ/गोपाल नामदेव का संभाग स्तरीय गोला फेंक, तार गोला फेंक प्रतियोगिता के लिए चयनित होने पर छात्र-छात्राओं एवं शिक्षक-शिक्षिकाओं में हर्ष की लहर व्याप्त है। चर्चा में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा के प्रभारी प्राचार्य सनत दुबे ने बताया कि कक्षा 12 वीं कामर्स का छात्र ऋषभ/गोपाल नामदेव को संभाग स्तरीय गोला फेंक, तार गोला फेंक में चयन हुआ है। जो कि शिवपुरी में 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक होने वाली प्रतियोगिता में संभागीय दल जबलपुर का प्रतिनिधित्व लालबर्रा बालाघाट जिले से करेगा। श्री दुबे ने बताया कि छात्र ऋषभ नामदेव का शिवपुरी के लिए रवाना कर दिया गया है, पीटीआई छत्तरसिंह ठाकरे, ब्लाक समन्वयक खेल एवं युवा कल्याण विभाग लालबर्रा लव पटेल के मार्गदर्शन में छात्र ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। छात्र के उज्जवल भविष्य की कामना स्कूल के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने की है।

सेवानिवृत्ति पर प्राचार्य जी.आर. अंगुरे को दी गई विदाई

बकोड़ा पीएम श्री शास. हाई स्कूल में विदाई समारोह का हुआ आयोजन

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। नगर मुख्यालय से लगभग 4 किमी. दूर ग्राम पंचायत बकोड़ा स्थित पीएम श्री शासकीय हाईस्कूल में गत दिवस विदाई समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम सेवानिवृत्त प्राचार्य जीआर अंगुरे के मुख्य आतिथ्य, सरपंच प्रतिनिधि श्रीराम नागेश्वर की अध्यक्षता एवं श्रीमति निर्मला अंगुरे, आर.के. मेश्राम सेवानिवृत्त प्राचार्य, एम.आर.पटले सेवानिवृत्त प्रधान पाठक, नारायण प्रसाद सोलंकी सेवानिवृत्त शिक्षक, आनंद चुरहे सेवानिवृत्त शिक्षक, रमेश निकोसे शाला प्रबंधन समिति उपाध्यक्ष के विशेष आतिथ्य में प्रारंभ हुआ। जिसमें सर्वप्रथम उपस्थितजनों ने माँ सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात शिक्षक-शिक्षिकाओं ने सेवानिवृत्त प्राचार्य जीआर अंगुरे का तिलकवंदन कर शाल, श्रीफल, उपहार भेंट की एवं उनके उ%जवल भविष्य की कामना कर भावभीनी विदाई दी। वहीं उपस्थित अतिथियों ने सेवानिवृत्त प्राचार्य जीआर अंगुरे के सेवाकाल में किये गये कार्यो की सराहना करते हुए कहा कि उनके द्वारा एक आदर्श शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हुए शासन के सभी कार्यो को बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया

गया है। साथ ही छात्रों के जीवन को सफल बनाने के लिए अपना शत-प्रतिशत योगदान प्रदान करने के साथ -साथ शाला विकास एव अनुशासन बनाये रखने में अपना योगदान प्रदान किया है। हम सभी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते है। वहीं सेवानिवृत्त प्राचार्य जीआर अंगुरे ने कहा कि 62 वर्ष की आयु तक शिक्षा विभाग में नौकरी के दौरान बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और मेरे द्वारा ब%चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के साथ ही उन्हे उचित मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया है। इसलिए सभी शिक्षक बच्चों को अ%छी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही शासन की योजनाओं का भी लाभ दिलवाये। इस अवसर पर श्रीराम तुरकर बी.आर.सी लालबर्रा, सनतकुमार दुबे प्रभारी प्राचार्य शास. उत्कृष्ट उ%चतर माध्यमिक विद्यालय लालबर्रा, श्रीमती लता अंगुरे, श्रीमति उमाबाई भोयर, श्रीमति भारती डायरे, श्रीमति स्वाति चौधरी, श्रीमती ज्योति अंगुरे, श्रीपाल अंगुरे, सौरभ चौधरी, झनकराम लानगें, गगन अंगुरे, राकेश भोयर, सुश्री साक्षी अंगुरे, श्री मारवाडे, श्रीमति वंदना टेकाम शिक्षिका शा. उमावि. कनकी, के.बी.बिसेन ,श्रीमति गीतेश्वरी खैरवार, लुकेश गौतम, एन.के.चौकसे, श्याम भलावी, घनश्याम भलावी, प्रणय गजभिये, हुकुमचंद गजभिये, एल.सी.ठाकरे, अफरोज खान, टी.एस. बिसेन, धनंजय सोनी, श्रीमति लेखन पटले, आर.पी.पटले, श्याम सोलंकी, अरूण बघेल, अजय कटरे, श्रीमति लता शिव, भवित कटरे, श्रीमति विनीता वैद्य, सत्यम कटरे, नरेन्द्र हाथी भृत्य एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

बहियाटिकुर के ग्रामीणों ने सीईओं को सौंपा ज्ञापन

ग्रामीणों ने पंचायत क्षेत्र में हुए कार्यों का निष्पक्ष जांच न होने पंचायत भवन में तालाबंदी की दी चेतावनी

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। नगर मुख्यालय से लगभग 8 किमी. दूर ग्राम पंचायत बहियाटिकुर में सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक द्वारा निर्माण कार्यों एवं पंचायत के समस्त वित्तीय भुगतानों में भारी अनियमितताओं की शिकायते ग्रामीणजनों ने जनसुनवाई, जनपद सीईओं, जिला कलेक्टर से पूर्व में की है। लेकिन अब तक कोई निष्पक्ष जांच एवं ठोस कार्यवाही नही होने से ग्रामीणजनों में रोष व्याप्त है। लगातार शिकायतों की अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 7 दिवस के भीतर शिकायत की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि दिये गये समय-सीमा के भीतर संबंधित अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं की जाती है, तो समस्त ग्रामवासी मिलकर ग्राम पंचायत भवन में तालाबंदी करेंगे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बहियाटिकुर पंचायत के निर्माण कार्यों एवं वित्तीय अनियमितता के संबंध में जनपद पंचायत लालबर्रा, जिला पंचायत बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकार, कलेक्टर महोदय बालाघाट को जनसुनवाई व आवेदनों के माध्यम से अनेकों बार सूचित किया है। इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है, जिससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश और निराशा है। जबकि इन कार्यों में लाखों रूपयों की हेराफेरी की गई है और धरातल पर काम नही हुआ है, जब पंचायत के जिम्मेदारों से जानकारी मांगी जाती है तो वे कोई जवाब नही दे रहे है। बुधवार को जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचकर सीईओं के नाम ज्ञापन सौंपकर शिकायत की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। यदि प्रशासन द्वारा बहियाटिकुर पंचायत में हुए निर्माण कार्य एवं वित्तीय भुगतानों में जो अनियमितता बरती गई है उसकी जल्द जांच शुरू नहीं की गई तो पंचायत भवन में तालाबंदी की जायेगी। इस तालाबंदी आंदोलन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी परिस्थिति और इस पूरी कार्यप्रणाली की जिम्मेदारी जांचकर्ता समूह के कर्मचारियों एवं शासन-प्रशासन की होगी। वहीं जनपद के अधिकारियों का कहना है कि शिकायत की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही की जायेगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

मांगे पूरी नही होने पर पंचायत में करेगें तालाबंदी

आदित्य चौधरी, शैलेष खोब्रागढ़े, बालकृष्ण उइके ने संयुक्त रूप से बताया कि बहियाटिकुर पंचायत के निर्माण कार्यों में सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक के द्वारा भारी अनियमितता बरती गई है और फर्जी बिल लगाकर राशि का आहरण कर लिया गया। गत दिवस चितरटोला में हो रहे निर्माण कार्य को देखने गये तो वहां घटिया गुणवत्ता की सामग्री पाई गई। वहीं काम कर रहे मिस्त्रियों ने भी इस बात की पुष्टि की है और उनके पास इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग साक्ष्य के रूप में मौजूद है। जब ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में हो रही धांधली पर सवाल उठाये और काम रोकने की कोशिश की गई तो सरपंच, सचिव के द्वारा झूठे मामले में एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी गई। साथ ही अन्य कार्यों में भी भारी धांधली गई गई है। आगे बताया कि निर्माण कार्यों एवं वित्तीय भुगतानों में हुई भारी अनियमितता की शिकायत जनपद सीईओं, जिला पंचायत सीईओं एवं कलेक्टर महोदय से की गई है। लेकिन निष्पक्ष जांच नही हो पा रही है। इसलिए बुधवार को लालबर्रा जनपद पंचायत पहुंचकर सीईओं को ज्ञापन सौंपकर बहियाटिकुर पंचायत में हुए निर्माण कार्यों एवं वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। उक्त मांगे 7 दिवस के अंदर पुरी नही होने पर ग्रामीणजन पंचायत भवन में तालाबंदी कर देगें।

सरंडी अंडरब्रिज में जलभराव और कीचड़ से ग्रामीण परेशान

पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से बढ़ी परेशानी, रेलवे ट्रैक पार कर आवागमन करने को मजबूर विद्यार्थीगण

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी कटंगी मार्ग से ग्राम सरंडी की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित रेलवे अंडरब्रिज में जलभराव और कीचड़ की समस्या के कारण ग्रामीणों एवं राहगीरों को आवागमन करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंडरब्रिज के भीतर पानी जमा होने और लगातार सीपेज के चलते पैदल चलने वाले ग्रामीणों, साइकिल सवारों तथा विद्यार्थियों के लिए रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया है। स्थिति ऐसी है कि कई लोगों को अंडरब्रिज से निकलने के बजाय रेलवे ट्रैक पार कर दूसरी ओर पहुंचना पड़ रहा है जिससे दुर्घटना का जोखिम बना हुआ है।

दीवारों से सीपेज का पानी भी हो रहा जमा

जानकारी के अनुसार वारासिवनी कटंगी मुख्य मार्ग से ग्राम सरंडी के लिए मार्ग निकलता है। इसी मार्ग पर रेलवे ट्रैक के निर्माण के दौरान रेलवे विभाग के द्वारा अंडरब्रिज का निर्माण किया गया था। अंडरब्रिज के निर्माण के बाद से ही यहां जलभराव की समस्या बनी हुई है। बारिश के दिनों में स्थिति और गंभीर हो जाती है तथा अंडरब्रिज के भीतर बड़ी मात्रा में पानी एवं कीचड़ जमा हो जाता है। वर्तमान में भी अंडरब्रिज की दीवारों से सीपेज के माध्यम से पानी लगातार अंदर पहुंचकर एकत्रित हो रहा है। इसके अलावा बारिश का पानी भी जमा होने से रास्ते पर कीचड़ की स्थिति बनी हुई है। वाहनों के आवागमन के दौरान पानी और कीचड़ के छींटे पैदल राहगीरों तथा साइकिल से आने जाने वाले लोगों के कपड़ों पर पड़ते हैं जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। यह मार्ग करीब आधा दर्जन गांवों को जोड़ता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण, विद्यार्थी और अन्य राहगीर इस मार्ग से आवागमन करते हैं। अंडरब्रिज में पानी और कीचड़ जमा होने के कारण मोटरसाइकिल एवं अन्य छोटे.बड़े वाहन तो किसी तरह वहां से निकल जाते हैं लेकिन पैदल चलने वाले और साइकिल सवारों के लिए स्थिति बेहद कठिन बनी हुई है। विशेषकर विद्यार्थियों को स्कूल एवं अन्य कार्यों के लिए आवागमन करते समय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंडरब्रिज से निकलना मुश्किल होने पर कुछ ग्रामीण और विद्यार्थी रेलवे ट्रैक पार कर ऊपर से आवागमन करने को मजबूर हैं। ऐसे में रेलवे ट्रैक पर आवागमन करना उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। बताया गया कि अंडरब्रिज में जमा पानी की निकासी के लिए संबंधित विभाग के द्वारा मोटर भी लगाई जाती है लेकिन इसके बावजूद पर्याप्त मात्रा में पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है। पानी की निकासी की व्यवस्था प्रभावी नहीं होने से समस्या बार बार उत्पन्न हो रही है। वहीं पानी के साथ जमा होने वाला कीचड़ भी राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। लगातार बनी हुई समस्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। अंडरब्रिज का उपयोग आसपास के कई गांवों के लोग रोजाना करते हैं ऐसे में यहां जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जाना आवश्यक है। केवल अस्थायी रूप से मोटर लगाकर पानी निकालने के बजाय ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे पानी अंडरब्रिज में जमा ही ना हो। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन एवं संबंधित विभाग से अंडरब्रिज का निरीक्षण कर पानी निकासी की बेहतर और स्थायी व्यवस्था बनाने कीचड़ की सफाई कराने तथा पैदल राहगीरों एवं विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाने की मांग की है।

सरंडी के अंडर ब्रिज में स्थाई रूप से सुधार कार्य होना चाहिए-प्रभुदयाल गौतम

ग्रामीण प्रभुदयाल गौतम ने बताया कि वारासिवनी से सरंडी सड़क यहां आती है उस पर यह अंडर ब्रिज बनाया गया है। जिसमें आए दिन परेशानी बनी रहती है पानी होने के कारण गाड़ियां खराब होती है स्कूल के बच्चे आते जाते हैं उन्हें परेशानी है कीचड़ और काई होती है जिसमें लोग फिसल जाते हैं। कई बार जानवर सामने आ जाते हैं गाड़ियों के बहुत परेशानी है जब से ब्रिज बना है तब से यह समस्या का घर हो गया है। १० गांव के लोग यहां से आना जाना करते हैं वह सभी परेशान है पानी निकासी के लिए यहां पर मोटर पंप लगा दिए हैं परंतु वह पर्याप्त पानी नहीं निकल पा रहा है। जिस कारण पानी और कीचड़ यहां पर बना हुआ है इसका स्थाई रूप से सुधार कार्य होना चाहिए।

सरंडी के अंडर ब्रिज में पानी भरने से विद्यार्थीयों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है-मनोज गौतम

मनोज गौतम ने बताया की मैं कोसरीटोला रहता हूं यह सरंडी ग्राम का रास्ता है जहां से ग्रामीण राहगीर और बच्चे सभी आते जाते हैं। बरसात में इस अंडर ब्रिज में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है कई बार तो बहुत ज्यादा पानी भर जाता है अक्टूबर ,नवंबर तक इसके अंदर पानी और कीचड़ रहता है जहां से आना जाना बहुत मुश्किल होता है। खतरा हमेशा बना रहता है जब तक कीचड़ सुख ना जाये पैदल और साइकिल वालों को ऊपर रेलवे ट्रैक पार कर जाना पड़ता है। पूरे दिन में १२ बार ट्रेन आती जाती है जान का खतरा हमेशा बना रहता है अब इसमें रेलवे क्या सुधार कर सकता है वह देखने लायक है। फिर भी जल्द सुधार होने चाहिए क्योंकि यह समस्या पुरानी है किसी हादसे का रास्ता विभाग ना देखें।

आंधी तूफान से प्रभावित कालीमाटी टेकाड़ी में विधायक पारंधी ने फसल नुकसान का किया जायजा

अधिकारियों को जल्द सर्वे कर किसानों को नियमानुसार राहत दिलाने के दिए निर्देश

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। ग्राम कालीमाटी टेकाड़ी में बीते दिनों आए तेज आंधी.तूफान एवं ओलावृष्टि से किसानों की धान की फसल को हुए नुकसान का जायजा लेने विधायक ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने खेतों में पहुंचकर क्षतिग्रस्त फसलों का निरीक्षण किया तथा किसानों से चर्चा कर नुकसान की स्थिति की जानकारी ली। किसानों ने बताया कि कटाई के करीब पहुंच चुकी धान की खड़ी फसल तेज हवाओं और ओलावृष्टि के कारण खेतों में गिर गई है जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ है। इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारी तहसीलदार एवं पटवारी भी मौजूद रहे। विधायक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से फसल नुकसान की स्थिति की जानकारी लेते हुए प्रभावित किसानों एवं खेतों का जल्द से जल्द सर्वे कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान वास्तविक क्षति का आकलन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र किसानों को नियमानुसार राहत एवं क्षतिपूर्ति का लाभ मिल सके। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में आंधी तूफान से विद्युत व्यवस्था एवं अन्य नुकसान को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक पारधी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की स्थिति में किसानों को राहत दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत और उनकी फसल को हुए नुकसान को गंभीरता से लिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय कर सर्वे एवं राहत संबंधी कार्रवाई को जल्द पूरा कराने के प्रयास किए जाएंगे। संकट की इस घड़ी में किसानों के साथ खड़े हैं और उनके हित में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

पदोन्नति नियमों में संशोधन की मांग को लेकर वन कर्मचारी संघ ने विधायक विवेक पटेल को सौंपा ज्ञापन

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। मध्य प्रदेश वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ ने वन विभाग के मैदानी कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी समस्याओं और मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम २०२५ में संशोधन की मांग को लेकर वारासिवनी विधायक विवेक पटेल को ज्ञापन सौंपा है। संघ के सदस्यों ने बताया कि मैदानी कर्मचारी कठिन और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में बीट निरीक्षण,वन एवं वन्यप्राणी अपराधों का पंजीयन जांच तथा वन सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ग्रामीणों के द्वारा अज्ञानतावश वन या वन्यप्राणियों को नुकसान पहुंचाने पर नियमानुसार अपराध दर्ज कर कार्रवाई भी इन्हीं कर्मचारियों के द्वारा की जाती है। कर्तव्यों के निर्वहन के बावजूद कई मामलों में कर्मचारियों के विरुद्ध लघु शास्ति, प्रतिकूल प्रविष्टि स्पष्टीकरण या वसूली जैसी कार्रवाई हो जाती है। जिससे उनकी पदोन्नति प्रभावित होती है। वरिष्ठता और पात्रता होने के बावजूद वे पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं,२०२५ के नियम १० में संशोधन कर दंड समाप्त होने के बाद पदोन्नति पर पड़ने वाले प्रभाव की अवधि स्पष्ट और न्यायसंगत अर्थात एक वर्ष की प्रभावशीलता समाप्त करने की मांग की है। ताकि छोटी विभागीय कार्रवाई के कारण कर्मचारियों का भविष्य लंबे समय तक प्रभावित ना हो। इसके अलावा तृतीय श्रेणी के मैदानी कर्मचारियों के गोपनीय कार्य निष्पादन प्रतिवेदन के मूल्यांकन में संशोधन की मांग भी की गई। वर्तमान व्यवस्था में उनके कठिन और जोखिमपूर्ण कार्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं हो पाता,जिसका असर पदोन्नति पर पड़ता है। संघ ने अन्य जिलों से प्रशासनिक या पारिवारिक कारणों से स्थानांतरित होकर आने वाले कर्मचारियों को सेवा वरिष्ठता और पात्रता के आधार पर पदोन्नति का लाभ देने के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाने की मांग रखी। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला अध्यक्ष श्रीराम घरते,संभागीय अध्यक्ष रोशन पड़वार,तहसील अध्यक्ष जगदीश बागड़े, संगठन सचिव सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। विधायक विवेक पटेल ने वन कर्मचारियों की समस्यायों को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव,सामान्य प्रशासन विभाग एवं वन बल प्रमुख भोपाल के समक्ष रखकर समाधान कराया जाने आश्वासन दिया गया।

जन सेवा ही प्रभु सेवा को बनाया यात्रा का मूलमंत्र -प्रदीप जायसवाल

सेवा ज्योति यात्रा का वारासिवनी नगर में हुआ भव्य स्वागत

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन एवं जनसेवा के २५ वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित सेवा ज्योति यात्रा एवं विकसित भारत संकल्प सभा बुधवार को पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल के नेतृत्व में वारासिवनी नगर पहुंची। यात्रा के नगर आगमन पर विभिन्न स्थानों पर लोगों ने पुष्पवर्षा कर गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं नगर के नगर पालिका परिषद चौक पर गणमान्य नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों ने कलश पूजन कर यात्रा का स्वागत किया और भारत माता व राष्ट्र निर्माण के जयघोष से वातावरण गुंजायमान हो उठा। यह सेवा ज्योति यात्रा का शुभारंभ जिला मुख्यालय से हुआ इसके बाद यात्रा रेंगाटोला, आलेझरी, कायदी, वारा होते हुए वारासिवनी नगर पहुंची। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय नागरिकों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। जनपद पंचायत परिसर में भी यात्रा का स्वागत किया गया। इसके पश्चात यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नपा परिषद चौक पहुंची जहां पुष्पवर्षा के साथ यात्रा का अभिनंदन किया गया। इस दौरान कलश का विधिवत पूजन कर उपस्थित लोगों ने उत्साह पूर्वक जयघोष किया। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण और सुशासन के कार्यों में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना ही सेवा ज्योति यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है। जन सेवा ही प्रभु सेवा के मूलमंत्र के साथ नागरिकों को सामाजिक सरोकारों और राष्ट्र निर्माण के कार्यों से जोड़ते हुए सेवा समर्पण और सक्रिय भागीदारी को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश को विकसित एवं आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प में समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वर्ष २०४७ तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर यह यात्रा जन जन तक पहुंचने का कार्य कर रही है। पूर्व मंत्री जायसवाल ने बताया कि सेवा ज्योति यात्रा ८ अक्टूबर को खैरलांजी क्षेत्र में पूरे दल बल के साथ पहुंचेगी। यात्रा प्रभारी नरेंद्र शुक्ला, संतोष आड़े, मिलिंद नगपुरे एवं चित्रेश बिसेन के नेतृत्व में यात्रा खैरलांजी सहित आसपास के विभिन्न ग्रामों में पहुंचेगी। यात्रा के दौरान खैरलांजी, खैरी, सावरी, चूटिया, अतरी, मोहाड़ी, आरंभा, सिवनघाट, लावनी, भेंडारा, डोंगरमाली सहित अन्य ग्रामों में जनसंपर्क किया जाएगा। इस दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने के साथ पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जागरूक किया जाएगा। सेवा ज्योति यात्रा का उद्देश्य केवल जनसंपर्क तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक शासन की योजनाओं और विकास की गतिविधियों का लाभ पहुंचाना भी है। यात्रा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें उनका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वारासिवनी नगर में यात्रा के भव्य स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों में खासा उत्साह देखने को मिला। पुष्पवर्षा, कलश पूजन और जयघोष के बीच यात्रा का नगर में आत्मीय अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सरिता मनोज दांदरे, भाजपा मंडल अध्यक्ष मिलिंद नगपुरे, मंडल अध्यक्ष संदीप मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सरपंच संघ की आवश्यक बैठक आज

पद्मेश न्यूज। खैरलांजी। खैरलांजी जनपद के अंतर्गत सभी सरपंच गणों की आवश्यक बैठक गुरुवार को कार्यालय ग्राम पंचायत भवन खैरलांजी में दोपहर १२ बजे रखी गई है। उक्त बैठक में मुख्य अतिथि कटंगी विधायक गौरव सिंह पारधी, प्रमुख अतिथि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गायत्री कुमार सारथी,अध्यक्षता सरपंच संघ अध्यक्ष पुष्पेंद्र देशमुख,विशेष अतिथि पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष रामकुमार नगपुरे, रमेश नगपूरे ,तेजलाल चौधरी,पुष्पेंद्र देशमुख ,कुंज बिहारी बिसेन की उपस्थिति में संपन्न होगी। जिसमें सरपंचों के विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। जिसके अंतर्गत सरपंचों का मानदेय विषय क्रमांक,पूर्व सरपंचों का मानदेय,मनरेगा का पेमेंट,जी राम जी के अंतर्गत नवीन कार्यों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा की जाएगी।

संदीपनि स्कूल के कक्षा १२ वीं के छात्र से हुई मारपीट

बेल्ट से हमला और जातिसूचक गाली देने का मामला दर्ज

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। सांदीपनी स्कूल के सामने स्थित किराना दुकान के पीछे बुधवार की दोपहर करीब १२ बजे कक्षा १२ वीं के एक छात्र के साथ मारपीट गाली गलौज,धमकी और जातिसूचक अपमान किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत पर वारासिवनी पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता अनीता पति स्व दिनेश भलावे ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा कक्षा १२वीं में सांदीपनी स्कूल वारासिवनी में अध्ययनरत है। छात्र स्कूल के सामने किराना दुकान के पीछे खड़ा था तभी उसके साथ पढ़ने वाला एक बालक वहां पहुंचा। जिससे उसका पूर्व में हुए विवाद को लेकर बहस शुरू की और अश्लील गाली गलौज करने लगा। विवाद बढ़ने पर सहपाठी बालक के दो साथी बालक भी वहां पहुंचे। जिस पर सहपाठी बेल्ट निकालकर छात्र के साथ मारपीट की जबकि उसके साथ आए दोनों युवकों पर भी हाथ मुक्कों से मारपीट की। जिससे छात्र के दाहिनी आंख के पास चोट आई और इसके बाद भी उक्त तीनो के द्वारा धमकी दी गयी। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने विवाद देखा सुना और बीच बचाव किया। इस दौरान छात्र की जाति के बारे में जानकारी होने के बावजूद उसके साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित किया गया। साथ ही भविष्य में गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गयी। इसके बाद घायल छात्र ने अपनी मां को पूरी घटना बताई जिसके बाद शिकायतकर्ता माँ अपने बेटे के साथ थाने पहुंचीं। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता २०२३ की धारा २९६ बी, ११५(२), ३५१(३),और ३,५ तथा एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम १९८९ की धारा ३,१ ,घ,३,१ ध और ३,२,५ के तहत तीन बालकों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।

फॉर्म 6 में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त के बाद राजनीतिक मायने?

भारत में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र में नागरिक के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मताधिकार का आधार हैं। इसलिए मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का बदलाव, संशोधन या नई प्रक्रिया केवल प्रशासनिक निर्णय भर नहीं माना जा सकता। इसके पीछे कानून, पारदर्शिता और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता जुड़ी होती है। ऐसे में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में कथित बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने फॉर्म-6 में इस प्रकार के किसी बदलाव को मंजूरी नहीं दी थी। अदालत ने यह जानने की इच्छा जताई है कि आखिर यह बदलाव किसके स्तर पर हुआ और इसके पीछे निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया क्या थी। सीजेआई सूर्यकांत की यह टिप्पणी कि यदि कोई गैर-कानूनी काम हुआ है तो उसके परिणाम भुगतने होंगे, मामले की गंभीरता को स्पष्ट करती है। यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि किसी वैधानिक प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले फॉर्म में बदलाव किया गया, तो वह किस अधिकार के तहत किया गया? क्या यह निर्णय चुनाव आयोग के स्तर पर सामूहिक रूप से लिया गया? क्या सभी चुनाव आयुक्तों की सहमति इसमें थी? क्या इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया? और सबसे महत्वपूर्ण क्या इस बदलाव की जानकारी सार्वजनिक रूप से दी गई थी? लोकतंत्र में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की ताकत केवल उसके अधिकारों में नहीं, बल्कि उसकी निष्पक्षता और सार्वजनिक विश्वास में होती है। चुनाव आयोग पर किसी एक राजनीतिक दल या सरकार का प्रभाव होने का संदेह भी लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए आयोग के प्रत्येक निर्णय में प्रक्रिया की पारदर्शिता उतनी ही आवश्यक है, जितना उसका अंतिम परिणाम। फॉर्म 6 का मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि यह नए मतदाताओं के पंजीकरण से संबंधित है। यदि इस प्रक्रिया में कोई अतिरिक्त घोषणा, दस्तावेज या शर्त जोड़ी जाती है, तो उसका सीधा प्रभाव नागरिक के मतदाता बनने के अधिकार पर पड़ सकता है। किसी पात्र नागरिक को केवल प्रक्रिया की जटिलता के कारण मताधिकार से वंचित होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं माना जा सकता। एसआईआर को लेकर पहले से ही राजनीतिक विवाद चल रहा है। विपक्षी दल इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी संख्या में मतदाता इससे प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग का तर्क अपनी जगह है। ऐसे माहौल में यदि फॉर्म 6 जैसे बुनियादी दस्तावेज में बदलाव को लेकर भी अस्पष्टता पैदा होती है, तो स्वाभाविक रूप से संदेह और बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू उठाया है निर्णय लेने की संस्थागत प्रक्रिया। अदालत यह जानना चाहती है कि एसआईआर से संबंधित निर्णय केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने लिए या फिर चुनाव आयोग ने उन्हें बहुमत अथवा सर्वसम्मति से मंजूरी दी। यह प्रश्न केवल वर्तमान विवाद तक सीमित नहीं है। यह चुनाव आयोग के भीतर सामूहिक निर्णय प्रणाली और संवैधानिक जवाबदेही से भी जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग कोई व्यक्तिगत संस्था नहीं है। यह एक संवैधानिक संस्था है और उसके निर्णय संस्थागत होने चाहिए।

गो-तस्करी के शक से अदालत तक -संदेह से सजा नहीं, सबूत जरूरी!

वैश्विक स्तरपर भारत में मवेशियों के परिवहन गो- तस्करी और गोवध के आरोप लंबे समय से केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं रहे हैं,बल्कि कई बार ये सामाजिक तनाव, भीड़ की हिंसा, मानवाधिकार और संवैधानिक शासन से जुड़े गंभीर प्रश्नों का कारण भी बने हैं।दादरी में सितंबर 2015 में हत्या,झारखंड के लातेहार में मार्च 2016 में दो पशु व्यापारियों की हत्या, राजस्थान के अलवर में अप्रैल 2017 में हत्या और जून 2017 में रामगढ़ में एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग जैसे मामलों ने देश में यह सवाल खड़ा किया कि क्या किसी व्यक्ति पर गो-तस्करी या गोवध का संदेह मात्र उसे कानून अपने हाथ में लेकर दंडित करने का अधिकार किसी भी भीड़ को दे सकता है? स्पष्ट उत्तर है,नहीं।लातेहार मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी दो पशु व्यापारियों की हत्या को लेकर झारखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी थी।2018 में अलवर की हत्या ने इस बहस को फिर तीव्र किया; बाद में स्थानीय अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष की सजा सुनाई। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र मीडिया में आई जानकारी के हवाले से यह बताना चाहूंगा कि इसी व्यापक सामाजिक और कानूनी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट का 29 सितंबर 2026 का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।यह निर्णय मॉब लिंचिंग का फैसला नहीं है, लेकिन मवेशियों के परिवहन को लेकर आपराधिक अभियोजन में संदेह, अनुमान और प्रमाण के बीच की कानूनी सीमा को स्पष्ट करता है।मामले का आधिकारिक रूप से उद्धृत शीर्षक सौरभ बजाज वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ऑदर्स है।यह क्रिमिनल अपील अरिसिंग आउट ऑ? स्पेशल लीव पिटीशन (क्रिमिनल.) नंबर 16871 ऑफ 2026 था और इसका नेउट्रल साइटेशन 2026 ई ए नं एससी 1076 है। फैसला न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.विनोद चंद्रन की पीठ ने 29 सितंबर 2026 को सुनाया।मीडिया पारदर्शिता की दृष्टि से ये विवरण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे पाठक समाचार रिपोर्ट और मूल न्यायिक निर्णय के बीच स्वतंत्र रूप से सत्यापन कर सकता है।

साथियों, मामले की शुरुआत छत्तीसगढ़ कृषि पशु संरक्षण अधिनियम,2004 के अंतर्गत हुई थी,अभियोजन का आरोप था कि 32 बैलों को एक ट्रक में केडुवा से ओडिशा की ओर ले जाया जा रहा था।पुलिस को सूचना मिली और एक हेड कांस्टेबल ने ट्रक को रोककर मवेशियों को जब्त किया तथा चालक और क्लीनर को गिरफ्तार किया।ट्रक के आगे एक बोलेरो वाहन भी चल रहा था, जिसमें चार लोग सवार थे ।पुलिस का आरोप था कि बोलेरो ट्रक को रास्ता दिखाने अथवा उसकी निगरानी करने के लिए आगे चल रही थी।अपीलकर्ता उन्हीं लोगों में शामिल था।अभियोजन ने आरोप लगाया कि मवेशियों का परिवहन अधिनियम की धारा 6 का उल्लंघन करते हुए वध के उद्देश्य से किया जा रहा था।निचली अदालत ने दोषसिद्धि की और धारा 10 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,000 रूपए जुर्माने की सजा दी। प्रथम अपीलीय अदालत और पुनरीक्षण अदालत ने भी दोषसिद्धि कायम रखी, हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने सजा को पहले से भुगती गई अवधि तक सीमित कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

साथियों,सुप्रीम कोर्ट के सामने मूल प्रश्न यह था कि क्या केवल इस तथ्य से कि मवेशियों के परिवहन के समय आवश्यक दस्तावेज मौजूद नहीं थे, यह कानूनी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उन्हें वध के लिए ले जाया जा रहा था ?अदालत ने इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक दिया।पीठ ने कहा कि केवल परिवहन दस्तावेजों काअभाव इस बात की धारणा पैदा नहीं कर सकता कि मवेशियों को वध के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। अदालत ने विशेष रूप से यह स्पष्ट किया कि यदि दस्तावेजों की कमी किसी अन्य कानून या नियम का उल्लंघन है तो उसके परिणाम उसी संबंधित कानून के तहत होंगे;उस कमी को स्वत: छत्तीसगढ़ कृषि पशु संरक्षण अधिनियम के तहत वध के उद्देश्य का प्रमाण नहीं बनाया जा सकता।

साथियों यहां निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत रिवर्स बर्डन ऑफ प्रुफ यानें सबूत के उलटे भार से संबंधित है।सामान्य आपराधिक न्याय व्यवस्था में मूल सिद्धांत यह है कि अभियोजन पक्ष को आरोपी के विरुद्ध अपराध के आवश्यक तत्व संदेह से परे साबित करने होते हैं। विशेष कानूनों में कभी-कभी आरोपी पर भी कुछ तथ्यों को साबित करने की जिम्मेदारी डाली जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा उलटा भार शुरुआत से ही आरोपी पर नहीं डाला जा सकता। पहले अभियोजन को यह स्थापित करना होगा कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद हैं अर्थात मवेशियों को वध के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था अथवा आरोपी को यह जानकारी थी कि उनका वध किए जाने की संभावना है। इसके बाद ही धारा 11 के तहत आरोपी पर संबंधित तथ्य साबित करने का भार सटीकता से आ सकता है।

साथियों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पाया कि हेड कांस्टेबल ने मवेशियों को वध के लिए ले जाए जाने की आशंका व्यक्त की थी, लेकिन केवल उस आशंकाके अलावा रिकॉर्ड में ऐसा पर्याप्त प्रमाण नहीं था जिससे वध का उद्देश्य सिद्ध हो सके। अदालत ने यह भी महत्वपूर्ण माना कि पशु चिकित्सक और गौशाला समिति के अध्यक्ष ने न्यायालय के समक्ष कहा था कि जब्त किए गए मवेशी स्वस्थ थे और कृषि कार्य, जैसे हल चलाने, के लिए उपयुक्त थे। इसलिए केवल पुलिस की आशंका और दस्तावेजों की अनुपस्थिति के आधार पर आपराधिक दोषसिद्धि कायम रखना न्यायसंगत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतत: ट्रायल कोर्ट,प्रथम अपीलीय अदालत और पुनरीक्षण आदेशों को निरस्त करते हुए सौरभ बजाज की दोषसिद्धि समाप्त कर दी और अपील स्वीकार कर ली।

साथियों,इस फैसले का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत में मवेशियों के परिवहन से संबंधित आरोप कई बार सामाजिक तनाव के बीच लगाए जाते हैं।दादरी की घटना में गोवध अथवा प्रतिबंधित मांस के सेवन के आरोपों के बीच भीड़ ने हमला किया था।अलवर के मामले में भी पशु परिवहन के दौरान भीड़ की हिंसा ने देशव्यापी बहस को जन्म दिया।रामगढ़ में भी हत्या उस समय हुई जब उनकी गाड़ी को रोककर उन पर मांस ले जाने का आरोप लगाया गया था;बाद में फास्ट- ट्रैक अदालत ने 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी थी।एक के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी घटना का संज्ञान लिया था और पुलिस की भूमिका तथा घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में हुई देरी को लेकर गंभीर मानवाधिकार प्रश्न उठे थे।

साथियों,हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को मॉब लिंचिंग के मामलों में सीधे लागू होने वाला फैसला समझना उचित नहीं होगा।अदालत ने भीड़ की हिंसा को वैधता नहीं दी है और न ही यह कहा है कि मवेशियों के परिवहन संबंधी दस्तावेजों की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्णय का वास्तविक और सीमित कानूनी अर्थ यह है कि किसी विशेष अपराध के लिए कानून में निर्धारित आवश्यक तत्वों का प्रमाण आवश्यक है। दस्तावेजों का अभाव किसी अलग वैधानिक उल्लंघन का विषय हो सकता है, लेकिन उसे बिना अतिरिक्त प्रमाण के वध के उद्देश्य का निर्णायक प्रमाण नहीं बनाया जा सकता।

साथियों,सबसे बड़ा संवैधानिक संदेश यही है कि कानून का शासन अनुमान पर नहीं,प्रमाण पर चलता है।किसी व्यक्ति पर गो-तस्करी,गोवध अथवा अवैध परिवहन का आरोप लगाना और न्यायालय में उस आरोप को प्रमाणित करना दो अलग-अलग बातें हैं।पुलिस को कानून के अनुसार जांच करनी होगी,अभियोजन को आवश्यक तत्व सिद्ध करने होंगे और न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देना होगा।किसी भी नागरिक को केवल संदेह, अफवाह,भीड़ के आरोप या दस्तावेजों की कमी के आधार पर हिंसा का शिकार बनाना संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। इसी प्रकार,यदि वास्तव में कोई व्यक्ति प्रतिबंधित गतिविधि में शामिल है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भीड़ नहीं,बल्कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए।

अत: अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि सौरभ बजाज वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का फैसला केवल 32 बैलों और एक आरोपी की दोषसिद्धि तक सीमित नहीं है।यह भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के उस मूल सिद्धांत को पुन: रेखांकित करता है कि संदेह अपराध का प्रमाण नहीं है और दस्तावेजों की कमी अपने आप में वध की मंशा का प्रमाण नहीं है।पशु संरक्षण, कानून का पालन और नागरिकों की सुरक्षा,तीनों एक साथ संभव हैं,लेकिन इसकी शर्त यही है कि कानून को भीड़ के हाथों नहीं, बल्कि संविधान और न्यायिक प्रक्रिया के हाथों संचालित किया जाए।यही इस फैसले का सबसे व्यापक सामाजिक,कानूनी और लोकतांत्रिक संदेश है।

-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

भारत में ब्याज दरों में बढ़ौतरी का चक्र प्रारम्भ

-प्रहलाद सबनानी

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 7 अक्टोबर 2026 को घोषित अपनी मौद्रिक नीति (मोनेटरी पॉलिसी) के माध्यम से रेपो दर में 25 आधार बिंदुओं की वृद्धि करते हुए इसे 5.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया है। भारत में, फरवरी 2023 के पश्चात, प्रथम बार रेपो दर में वृद्धि की घोषणा की गई है। अब संभवतः समस्त बैंक अपने ऋणों पर ब्याज दरों में बढ़ौतरी की घोषणा करेंगे। दरअसल, भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी मुद्रा स्फीति की दर में वृद्धि देखी जा रही है और मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा आदि देश पहिले से ही ब्याज दरों में वृद्धि की घोषणा कर चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास भी मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से रेपो दर में वृद्धि करने के अतिरिक्त और कोई उपाय था भी नहीं। रेपो दर में वृद्धि वित्तीय बाजार में लगाए जा रहे अनुमान के आधार पर ही रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि निकट भविष्य में रेपो दर में कमी की सम्भावना अब कम ही है बल्कि वित्तीय बाजार का अनुमान है कि दिसम्बर माह में होने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक में भी सम्भवतः रेपो दर में 25 आधार बिंदुओं की पुन: वृद्धि की घोषणा की जाएगी। दरअसल वैश्विक स्तर पर वित्तीय बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है क्योंकि रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराईल-हम्मास युद्ध, ईरान-अमेरिका युद्ध तो लम्बे समय से चल ही रहा था अब सऊदी अरब-हूथी युद्ध भी छिड़ गया है एवं इसमें पाकिस्तान एवं टर्की भी शामिल हो गए हैं। इस सबका विपरीत प्रभाव वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति पर पड़ा है एवं कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं जिससे विश्व के कई देशों में मुद्रा स्फीति की स्थिति लगातार गम्भीर होती जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत में मुद्रा स्फीति के अनुमान को बढ़ाया है। पूर्व में, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत में मुद्रा स्फीति के 5 प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 5.2 प्रतिशत कर दिया गया है। मुद्रा स्फीति, एक गम्भीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है, इसे नियंत्रित करना अति आवश्यक है क्योंकि इसका सबसे अधिक विपरीत प्रभाव गरीब नागरिकों पर अति गम्भीर रूप से पड़ता है। मुद्रा स्फीति के लगातार बढ़ने से नागरिकों की क्रय शक्ति कमजोर हो जाती है। पूरे विश्व में लगभग समस्त देशों द्वारा मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है ताकि नागरिक अपने खर्चों को बढ़ाने के लिए निरुत्साहित हों एवं इस धनराशि को वे बैंकों में जमा करें एवं साथ ही नागरिक बैंकों से ऋणराशि लेने हेतु भी निरुत्साहित हों क्योंकि ब्याज दर के बढ़ाने से ऋणराशि पर अब अधिक ब्याज देना होगा। इससे बाजार में उत्पादों की मांग में कमी आती है एवं उत्पादों की कीमतें कम होने लगती हैं और अंतत: मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण स्थापित होने लगता है। परंतु, ब्याज दरों में एक सीमा से अधिक वृद्धि करने से आर्थिक विकास दर विपरीत रूस से प्रभावित होने लगती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में तो मुद्रा स्फीति का उल्लेख ही नहीं मिलता है क्योंकि उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति बाजार में बनाए रखी जाती थी, बल्कि शास्त्रों में उत्पादों के दाम कम होते जाने का उल्लेख जरूर मिलता है। वर्तमान स्थिति बिलकुल भिन्न है, बाजार में उत्पादों की मांग बढ़ जाती है परंतु आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाती है, इससे इन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि दृष्टिगोचर होने लगती है।

प्राचीन भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुसार, मूल्य वृद्धि को बाजार में वस्तुओं/उत्पादों की आपूर्ति को बढ़ाकर नियंत्रित किया जाना चाहिए न कि इन उत्पादों की मांग में कमी करने के प्रयास कर इन वस्तुओं/उत्पादों की कीमतों पर नियंत्रण स्थापित किया जाय। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत ब्याज दर में की गई वृद्धि के कारण बाजार पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव को आंकने का प्रयास ही नहीं किया जाता हैं। यदि उत्पादों की मांग में कमी करने के प्रयास किए जाएंगे तो इन उत्पादों का निर्माण कम होगा, इससे विनिर्माण इकाईयों एवं इन इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। उत्पादन कम होने के चलते विनिर्माण इकाईयों द्वारा बहुत सम्भव है कि श्रमिकों की छटनी की जाने लगे। इससे देश में बेरोजगारी फैल सकती है। परंतु, भारत में इस तरह की समस्या वर्तमान परिस्थितियों में बीच दिखाई नहीं देती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी यह सम्भावना व्यक्त की गई है कि रेपो दर में की गई वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना लगभग शून्य है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली वृद्धि दर को संशोधित कर इसे पूर्व के अनुमान 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया गया है। अन्यथा, सामान्यत: ब्याज दरों में वृद्धि का आर्थिक विकास दर पर विपरीत प्रभाव दिखाई देता है। भारत में आर्थिक विकास दर मजबूत बनी हुई है। हाल ही के समय में विशेष रूप से विनिर्माण के क्षेत्र एवं सेवा के क्षेत्र में आकर्षक वृद्धि दर दर्ज हुई है। विभिन्न उत्पादों के निर्यात भी तेज गति से बढ़ रहे हैं। निजी क्षेत्र में निवेश भी अब बढ़ने लगा है जबकि सरकारी क्षेत्र में निवेश तो पहिले से ही मजबूत बना हुआ है। बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋणराशि में अतुलनीय वृद्धि दिखाई दे रही है एवं वस्तु एवं सेवा कर तथा आय कर एवं कारपोरेट कर के संग्रहण में मजबूत वृद्धि दिखाई दे रही है। भारत उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था है अत: स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों का बाजार भारत में ही उपलब्ध रहता है, केंद्र सरकार की नीतियों के चलते इन उत्पादों के अन्य देशों से आयात को निरुत्साहित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, अन्यथा यदि इन उत्पादों का आयात आसानी होने दिया जाय तो सम्भव है कि इन उत्पादों के साथ मुद्रा स्फीति भी आयातित होने लगे, जैसा महंगे कच्चे तेल के आयात से हो रहा है। भारत में बढ़ रही मुद्रा स्फीति के लिए कुछ हद्द तक अन्य देशों से आयातित उत्पादों (स्वर्ण, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कच्चा तेल आदि) की बढ़ी हुई कीमतें भी जिम्मेदार हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रेपो दर में 25 आधार बिंदुओं की वृद्धि के निर्णय के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण जिम्मेदार है। दरअसल, अमेरिका की केंद्रीय बैंक यूएस फेड रिजर्व ने यू एस फेड दर में वृद्धि की घोषणा की है। इसस `, अमेरिकी में बांड यील्ड में अतुलनीय वृद्धि ध्यान में आई है। 30 वर्षीय बांड यील्ड बढ़कर 5.60 प्रतिशत के स्तर को पार कर गई है, जो वर्ष 2002 के बाद से सबसे अधिक है। इससे विदेशी संस्थागत निवेशक, तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं में से अपने निवेश को निकालकर अमेरिकी बांड में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। इसके चलते भारत सहित कई देशों की मुद्राओं की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी से गिर रही है। अत: अपने देश की मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से भी कई देशों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की जा रही है ताकि विदेशी निवेश को अपने देश में आकर्षित किया जा सके। भारत में रेपो दर में वृद्धि से भारत के बांड बाजार में भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले बांड पर यील्ड में सुधार होगा जिससे विदेशी निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले बांड में अपना निवेश बढ़ा सकते हैं।

बेहतर विकल्प एवं जरूरी मुद्दों का अभाव ही विपक्ष की अक्षमता

भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि यहां कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती और कोई भी विपक्ष हमेशा के लिए विपक्ष नहीं रहता। सत्ता के लंबे कार्यकाल के बाद स्वाभाविक रूप से सरकार के प्रति उकताहट पैदा होती है। लेकिन उकताहट और सत्ता परिवर्तन के बीच एक बड़ा अंतर है। मतदाता किसी सरकार से नाराज हो सकता है, उसके कामकाज पर सवाल उठा सकता है, फिर भी केवल नाराजगी के आधार पर किसी ऐसे विकल्प को स्वीकार नहीं करता, जिसके पास देश के भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा न हो, जो सत्ता का लालची एवं बेहतर विकल्प से वंचित हो। आज भारतीय राजनीति में विपक्ष के सामने मूल प्रश्न यही है-क्या वह केवल सरकार से असंतुष्ट है या जनता के सामने कोई विश्वसनीय विकल्प भी रख रहा है? राहुल गांधी लंबे समय से यह सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सरकार के प्रति अपेक्षित एंटी-इंकबेंसी दिखाई क्यों नहीं देती। उनका आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी और 'वोट चोरी' के कारण जनता की वास्तविक इच्छा सामने नहीं आ पा रही। इन आरोपों के समर्थन में उनके द्वारा प्रस्तुत दावों को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस जारी है, उन्हें अंतिम रूप से सिद्ध तथ्य मानना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची और निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता पर उठने वाले प्रत्येक प्रश्न का निष्पक्ष और तथ्यात्मक उत्तर मिलना लोकतंत्र के हित में है।

इसी संदर्भ में एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विवाद महत्वपूर्ण हो गया है। निर्वाचन आयोग स्वयं एसआईआर-2026 से संबंधित मतदाता सेवाएं और मतदाता सूची उपलब्ध करा रहा है तथा वह अपने को स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण बताता है। दूसरी ओर विपक्ष ने इस प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस विवाद को अब सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती मिली है। इस पूरे मामले का अंतिम निष्कर्ष राजनीतिक नारों से नहीं, संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया से निकलेगा। यहीं विपक्ष की राजनीति की असली परीक्षा शुरू होती है। चुनाव आयोग के विरुद्ध आंदोलन करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है। मतदाता सूची में यदि किसी पात्र नागरिक का नाम गलत ढंग से हटाया गया है तो उसका विरोध होना चाहिए। यदि किसी अधिकारी ने नियमों का उल्लंघन किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र की रक्षा केवल आयोग के विरोध से नहीं होगी। लोकतंत्र की रक्षा तब होगी जब विपक्ष जनता को यह भी बताए कि सत्ता मिलने पर वह शिक्षा, रोजगार, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शहरी जीवन, कानून-व्यवस्था और प्रशासन में क्या बदलेगा।

यही वह बिंदु है जहां 'वोट चोरी' का राजनीतिक विमर्श जनता के रोजमर्रा के सवालों से टकराता है। एक सामान्य परिवार को बच्चों की महंगी शिक्षा की चिंता है। रोजगार की बदलती प्रकृति, एआई और नई तकनीक के कारण पारंपरिक कौशल तेजी से अप्रासंगिक हो रहे हैं। डिग्री लेने के बाद भी रोजगार की गारंटी नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल की घटनाएं युवाओं के विश्वास को चोट पहुंचाती हैं। ऐसे में युवा यह जानना चाहता है कि अगली सरकार परीक्षा व्यवस्था को कैसे विश्वसनीय बनाएगी, स्कूलों की गुणवत्ता कैसे सुधारेगी और बदलती तकनीकी अर्थव्यवस्था के लिए करोड़ों युवाओं को तैयार कैसे करेगी। किसान की समस्या भी केवल एमएसपी या आंदोलन तक सीमित नहीं है। फसल आने पर कीमत गिर जाती है और कुछ महीने बाद वही प्याज, टमाटर या दूसरी सब्जियां महंगी हो जाती हैं। इसका समाधान केवल विरोध में नहीं, बल्कि गांव-कस्बे तक भंडारण, कोल्ड-चेन, प्रसंस्करण, कृषि बाजार और मूल्यवर्धन की मजबूत व्यवस्था में है। विपक्ष यदि कृषि सुधारों का विरोध करता है तो उसे यह भी बताना होगा कि वह वैकल्पिक कृषि ढांचा किस तरह खड़ा करेगा।

रोजगार का प्रश्न इससे भी बड़ा है। भारत की युवा आबादी को उद्योग, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, अनुसंधान और नई तकनीक से जोड़ना होगा। निवेश के लिए स्थिर कानून-व्यवस्था, पारदर्शी प्रशासन और भरोसेमंद कारोबारी वातावरण जरूरी है। केवल बड़े उद्योगपतियों पर राजनीतिक प्रहार या संपत्ति की गणना जैसे नारों से रोजगार पैदा नहीं होते। विपक्ष यदि संपत्ति के पुनर्वितरण या सामाजिक न्याय की बात करता है तो उसे साथ ही यह भी बताना होगा कि संपत्ति और अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे। 'जितनी आबादी, उतना हक' जैसी राजनीति सामाजिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न को सामने लाती है, लेकिन आज की चुनौती प्रतिनिधित्व के साथ-साथ क्षमता निर्माण की भी है। पिछड़े, दलित, आदिवासी और कमजोर वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और अवसर मिलें-यह सामाजिक न्याय का अधिक स्थायी आधार है। केवल आंक? गिनना पर्याप्त नहीं, उन आंक?ों के पीछे खड़े मनुष्य का जीवन बदलना जरूरी है। इस पूरे परिदृश्य में ममता बनर्जी की भूमिका विशेष चर्चा का विषय बनी है। राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर नया विमर्श अवश्य उभरा है। हाल की इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्होंने विपक्ष का दायरा बढ़ाने और व्यापक एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा संकट केवल भाजपा से मुकाबला नहीं, बल्कि उसके भीतर का परस्पर अविश्वास है। सीटों का बंटवारा, क्षेत्रीय वर्चस्व, नेतृत्व का प्रश्न और राज्यों में एक-दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों का राष्ट्रीय स्तर पर साथ आना आसान नहीं है। आज की स्थिति में आप का चुनाव आयोग तक प्रस्तावित मार्च से अलग रहकर अपना रास्ता अपनाना भी इस अंतर्विरोध को दिखाता है।

कांग्रेस, तृणमूल, समाजवादी पार्टी, वामपंथी दल, राजद, आप और दूसरे क्षेत्रीय दल जब अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग राजनीति करते हैं, तब राष्ट्रीय मंच पर उनका साझा न्यूनतम कार्यक्रम क्या है? जनता इसी का उत्तर चाहती है। चुनाव आयोग के मुद्दे पर भी यही कसौटी लागू होती है। इंडिया गठबंधन ने 6 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग तक मार्च सहित विरोध कार्यक्रम घोषित किए हैं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई है। यह आंदोलन संवैधानिक प्रश्नों को सार्वजनिक बहस के केंद्र में ला सकता है। लेकिन यदि विपक्ष का पूरा राजनीतिक अभियान केवल एक व्यक्ति के इस्तीफे तक सीमित रह गया, तो इससे चुनावी संस्थाओं पर व्यापक विश्वास का प्रश्न हल नहीं होगा। उसे यह भी बताना होगा कि सत्ता में आने पर निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, मतदाता सूची, ईवीएम-वीवीपैट, चुनावी चंदे और चुनावी पारदर्शिता को लेकर वह कौन से संस्थागत सुधार करेगा।

बड़ा प्रश्न है कि सत्ता की पात्रता को विकसित करने के लिये विपक्ष क्यों नहीं जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सकारात्मक राजनीति को बल देती। वास्तव में विपक्ष के सामने सबसे बड़ा संकट मुद्दों की कमी नहीं, मुद्दों को समाधान में बदलने की क्षमता का है। बेरोजगारी है, शिक्षा का संकट है, कृषि की समस्या है, स्वास्थ्य का खर्च है, महंगाई की चिंता है, शहरी प्रदूषण है, एआई से बदलती नौकरियां हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की प्रतिस्पर्धा का प्रश्न है। जनता इन सबको प्रतिदिन महसूस करती है। लेकिन राजनीतिक विमर्श बार-बार मोदी बनाम कौन, राहुल बनाम मोदी, ईवीएम बनाम बैलेट और आयोग बनाम विपक्ष की बहस में सिमट जाता है। भारतीय मतदाता सरकार से मोहभंग होने पर भी यह देखता है कि उसके सामने विकल्प क्या है। वह जमीन छोड़कर अंधे कुएं में छलांग नहीं लगाता। उसे ऐसा विपक्ष चाहिए जो सरकार की कमियां गिनाने के साथ अपनी क्षमताएं भी बताए, जो केवल सत्ता की आलोचना नहीं, शासन का वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करे, जो चुनाव आयोग से सवाल पूछे तो अपनी चुनावी पारदर्शिता की कसौटी भी सामने रखे, जो सामाजिक न्याय की बात करे तो शिक्षा और अवसर का रास्ता भी बताए, जो उद्योगपतियों से सवाल करे तो निवेश और रोजगार की अपनी नीति भी स्पष्ट करे।

लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही जितनी जरूरी है, विपक्ष की जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। सत्ता से मोहभंग लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन उस मोहभंग को राजनीतिक परिवर्तन में बदलने के लिए विश्वसनीय विकल्प चाहिए। आज इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती भाजपा और नरेंद्र मोदी से लड़ने से बड़ी है-उसे जनता के मन में यह विश्वास पैदा करना है कि उसके पास भारत के अगले दशक की कोई स्पष्ट, ठोस और क्रियान्वित करने योग्य कहानी भी है। विपक्ष यदि यह विश्वास पैदा कर पाया तो चुनाव आयोग का मुद्दा भी लोकतांत्रिक सुधार की सार्थक बहस बनेगा, ममता बनर्जी की भूमिका भी सार्थक होगी और राहुल गांधी के सवाल भी व्यापक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनेंगे।

-ललित गर्ग

इंदौर बाजार भाव

इंदौर। एजेंसी। संयंत्रों की माँग से बुधवार को अनाज मंडी में सोयाबीन बाजार बढ़त पर रहे। खाद्य तेलों में व्यापार ठंडा-ठंडा ही रहा। दलहनों में तेजी के तेवर कायम रहे। किराना जिंसों में नारियल व सूखे मेवों में पूछपरख अच्छी रही। व्यापारिक सूत्रों के अनुसार सोयाबीन में संयंत्रों की लेवाली से बाजार बढ़त पर रहे। सोयाबीन सुधरकर 5900-6000 रू. प्रति क्विंटल पर आ गये। खाद्य तेलों में व्यापार ठंडा-ठंडा ही रहा। दलहनों में सुर्खी कायम रही। चना बढ़िया मालों में 7550-7600 रू. क्विंटल पर आ गया। उधर, किराना जिंसों में नारियल व सूखे मेवों में पूछपरख से बाजार बढ़त पर रहे। भाव इस प्रकार रहे-

किराना- शक्कर 4760-4820, खोपरा गोला 330-380, खोपरा बूरा 3150-5800 (15 कि.ग्रा.), जीरा राजस्थान 280-285, ऊंझा हल्का 290-295, बेस्ट 315-325, हल्दी निजामाबाद 230-250, सांगली 310-320, साबूदाना हल्का 5200-5350, मीडियम 5450-5600, बेस्ट 6000-6100, सच्चा मोती 5700, मोरधन 7200-8200, सौंफ मोटी 275-350, बेस्ट 350-400, सौंफ बारिक 180-300, एक्स्ट्रा बोल्ड 350-400, राई दाल 90-95, सरसो दाल 85-95, कालीमिर्च एटम 775-785, गारबल्ड 755-760, मटरदाना 800-900, खसखस अनक्लीन 1150-1250, क्लीन 1300-1350, दालचीनी 250-260, जायफल 725-750, वाद्यान फूल 405-600, शाहजीरा 350-400, तेजपान 90-100, पत्थर फूल 235-425, जावत्री 1675-1750, केसर 200-250, नाग केसर 925-975, सौंठ 325-500, धोली मूसली 1400-1600, लौंग 700-720, बेस्ट 760-790, हींग (वनदेवी 751) 3450, पाउच 10 ग्राम 3550, सिंघाडा छोटा 100-120, बड़ा 120-130, सिंदूर (25 कि.ग्रा. पैकिंग) 7300, देशी कपूर 1050-1150, पूजा बादाम 115-125, बेस्ट 220-230, पूजा सुपारी 425-450, अरीठा 180-200, हरी इलायची शंकर 3000-3300, मीडियम 3500-3600, बेस्ट 4400-4600, एक्ट्रा बेस्ट 4600-4800, पानबार 3000-3200, बड़ी इलायची 1350-1650, तरबूज मगज 480-520, काजू (240) 940-960, काजू (320) 910-920, काजू डब्ल्यू (340) 850-870, काजू एस.डब्ल्यू (300) 850-900, काजू जे.एच. 840-870, टुकड़ी 780-820, बादाम मगज 1065-1200, सिंगापुरी 980-1000, बादाम टांच 700-725, अखरोट 590-850, अखरोट गिरी 1250-1550, जर्दालु 375-500, बेस्ट 550-650, किशमिश कंधारी 450-600, इंडियन 400-450, चारौली 1450-1750, मुनक्का 350-550, अंजीर 850-950, मखाना 750-890, बेस्ट 1250-1300, खारक एवरेज 75-80, मीडियम 90-130, बेस्ट 140-260, पिस्ता पिशोरी 2900-3100, कंधारी 2500-2700, नमकीन पिस्ता 1000-1150, बेस्ट 1200-1250, गेहूँ आटा 1820, मैदा कट्टा 1850, रवा कट्टा 1880, बेसन 4675 (50 कि.ग्रा.), नारियल (120) 3200, (160) 3400, (200) 3700, (250) 4500,

तेल- सींगदाना 1660-1680, मुम्बई 1700, राजकोट तेलिया 2650, सोया साल्वेंट 1370-1375, सोया रिफाइंड 1425-1430, कपास्या 1485, धूलिया 1480, कड़ी 1485,

रात की धारणा- गुजरात लुज 1650, मुम्बई पाम 1450, मुम्बई सोया 1450,

खली - कपस्या खली (60 कि.ग्रा.) इन्दौर 2690, देवास-उज्जैन 2690, खंडवा-बुरहानपुर 2660, अकोला 3950 (प्रति क्विंटल)

तिलहन- सरसो 8500, रायडा 7300-7500, सोयाबीन 5900-6000, टोली (महुआ बीज) 5700-5900, करंज 4400-4500, अलसी 8500-9000, अरंडी 4500-4700, तिल्ली पुरानी 6500-7000, तिल्ली नई 7200-7500,

दलहन- चना कांटेवाला बेस्ट 7550-7600, विशाल 7400-7500, काबूली चना डॉलर 7200-8500, काबूली चना रशियन 5600-5800, बिटकी 5200-5300, मसूर बेस्ट 6100-6150, एवरेज 6000-6050, मूंग गर्मी बेस्ट 8100-8300, मूंग पुराना बोल्ड 8400-8500, तुअर निमाड़ी बेस्ट 8800-8900, एवरेज 8600-8700, हल्की 8400-8500, महाराष्ट्र सफेद 8900-9100, महाराष्ट्र लाल 9300-9500, कर्नाटक 9400-9600, उड़द बेस्ट 9600-9900, उड़द गर्मी 9200-9600, ग्रेविटी क्लीन 9800-10100, हल्की 4000-6000,

दाल- चना दाल एवरेज 7400-7500, मीडियम 7600-7700, बोल्ड 7900-8100, तुअर दाल सवा नं. 8200-8400, तुअर दाल 7300-7600, तुअर दाल मीडियम 8500-8800, बेस्ट 9900-10200, मसूर दाल 6800-7100, मूंग दाल 8700-8900, मूंग मोगर 10100-10600, उड़द दाल 9900-10300, मोगर 10800-11000,

अनाज- गेहूं मिल क्वालिटी 2500-2550, लोकवन एवरेज 2550-2650, बेस्ट 2750-2800, मालवराज 2600-2650, गेहूँ पूर्णा एवरेज 2400-2550, बेस्ट 2650-2750, मक्का पीली 1975-2000,

चावल- चावल हंसा सफेद 2900-3100, सेला 3500-3700, परमल 3400-3500, दुबराज 4500-5500, राजभोग 7500, काली मुंछ डिनर किंग 9000-9500, बासमती दुबार 8000-8500, मीनी दुबार 8000-8500, मोगरा 5000-7000, तिबार 10500-11800, बासमती (921) 12000-13000, बासमती सेला 7500-9500, पोहा 4500-5100,

मावा- इन्दौर 360, उज्जैन 310, रतलाम 300 रू. प्रति किलो।

इंदौर सर्राफा बाज़ार

इन्दौर। एजेंसी। बुधवार को स्थानीय सराफा बाजार में कामकाज की मात्रा कम ही रही। दोनों ही मूल्यवान धातुओं में बाजार पूर्वस्तर पर बने रहे। भाव इस प्रकार रहे -

चॉंदी (9999) 226000, चॉंदी (99) 225800, टंच 225200, सिक्का 2600, सोना 10 ग्राम 149000,

बैंक एसडी पर मिलने वाले ब्याज को अपनी मर्जी से कम नहीं कर सकता

नई दिल्ली। एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) को लेकर एक फैसला सुनाया है, जिसके तहत अगर किसी एफडी को कोर्ट के आदेश पर बनाया गया है, तो बैंक उस पर मिलने वाले ब्याज को अपनी मर्जी से कम नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि बैंक के पास ब्याज कम करने के लिए कोई वैध कारण होना जरूरी है। यह मामला हीरो एक्सपोर्ट्स और टिफिन्स बैरीट्स, एस्बेस्टोस एंड पेंट्स लिमिटेड के बीच चल रहे विवाद से जुड़ा था, जिसमें कोर्ट के आदेश पर 5.89 करोड़ रुपए की एफडी नैटवेस्ट मार्केट्स पीएलसी में बनाई गई थी। शुरुआत में इस एफडी पर 7.75फीसदी से 8.25फीसदी तक ब्याज मिलता रहा, लेकिन 30 जनवरी 2018 से बैंक ने ब्याज दर घटाकर 3.5फीसदी कर दी। हीरो एक्सपोर्ट्स ने इस कटौती का विरोध किया और मामला कोर्ट पहुंच गया।

शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद

मुम्बई। एजेंसी। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। इस गिरावट का एक बड़ा कारण भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी करना भी रहा। इससे निवेशकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा जिससे बाजार में बिकवाली शुरु हो गयी। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 429.11 अंक टूटकर 72,638.70 पर बंद हुआ जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी भी 173.05 अंक फिसलकर 22,603.05 पर बंद हुआ। आज बाजार में बिकवाली के कारण तकरीबन 2251 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि 1928 शेयरों में बढ़त आई। वहीं 192 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज करने वाले शेयरों में टाइटन कंपनी, अडानी एंटरप्राइजेज, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जेएस डब्लयू स्टील और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख थे, जिन्होंने निवेशकों को निराश किया। वहीं, कुछे शेयर ऐसे भी थे जिन्होंने इस माहौल में भी अपनी बढ़त बनाए रखी, जिनमें कोटक महिंद्रा बैंक, बीएसई लिमिटेड, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक और कोल इंडिया शामिल थे। वहीं सेक्टरों की बात करें तो, मीडिया और पीएसयू बैंक को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी, वाहन, धातु और रियल्टी सेक्टरों में 1-2 फीसदी की भारी गिरावट रही, जो दिखाती है कि व्यापक आर्थिक चिंताओं से सभी प्रभावित हुए हैं। आज बाजार गिरावट का सबसे अहम कारण आरबीबाई द्वारा रेपो दर में 25 बेसिस अंकों की बढ़ोतरी रही। जिससे यह दर फरवरी 2023 के बाद पहली बार बढ़ी है। यह बढ़ोतरी तब हुई है जब बाजार विश्लेषक और निवेशक दोनों मुद्रास्फीति के दबावों पर केंद्रीय बैंक की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे।

थर्मल पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक नीचे लेवल पर, देश में महंगी होगी बिजली

नई दिल्ली। एजेंसी। देश में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इसके चलते स्पॉट मार्केट में बिजली की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। वहीं दूसरी ओर थर्मल पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक भी नीचे लेवल पर आ गया है। सितंबर में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के डे-अहेड मार्केट में बिजली की औसत कीमत बढ़कर 7.3 रुपए प्रति यूनिट हो गई, जो पिछले साल के मुकाबले 105फीसदी ज्यादा है। इतना ही नहीं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के डे-अहेड मार्केट में खरीद की बोलियों में 281फीसदी का उछाल यह साफ दिखाता है कि राज्यों के बिजली वितरण निगम ग्रिड पर बढ़ती मांग से किस कदर जूझ रहे हैं। बता दें अधिकतर राज्य बिजली वितरण कंपनियां पहले से ही घाटे में चल रही हैं। ऐसे में एक्सचेंज से 7.3 रुपए प्रति यूनिट की महंगी दर पर शॉर्ट-टर्म बिजली खरीदने से उनका वित्तीय संकट और गहरा सकता है। वहीं, जिन राज्यों के पास महंगी बिजली खरीदने का बजट नहीं है उन्होंने अपने हाथ पहले से ही खड़े कर दिए हैं। ऐसे में बिजली की बढ़ती मांग को मैनेज करने के लिए ये ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का सहारा ले रहे हैं। नियमों के मुताबिक थर्मल पावर प्लांट के पास कम से कम 15 से 20 दिनों के कोयले का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन अभी इनके पास सिर्फ 20.5 मिलियन टन कोयला है, जो आवश्यक स्टॉक का सिर्फ 33फीसदी है। इससे औसतन केवल 6 से 7 दिनों की जरूरतें ही पूरी हो सकती हैं। ऐसे में ग्रिड पर ब्लैकआउट का खतरा काफी बढ़ जाता है। बता दें जब आईईएक्स पर बिजली की मांग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, तो बिजली की प्रति यूनिट कीमत भी बढ़ती है। आखिरकार इसका सीधा बोझ राज्यों और अंतत: आम उपभोक्ताओं और फैक्ट्रियों पर पड़ता है।

कल जीएसटी काउंसिल की बैठक, ऑनलाइन फूड डिलीवरी लागत को लेकर होगा फैसला

नई दिल्ली। एजेंसी। 8 अक्टूबर यानी गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, जिसमें ऑनलाइन फूड डिलीवरी की लागत से जुड़ा फैसला हो सकता है, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ सकता है। डिलीवरी चार्ज पर लगने वाला जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। हालांकि, अंतिम फैसला बैठक में ही होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खाना ऑर्डर करने पर खाने की कीमत पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है, लेकिन डिलीवरी फीस को अलग सेवा मानते हुए उस पर 18 फीसदी टैक्स लगाया जाता है। अब जीएसटी काउंसिल इस अंतर को खत्म करने पर विचार कर रही है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म पर लगने वाली डिलीवरी फीस पर भी 5 फीसदी जीएसटी लागू हो सकता है। इससे बिलिंग व्यवस्था आसान होने के साथ ग्राहकों को भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। बैठक में होटल, रेस्टोरेंट और फिटनेस सेंटर जैसे कारोबारों के लिए आईटीसी से जुड़ा प्रस्ताव भी चर्चा में है। 5 फीसदी जीएसटी देने वाले इन सर्विस प्रोवाइडर्स को कुछ इनपुट खर्चों पर टैक्स क्रेडिट देने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इससे कारोबारियों की लागत कम करने में मदद मिल सकती है। जीएसटी काउंसिल दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को लेकर भी अहम फैसला कर सकती है। सात और दुर्लभ बीमारियों को जीएसटी छूट वाली सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे महंगी और जीवनरक्षक दवाओं पर मरीजों का आर्थिक बोझ कम हो सकता है। डिफेंस सेक्टर में मिसाइल के पुर्जों, स्पेयर पार्ट्स और विशेष टेस्टिंग उपकरणों को आर्जीएसटी छूट देने पर विचार हो सकता है। वहीं, कृषि बीजों की स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाओं को जीएसटी से मुक्त करने का प्रस्ताव भी सामने है। इसके अलावा विदेशी शिपिंग कंपनियों को दी जाने वाली कुछ सेवाओं और सिमिनस प्रोविडेंट फंड ओरगंनाइजेशन की सेवाओं को भी टैक्स राहत देने पर चर्चा हो सकती है। जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक गुरुवार को होगी, फिलहाल ये सभी प्रस्ताव विचाराधीन हैं। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही इन पर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

मेष- आज दिन की शुरुआत ही अच्छे संकेतों के साथ हो सकती है। धन लाभ के साथ मन को खुश करने वाली कोई खबर भी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, इसलिए कई काम बिना ज्यादा परेशानी के पूरे हो जाएंगे। संतान के साथ कहीं घूमने जाने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में और अपनापन आएगा। विरोधियों से निपटने में आपकी समझदारी और आत्मविश्वास काम आएगा।

वृषभ- आज कुछ नया करने और अपनी क्षमता साबित करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों भरपूर रहेंगे, इसलिए जिस काम को हाथ में लेंगे उसे पूरा करने का जज्बा भी रहेगा। हालांकि दूसरों को बिना मांगे सलाह देने से बचें, क्योंकि आपकी अच्छी बात भी कोई गलत तरीके से ले सकता है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में ध्यान लगाने का समय है, खासकर यदि परीक्षाएं नजदीक हैं।

मिथुन- आज तरक्की के नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों और करीबी लोगों का साथ मिलेगा, जिससे किसी भी चुनौती का सामना करने का आत्मविश्वास बना रहेगा। सेहत से जुड़ी कोई छोटी परेशानी थोड़ी असुविधा दे सकती है, लेकिन जल्द ही राहत मिल जाएगी। कारोबार में कुछ मुश्किलें सामने आएंगी, मगर आपकी सूझबूझ से रास्ता निकल आएगा। शेयर बाजार में पैसा लगाने का विचार है तो जल्दबाजी न करें और पूरी जानकारी लेने के बाद ही निर्णय लें।

कर्क- आज आपको हर महत्वपूर्ण फैसले में थोड़ा ठहरकर सोचने की जरूरत है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी खड़ी कर सकता है। खासकर पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी रखें और किसी अनजान व्यक्ति की बातों पर तुरंत भरोसा न करें। कार्यक्षेत्र में बॉस या वरिष्ठ अधिकारी की ओर से कोई ऐसी सलाह मिल सकती है, जो आपके काम को नई दिशा दे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए कोई अच्छी खबर आने की संभावना है।

सिंह- आज कुछ पारिवारिक चिंताएं आपको मानसिक रूप से व्यस्त रख सकती हैं। पुरानी समस्या फिर सामने आने से थोड़ी परेशानी महसूस होगी। नौकरी से जुड़ा कोई काम आपको दूसरे शहर या स्थान की यात्रा करा सकता है। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों को किसी पद, जिम्मेदारी या सम्मान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। सफलता मिलने पर भी अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें।

कन्या- आज आपकी बातों का असर रिश्तों पर साफ दिखाई दे सकता है, इसलिए बोलते समय थोड़ा संयम रखें। परिवार में किसी करीबी को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। वहीं मधुर भाषा और समझदारी से माहौल को सहज बनाए रखा जा सकता है। प्रेम जीवन से जुड़ा कोई व्यक्ति आपके लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है, जिससे दिन और खास हो जाएगा।

तुला- आज वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है। यदि पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही है तो आज उस पर ध्यान देना जरूरी होगा। किसी पुराने मित्र की याद आपको भावुक कर सकती है। भाई-बहनों के साथ चली आ रही नाराजगी बातचीत के जरिए दूर होगी और रिश्तों में फिर से गर्माहट लौटेगी।

वृश्चिक- आज का दिन मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारियों के बीच बीतेगा। काम को लेकर थोड़ी भी लापरवाही न करें, क्योंकि छोटी गलती भी काम को उलझा सकती है। कोई मित्र निवेश का नया प्रस्ताव आपके सामने रख सकता है, लेकिन केवल भरोसे के आधार पर फैसला न लें।

धनु- आज का दिन उत्साह और सकारात्मकता से भरा रहेगा। काम के प्रति आपका जोश बढ़ेगा और नौकरी या कारोबार में मन लगाकर काम करने का अवसर मिलेगा। हालांकि संतान की संगति और उसके आसपास के लोगों पर नजर रखना जरूरी होगा। पुरानी गलतियों को दोहराने से बचें, क्योंकि वही गलती फिर परेशानी खड़ी कर सकती है।

मकर- आज आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है। आय के किसी अतिरिक्त स्रोत से पैसा मिलने की संभावना है, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। घर में धार्मिक कार्यक्रम या पूजा-पाठ होने से माहौल सकारात्मक और शांत रहेगा।

कुंभ- आज प्रॉपर्टी से जुड़े किसी लेन-देन के लिए अवसर अच्छा हो सकता है, लेकिन कागजी कार्रवाई में पूरी सावधानी रखें। कोई व्यक्ति आपको गलत जानकारी देकर फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े भरोसा न करें। परिवार में पुरानी कड़वाहट दूर करने का अच्छा मौका मिलेगा। घर में स्वादिष्ट भोजन और अपनों के साथ बिताया समय मन को खुश रखेगा।

मीन- आज का दिन खुशियों से भरा रह सकता है और एक के बाद एक अच्छी खबरें आपका मन प्रसन्न करेंगी। संतान की किसी उपलब्धि पर आपको गर्व महसूस होगा। परिवार के साथ बैठकर पुराने मतभेद दूर करने का मौका मिलेगा और रिश्तों में फिर से वही अपनापन लौट सकता है।

शब्दजाल- 8414

अ	व	र	नो	ए	न्ट्री	स	प	ला	नी	का
धु	है	क	ज	इं	डो	ने	ह	इं	म	ल
म	क्या	दि	ल	ने	क	हा	ड	सा	प	नि
हु	रा	ल	मा	ज	ल	स	रा	न	इ	ही
को	ई	मे	रे	दि	ल	से	पु	छे	क	नि
द	जे	कि	र	क	पा	का	म	न	रि	या
शी	मा	दे	प्या	व	था	य	अ	म	क	ती
द	दे	श	रे	न	प	य	यु	घु	व	ला
स	दि	ल	मो	ले	दा	र	जा	वा	वी	दे
क्षि	ज	ति	ह	हि	द	ह	मा	द	ल	र
त	र	सु	न	मा	स्व	रा	ज	त	र	म

शब्दजाल में ईशा देओल १० फिल्मों के नाम' ढूंढिए.शब्द ऊपर से नीचे,दाएं से बाएं एंव तिरछे हो सकते हैं

नो एन्ट्री, दस, प्यारे मोहन, धुम, युवा, इंसान, अनकही, क्या दिल ने कहा, कोई मेरे दिल से पुछे, काल.

शब्दजाल - 8413 का हल

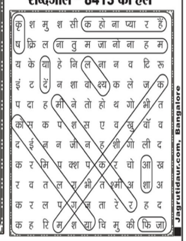

Jagrutidaur.com, Bangalore

फिल्म वर्ग पहेली- 7348

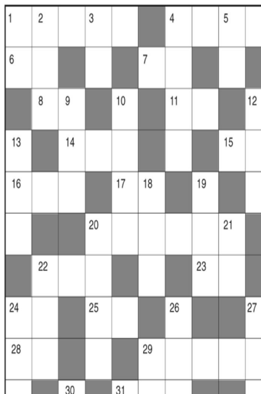

ऊपर से नीचे:-

१. 'नदिया किनारे आआ' गीत वाली संजय दत्त, आफताब, नंदिता की फिल्म-२
२. ऋषिकपूर, माधुरी दीक्षित की 'जाने वो कैसा चोर था' गीत वाली फिल्म-३
३. 'आजकल पाँव जमीं पर' गीत वाली फिल्म-२
४. अक्षय, करीना कपूर, प्रियंका की फिल्म-४
५. 'दिल दिया है तुझे' गीत वाली अतीन भल्ला, संदली सिन्हा की फिल्म-२
९. राहुल बोस, करीना कपूर की 'जाने क्यूं हमको' गीत वाली फिल्म-३
१०. राजकपूर, परवीन की 'आपसा कोई हसीन' गीत वाली फिल्म-२,२
१२. 'तोता मैना की कहानी' गीत वाली शशिकपूर, शबाना की फिल्म-३
१३. मिलिंद सोमण, किरण झवेर की 'जीना है तेरी' गीत वाली फिल्म-३
१८. 'सुलगे हुए हैं' गीत वाली जिमी, इरफान, ऋषिता, नम्रता की फिल्म-३
१९. फिल्म 'अवतार' में राजेश की नायिका?-३
२०. 'नहीं ये हो नहीं सकता' गीत वाली फिल्म-४
२१. अमिताभ, जैकी, कैटरीना, मधु, सीमा की 'आई सी यू बेबी' गीत वाली फिल्म-२
२२. 'रंग और नूर की बारात' गीत वाली सुनीलदत्त, मीना कुमारी की फिल्म-३
२४. नसीर, फारूख शेख, स्मिता की फिल्म-३
२६. 'बोल गोरी बोल' गीत वाली सुनीलदत्त, नूतन की फिल्म-३
२७. शाहरूख, माधुरी की 'तू सामने जब आता है' गीत वाली फिल्म-३
२९. 'हम प्यार करने वाले' गीत वाली फिल्म-२

बायें से दायें:-

१. अमिताभ, जया की 'ये जुल्फ कैसी है' गीत वाली फिल्म-२,१,२
४. 'सीमायें बुलाये तुझे' गीत वाली जे.पी.दत्ता की युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी एक मल्टीस्टारर फिल्म-२,१,१
६. फिल्म 'साया' में नायिका कौन थी-२
७. 'झमका चाँदी दा' गीत वाली मनोज, अरशद, तब्बू, शीबा की फिल्म-२
८. अभिषेक, अंतरा माली की 'बेरंग जिंदगी' गीत वाली फिल्म-२
११. फिल्म 'जीवनमृत्यु' में नायिका थी-२
१४. 'तुम तो परदेसी हो' गीत वाली फराजखान, रानी मुखर्जी की फिल्म-३
१५. अमिताभ, अजय, अक्षय, ऐश्वर्या की 'दिल डूबा' गीत वाली फिल्म-२
१६. 'आज मदहोश हुआ जाये' गीत वाली शशिकपूर, रेखा की फिल्म-३
१७. संजय कपूर, रवीना, अदिति की 'हंसता है हसता' गीत वाली फिल्म-२
२०. 'सनन सनन साय साय हो' गीत वाली गोविंदा, रमैया की फिल्म-४,२
२२. सनी देओल, अमीषा पटेल की 'घर आजा परदेसी' गीत वाली फिल्म-३
२३. 'तू कल चला' गीत वाली संजयदत्त, कुमार गौरव, पूनम ढिल्लों की फिल्म-२
२४. जैकी, सुनील शेट्टी, डिनो, करिश्मा की 'ऐ सुबह तू' गीत वाली फिल्म-२
२५. 'हुस्ने जाना इधर आ' गीत वाली राजेंद्रकुमार, वैजयंती की फिल्म-२
२८. देवआनंद, गीता बाली की 'चांदनी रातें प्यार की' गीत वाली फिल्म-२
२९. 'जिनके पास हाथी घोड़ा' गीत वाली राजकुमार, लीना की फिल्म-२,१,२
३०. जीतेंद्र, जयाप्रदा की 'आईने के सौ टुकड़े' गीत वाली फिल्म-१
३१. 'लड़की जो आए बाजार में' गीत वाली जैकी श्रॉफ, मनीषा की फिल्म-३

फिल्म वर्ग पहेली- 7347

Jagrutidaur.com, Bangalore

दैनिक पंचांग

8 अक्टूबर 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह	स्थिति	लग्नारंभ समय	
सूर्य	कन्या में	तुला	06.39 बजे से
चंद्र	सिंह में	वृश्चिक	08.54 ब.से
मंगल	कर्क में	धनु	11.10 बजे से
बुध	तुला में	मकर	13.15 बजे से
गुरु	कर्क में	कुंभ	15.02 बजे से
शुक्र	तुला में	मीन	16.34 बजे से
शनि	मीन में	मेष	18.05 बजे से
राहु	कुंभ में	वृष	19.45 बजे से
केतु	सिंह में	मिथुन	21.43 बजे से
		कर्क	23.57 बजे से
		सिंह	02.13 बजे से
		कन्या	04.25 बजे से

राहुकाल 1.30 से 3.00 बजे तक

गुरुवार 2026 वर्ष का 281 वा दिन **दिशाशूल** दक्षिण **ऋतु** शरद। **विक्रम संवत्** 2083 **शक संवत्** 1948 **मास** आश्विन (दक्षिण भारत में भाद्रपद) **पक्ष** कृष्ण **तिथि** त्रयोदशी 22.17 बजे को समाप्त। **नक्षत्र** पूर्वाफाल्गुनी 21.20 बजे को समाप्त। **योग** शुक्ल(शुक्र) 00.59 बजे रात्र को समाप्त। **करण** गर 10.44 बजे तदनन्तर वणिज 22.17 बजे को समाप्त। **चन्द्रायु** 24.9 घण्टे **रवि क्रान्ति** दक्षिण 05° 48' **सूर्य** दक्षिणायन **कलि अहर्गण** 1872856 **जूलियन दिन** 2461321.5 **कलियुग संवत्** 5128 **कल्पारंभ संवत्** 1972949128 **सृष्टि ग्रहारंभ संवत्** 1955885128 **वीरनिर्वाण संवत्** 2552 **हिजरी सन्** 1448 **महीना** रवि उस्सानी **तारीख** 26 **विशेष** गुरु प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, कलि युग दिवस।

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
शुभ	05.54 से	07.22 बजे तक	अमृत	05.40 से	07.11 बजे तक
रोग	07.22 से	08.51 बजे तक	चर	07.11 से	08.43 बजे तक
उद्वेग	08.51 से	10.19 बजे तक	रोग	08.43 से	10.15 बजे तक
चर	10.19 से	11.47 बजे तक	काल	10.15 से	11.47 बजे तक
लाभ	11.47 से	01.15 बजे तक	लाभ	11.47 से	01.19 बजे तक
अमृत	01.15 से	02.43 बजे तक	उद्वेग	01.19 से	02.51 बजे तक
काल	02.43 से	04.11 बजे तक	शुभ	02.51 से	04.23 बजे तक
शुभ	04.11 से	05.40 बजे तक	अमृत	04.23 से	05.55 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अत: आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

प्रसंगत: पद की निष्ठा

सिकंदर का सेनापति अपनी योग्यता और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। सिकंदर उसके काम करने के तरीके से बहुत प्रसन्न रहता था। मगर एक बार एक छोटी सी गलती पर वह उससे बेहद नाराज हो गया और उसे सेनापति के पद से हटा कर सूबेदार बना दिया। यह सेना का सबसे छोटा ओहदा था। लेकिन सेनापति ने इस पर कोई नाराजगी नहीं दिखाई और उसने इस निर्णय को भी सहजता से स्वीकार किया। सूबेदार के पद पर भी वह पहले की तरह निष्ठा और समर्पण से कार्य करने लगा। कुछ समय बाद उसे किसी काम से सिकंदर के सामने उपस्थित होना पड़ा। सिकंदर ने उससे पूछा, 'तुम सेनापति से सूबेदार हो गए, मगर मैं तुम्हें पहले की तरह ही खुश और उत्साहित देखता हूं। बात क्या है?' सूबेदार ने कहा, 'श्रीमान, मैं तो पहले से और ज्यादा सुखी हूं। पहले तो सैनिक और सेना के छोटे अधिकारी मुझसे डरते थे, किंतु अब वे मुझसे स्नेह करते हैं और हर बात में मुझसे राय लेते हैं। सही मायनों में उनकी सेवा का अवसर तो मुझे अब मिला है।' इसके बाद सिकंदर ने प्रश्न किया, 'लेकिन बड़े पद से हटने पर तुम्हें अपमान नहीं महसूस होता? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सब तुम पर मन ही मन हंसते होंगे।' यह सुनकर सूबेदार मुस्कराया और बोला, 'श्रीमान बताएं, सम्मान पद में है या मानवता में? उच्च पद पाकर कोई अहंकार में चूर हो जाए और दूसरों को सताए तो वह निंदनीय ही है। सम्मान तो दूसरों की सेवा करने, ईमानदार होने, नम्र व्यवहार करने और कर्तव्यनिष्ठ रहने में है। ऐसा जो करता है वह सुखी और संतुष्ट रहता है। भले ही वह अदना सैनिक हो या सेनापति।' इतना कह सूबेदार ने सिकंदर से विदा ली। सिकंदर सूबेदार के साथ अपने व्यवहार और उसके व्यवहार के बारे में रात भर सोचता रहा। अगले ही दिन उसने सूबेदार को बुलाया, उससे क्षमा मांगी और उसे फिर सेनापति बना दिया।

सूडोकु नवताल- 7657

★★★★★ कठिनतम

		8			4			
1								9
3				2			5	
			1				8	
		5				4		
	7				9			
	6			3				2
9								1
			8			7		

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7656 का हल

6	3	8	5	2	1	4	7	9
7	9	1	4	6	3	5	8	2
2	4	5	7	9	8	6	3	1
9	1	3	2	5	4	8	6	7
4	6	2	8	1	7	9	5	3
5	8	7	6	3	9	1	2	4
3	2	4	1	8	5	7	9	6
8	7	6	9	4	2	3	1	5
1	5	9	3	7	6	2	4	8

शब्द पहेली - 8872

बाएँ से दाएँ

1.सावधान,सचेत-3
3.खूबसूरत-3
5.वचन,प्रतिज्ञा-2
6.हत्या,मर्डर-2
8.तब तक,अवधि में-4
10.चरित्र,लक्षण-3
12.रूस की मुद्रा-3
13.परागकण-2
14.नाखून-2
15.छुटकारा,आजादी-3
17.तट,किनारा-3
19.ईश्वर,भगवान -4
21.अधीन,काबू-2
23.नवीन,नवजात-2
24.लेखनी,पेन-3
25.लाईन,रेखा -3

ऊपर से नीचे

1.हमेशा,सदैव-2
2.विष,जहर-3
3.गर्भ-3
4.नया,नवल-2
5.पुनरागमन-3
7.मस्ती,उछलकूद-3
8.स्वभाव,आदत-4
9.नुकसान,घाटा-2
12.कपोल,गाल-4
15.शान्ति,सन्नाटा-3
16.ताकत,दम,बल-2
18.बोलने का तरीका-3
19.प्रतिज्ञा,वचन-3
20.आज्ञापालन-3
22.वहम,संदेह-2
23.लोहे की तांत-2

शब्द पहेली -8871 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

पालडोंगरी कैप मार्ग की बदहाली देखने पहुंचे एसडीएम, सुधार के दिए निर्देश

पद्मेश न्यूज। लांजी। धान खरीदी शुरू होने से पहले पालडोंगरी कैप तक पहुंचने वाले जर्जर मार्ग की बदहाली को लेकर प्रकाशित खबर का असर सामने आया है। खबर के माध्यम से प्रशासन और संबंधित विभागों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया था कि आगामी धान खरीदी सीजन में इसी मार्ग से दो दर्जन से अधिक गांवों के हजारों किसानों की उपज पालडोंगरी कैप तक पहुंचेगी। इसके बावजूद कैप तक पहुंचने वाला मार्ग लंबे समय से बदहाल स्थिति में था। अब प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। 7 अक्टूबर को लांजी एसडीएम आदित्य नारायण तिवारी ने तहसीलदार संजय बारस्कर के साथ पालडोंगरी कैप का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कैप तक पहुंचने वाले मार्ग की स्थिति को मौके पर देखा और आगामी धान खरीदी के दौरान संभावित परेशानियों को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा की। निरीक्षण के दौरान मार्ग की वास्तविक स्थिति सामने आने के बाद एसडीएम ने पालडोंगरी सरपंच गणेशराम नारनौरे से चर्चा कर कैप स्थल तक पहुंचने वाले रास्ते को दुरुस्त कराने के लिए आवश्यक प्रयास करने के निर्देश दिए।

हर साल मुरुम डालने की खानापूर्ति से अलग अब स्थायी सुधार की जरूरत

उल्लेखनीय है कि पालडोंगरी कैप तक पहुंचने वाला मार्ग लंबे समय से किसानों और परिवहन में लगे वाहनों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। हर वर्ष धान खरीदी का समय नजदीक आने पर मार्ग पर मिट्टी और मुरुम डालकर उसे अस्थायी रूप से आवागमन योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण कुछ ही समय बाद मार्ग फिर गड्ढों और उबड़-खाबड़ स्थिति में पहुंच जाता है। पूर्व में प्रकाशित खबर में भी इसी समस्या को प्रमुखता से उठाते हुए सवाल किया गया था कि जब प्रशासन और संबंधित विभागों को हर वर्ष यह मालूम रहता है कि धान खरीदी के दौरान इस मार्ग से बड़ी संख्या में किसान और परिवहन वाहन गुजरेंगे, तो फिर स्थायी समाधान की दिशा में पहल क्यों नहीं की जाती। धान खरीदी के दौरान पालडोंगरी कैप पर वाहनों का दबाव कई गुना बढ़ जाता है। किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली में अपनी उपज लेकर पहुंचते हैं, वहीं परिवहन में लगे मालवाहक वाहन धान के उठाव के लिए लगातार आवागमन करते हैं। ऐसे में जर्जर मार्ग न केवल आवागमन में परेशानी पैदा करता है, बल्कि वाहनों के फंसने और दुर्घटना की आशंका को भी बढ़ाता है। यही वजह है कि धान खरीदी शुरू होने से पहले मार्ग को दुरुस्त किये जाने की मांग की गई है।

समस्या सामने आते ही मौके पर पहुंचा प्रशासन

इस पूरे घटनाक्रम में एक सकारात्मक पहलू यह भी सामने आया कि समस्या को सामने आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रहने के बजाय मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया। एसडीएम आदित्य नारायण तिवारी द्वारा तहसीलदार के साथ पालडोंगरी कैप पहुंचकर मार्ग की स्थिति देखना और स्थानीय जनप्रतिनिधि से चर्चा कर समाधान की दिशा में पहल करना प्रशासन की सक्रिय कार्यप्रणाली को दर्शाता है। प्रशासनिक व्यवस्था में जब अधिकारी जनसमस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनकी वास्तविक स्थिति जानने के लिए मौके पर पहुंचते हैं, तो छोटी-छोटी समस्याएं बड़ी परेशानी बनने से पहले ही दूर की जा सकती हैं। इससे आम लोगों में भी यह भरोसा बढ़ता है कि उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने के बाद उस पर संज्ञान लिया जाएगा और समाधान की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।

सरपंच ने पंचायत इंजीनियर को दिए निर्देश

एसडीएम द्वारा मौके पर निरीक्षण किए जाने और सरपंच से चर्चा के बाद पालडोंगरी सरपंच गणेशराम नारनौरे ने पंचायत इंजीनियर को मार्ग सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यदि समय रहते मार्ग की मरम्मत और आवश्यक सुधार कार्य पूरा कर लिया जाता है तो आगामी खरीदी सीजन में किसानों को काफी हद तक राहत मिल सकती है। इस पहल से यह भी उम्मीद जगी है कि किसानों को अपनी उपज लेकर कैप तक पहुंचने में अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और धान के परिवहन एवं भंडारण की व्यवस्था भी सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी।

शासकीय महाविद्यालय में 40 विद्यार्थियों ने इको फ्रेंडली बैगमेकिंग का प्राप्त किया प्रशिक्षण

पद्मेश न्यूज। लांजी। शासकीय महाविद्यालय लांजी में विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित एक माह के 'इको फ्रेंडली बैगमेकिंग' प्रशिक्षण का सोमवार को समापन हुआ। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के तत्वावधान में यह प्रशिक्षण 1 सितंबर से 5 अक्टूबर तक संचालित किया गया। प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को पर्यावरण हितैषी बैग बनाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। समापन समारोह की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. गौतमा कठाने ने की। कार्यक्रम का संचालन स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के प्रभारी महेश ढोक ने किया।

प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को प्रशिक्षक ममता उरकुड़े द्वारा बैग निर्माण से संबंधित विभिन्न तकनीकों एवं उपयोगी कौशल का प्रशिक्षण दिया गया। समापन अवसर पर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले 40 छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्राचार्य डॉ. गौतमा कठाने सहित उपस्थित शिक्षकों ने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण से प्राप्त कौशल का उपयोग आत्मनिर्भर बनने और रोजगार के अवसर तलाशने में करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सभी प्रतिभागियों के उज्ज्वल एवं स्वावलंबी भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में सहायक प्राध्यापक डॉ. कांता वर्मा, डॉ. सपना सेंड्रे, महेंद्र कुमार तलवारे एवं रितेश सोनवाने सहित महाविद्यालय के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

पितरों के स्मरण में श्रद्धा से हो रहे श्राद्ध कर्म, 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या पर समापन

द्वादशी और त्रयोदशी श्राद्ध पर घर-घर तर्पण, दान-पुण्य व ब्राह्मण भोज का क्रम जारी

पद्मेश न्यूज। लांजी। पितरों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का विशेष पर्व पितृपक्ष इन दिनों क्षेत्र में धार्मिक आस्था और श्रद्धा के वातावरण में मनाया जा रहा है। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने दिवंगत पूर्वजों का स्मरण करते हुए उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और दान-पुण्य के कार्य कर रहे हैं। घरों में विधि-विधान से श्राद्ध कर्म के साथ पितरों को जल अर्पित कर तर्पण किया जा रहा है। कई परिवारों द्वारा ब्राह्मण भोज और जरूरतमंदों को भोजन कराने के साथ यथाशक्ति दान-पुण्य भी किया जा रहा है। पितृपक्ष के अंतिम दिनों में श्राद्ध कर्म को लेकर धार्मिक गतिविधियां और बढ़ गई हैं। 7 अक्टूबर को द्वादशी श्राद्ध तथा 8 अक्टूबर को त्रयोदशी श्राद्ध के अवसर पर विभिन्न परिवारों में अपने पूर्वजों के निमित्त धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। इसके बाद 9 अक्टूबर को चतुर्दशी श्राद्ध और 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ पितृपक्ष का समापन होगा।

सर्वपितृ अमावस्या पर ज्ञात-अज्ञात पितरों का स्मरण

सर्वपितृ अमावस्या को पितृपक्ष की महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है। जिन पूर्वजों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती अथवा किसी कारणवश निर्धारित तिथि पर श्राद्ध नहीं हो पाता, उनके निमित्त इस दिन श्राद्ध और तर्पण करने की परंपरा है। इसी कारण अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में लोग अपने ज्ञात-अज्ञात पूर्वजों का स्मरण करते हुए श्राद्ध कर्म और दान-पुण्य करते हैं।

पीढ़ियों को संस्कारों से जोड़ता है पितृपक्ष

पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार की नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के संघर्ष, संस्कार और योगदान से परिचित कराने का अवसर भी माना जाता है। सनातन परंपरा में मान्यता है कि जिस चंद्र तिथि को किसी परिजन का निधन हुआ हो, पितृपक्ष में उसी तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है। इसी मान्यता के अनुसार लांजी क्षेत्र में सर्वसमाज के परिवार अपनी-अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार पितरों का स्मरण कर रहे हैं। पितृपक्ष के शेष दिनों में भी घरों में तर्पण, श्राद्ध कर्म, भोजन और दान-पुण्य का क्रम जारी रहेगा। 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ इस धार्मिक पर्व का समापन होगा।

शासकीय महाविद्यालय लांजी की छात्रा त्रिवेणी ने संभाग स्तरीय चेस में किया शानदार प्रदर्शन, अब जयपुर में राष्ट्रीय स्तर पर दिखाएंगी प्रतिभा

पद्मेश न्यूज। लांजी। शासकीय महाविद्यालय लांजी की छात्रा त्रिवेणी बढ़ाई ने शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए महाविद्यालय और लांजी क्षेत्र का नाम रोशन किया है। पांढुर्ना में आयोजित संभाग स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद त्रिवेणी का चयन ऑल इंडिया चेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है। राष्ट्रीय स्तर की यह प्रतियोगिता आगामी दिनों में जयपुर में आयोजित की जाएगी। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में त्रिवेणी ने अपनी रणनीतिक सोच, एकाग्रता और खेल कौशल का प्रभावी प्रदर्शन किया। लगातार बेहतर प्रदर्शन के चलते उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जगह बनाई। अब जयपुर में होने वाली ऑल इंडिया चेस प्रतियोगिता में वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी।

डॉ. ललित कामडे के मार्गदर्शन में निखारा खेल

त्रिवेणी की इस उपलब्धि के पीछे उनकी मेहनत के साथ नियमित अभ्यास और मार्गदर्शन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्हें डॉ. ललित कामडे का विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उनके निर्देशन में त्रिवेणी ने शतरंज की बारीकियों को समझते हुए अपनी खेल क्षमता को लगातार बेहतर किया।

महाविद्यालय परिवार ने दी शुभकामनाएं

त्रिवेणी बढ़ाई के ऑल इंडिया चेस प्रतियोगिता के लिए चयन से शासकीय महाविद्यालय लांजी में खुशी का माहौल है। महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों सहित महाविद्यालय परिवार ने त्रिवेणी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। सभी ने जयपुर में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। त्रिवेणी की यह उपलब्धि लांजी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक है। ग्रामीण अंचल से निकलकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता तक पहुंचना उनकी मेहनत और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

बी पैक्स पालडोंगरी में एसडीएम-तहसीलदार का औचक निरीक्षण

रिकॉर्ड, कार्यप्रणाली और किसानों से जुड़ी व्यवस्थाओं की ली जानकारी, दिए आवश्यक निर्देश

पद्मेश न्यूज। लांजी। बी पैक्स पालडोंगरी में बुधवार को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आदित्य नारायण तिवारी एवं तहसीलदार संजय बारस्कर ने औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों के अचानक समिति परिसर पहुंचने से कर्मचारियों में सक्रियता नजर आई। इस दौरान उन्होंने समिति में संचालित विभिन्न कार्यों और व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने समिति के रिकॉर्ड, कार्यालयीन कार्यप्रणाली, किसानों से संबंधित व्यवस्थाओं तथा उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कर्मचारियों से विभिन्न कार्यों की प्रगति के संबंध में चर्चा कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की और मौके पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। एसडीएम एवं तहसीलदार ने समिति की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित एवं सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों और आमजन से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता तथा समयबद्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों ने कहा कि समिति के कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। किसानों एवं अन्य हितग्राहियों को शासन की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ नियमानुसार समय पर उपलब्ध कराया जाए। अधिकारियों ने कर्मचारियों को रिकॉर्ड एवं कार्यालयीन कार्यों को व्यवस्थित रखने के साथ ही लंबित कार्यों का समय पर निराकरण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि समिति से जुड़े कार्य सीधे किसानों और आमजन के हितों से जुड़े हैं, इसलिए कार्यप्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है। औचक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए व्यवस्थाओं में लगातार सुधार करने के लिए कहा। निरीक्षण के बाद समिति में कार्यरत कर्मचारियों में भी अपने दायित्वों को लेकर सक्रियता देखने को मिली।

सेवा ज्योति कलश के अंतर्गत पीजी कॉलेज में प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन का सीधा प्रसारण देखा गया

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालाघाट में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा ज्योति कलश से संबंधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अशोक कुमार मराठे के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में कक्ष क्रमांक 02 में किया गया, जिसमें महाविद्यालय के 35 विद्यार्थियों ने सहभागिता की। इस दौरान विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का सीधा प्रसारण देखा एवं उनके विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। कार्यक्रम का संयोजन डॉ. गजानन कटरे एवं डॉ. डुलेश्वरी टेम्भरे द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉ. एम.एस. मरकाम, डॉ. नाजली कुरैशी सहित महाविद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को राष्ट्रहित, सेवा भावना, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं जनकल्याणकारी गतिविधियों के प्रति जागरूक करना था। प्रधानमंत्री के उद्बोधन से प्रेरित होकर विद्यार्थियों ने समाज एवं राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने तथा सेवा और समर्पण की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प लिया। इस आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध एवं जनसेवा की भावना को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया।

लांजी में "पद्मेश"
इंटरनेट (ब्राडबैंड) कनेक्शन के लिये संपर्क करें
Mo. 8319969927

धान उत्पादक किसानों को बोनस दें - सांसद प्रफुल पटेल

दिवाली से पहले सरकारी धान खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग - किसानों की समस्याओं पर मुंबई में बैठक

रवि ठकरानी

पदमेश न्यूज। गोंदिया। नागपुर संभाग में न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदी योजना के तहत संचालित सरकारी व सहकारी धान खरीदी केंद्रों की समस्याओं, सीएमआर भराई, भंडारण और किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर मुंबई स्थित अन्न, नागरी आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण मंत्रालय में मंत्री छगन भुजबल की उपस्थिति में बैठक हुई. बैठक में सांसद प्रफुल पटेल ने गोंदिया-भंडारा जिले के धान उत्पादक किसानों की समस्याएं उठाईं।

सांसद पटेल ने कहा कि संकट में घिरे धान उत्पादक किसानों को बोनस दिलाने के लिए वे लगातार सरकार के समक्ष मांग रखते आए हैं. विधानसभा के अधिवेशन में भी सरकार की ओर से धान पर बोनस देने का आश्वासन दिया गया था. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर किसानों को बोनस देने का आग्रह करेंगे. पटेल ने दिवाली से पहले सरकारी धान खरीदी केंद्र तत्काल शुरू करने तथा खरीदी किए गए धान की समय पर उठाव व्यवस्था करने की मांग की. उन्होंने ई-पीक पंजीयन में किसानों को परेशानी न हो और धान खरीदी प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन को सतर्कता से काम करने को कहा. बैठक में विधायक राजकुमार बडोले, विधायक विजय रहांगडाले, विधायक राजू कारेमोरे सहित विदर्भ के अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

2001 से लंबित कमीशन का मुद्दा उठा

बैठक में महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास मंडल (झ्ष्ठ्ट) द्वारा भंडारा और गोंदिया जिले में की गई धान खरीदी का वर्ष 2001 से 2014 तक का लंबित कमीशन तत्काल जारी करने की मांग भी रखी गई. इसके अलावा सरकारी धान खरीदी केंद्रों और खरीदी संस्थाओं की तकनीकी व भौतिक समस्याओं पर भी चर्चा हुई।

BEAM पोर्टल शुरू करने की मांग

सांसद राजेंद्र जैन ने ऑनलाइन बैठक में नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर कर्जमुक्ति योजना का लाभ जल्द देने की मांग की. उन्होंने कहा कि किसानों के पंजीयन के लिए इस्तेमाल होने वाला क्ष्ष्रू पोर्टल बंद होने से किसानों को परेशानी हो रही है. इसलिए पोर्टल तत्काल शुरू किया जाए. जैन ने भंडारण क्षमता की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि करीब 70 प्रतिशत धान खुले में रखने की स्थिति बन रही है. उन्होंने गोदामों की संख्या और क्षमता बढ़ाने तथा गोंदिया-भंडारा जिले में धान खरीदी केंद्र जल्द शुरू करने की मांग की।

हाईवे पर हादसे रोकने तत्काल उपाय करें - राजेंद्र जैन

पदमेश न्यूज। गोंदिया। जिले के गोंदिया-तिरोड़ा और गोंदिया-बालाघाट राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधूरे सड़क कार्यों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है. पिछले एक महीने में इन मार्गों पर कई दुर्घटनाएं होने और इनमें 10 से 12 लोगों की जान चली गई. सांसद राजेंद्र जैन ने इसे गंभीरता से संज्ञान लिया. उन्होंने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर दुर्घटनाओं पर तत्काल रोक लगाने के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता शास्त्री सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे. सांसद जैन ने रावणवाड़ी-नागरा तथा तिरोड़ा मार्ग पर हुई दुर्घटनाओं का उल्लेख करते हुए सड़क सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की. विजयनगर नाला परिसर में सड़क पर बने गड्ढों को जेसीबी की मदद से तत्काल भरने तथा दुर्घटनाओं की आशंका वाले स्थानों पर सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

उत्तम सावजी के पास संकरा मोड़ बना जोखिम

जैन ने कहा कि तिरोड़ा मार्ग पर उत्तम सावजी के पास सड़क का घुमावदार और संकरा हिस्सा दुर्घटनाओं की दृष्टि से जोखिमपूर्ण है. वहीं, गोंदिया-बालाघाट मार्ग पर कई स्थानों पर सड़क निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है. कुछ जगह नालियों के लिए खुदाई कर दी गई है, लेकिन वहां काम चल रहा होने की सूचना देने वाले पर्याप्त संकेतक नहीं लगाए गए हैं. इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सांसद जैन ने कहा कि 11 अक्टूबर से नवरात्रि उत्सव शुरू हो रहा है. इस दौरान दोनों मार्गों पर यातायात और भी बढ़ने की संभावना है. इसे देखते हुए उन्होंने नवरात्रि से पहले प्रमुख स्थानों के गड्ढे भरने, दिशादर्शक बोर्ड लगाने तथा जहां सड़क का काम चल रहा है, वहां स्पष्ट सूचना फलक और सुरक्षा रिबन लगाने के निर्देश दिए।

621 स्थानों पर विराजेंगी आदिशक्ति, 627 जगह शारदा माता

पदमेश न्यूज। गोंदिया। आदिशक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रोत्सव 11 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है. घर-घर घटस्थापना के साथ जिले में सार्वजनिक दुर्गोत्सव मंडलों की तैयारियां भी अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. जिले में करीब 621 स्थानों पर सार्वजनिक मंडलों द्वारा आदिशक्ति की स्थापना, जबकि 627 स्थानों पर शारदा माता की प्रतिमाएं विराजमान होंगी. नौ दिनों तक धार्मिक आयोजनों के साथ विभिन्न सामाजिक उपक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

दुर्गोत्सव को लेकर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक मंडलों द्वारा आकर्षक पंडाल, विद्युत रोशनी और विभिन्न विषयों पर आधारित सजावट तैयार की जा रही है. कई मंडलों के पंडालों का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है. नवरात्र के दौरान विभिन्न स्थानों पर रास-दांडिया और गरबा कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था

नवरात्रोत्सव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार किया है. सुरक्षा के लिए 4 दंगा नियंत्रण दल, 36-36 जवानों वाले 2 त्वरित कार्रवाई दल, 10 बीट मार्शल और 2 निर्भया दल तैनात रहेंगे. इसके अलावा चार उपविभागीय पुलिस अधिकारियों के अधीन एक-एक ट्रैकिंग फोर्स तथा पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के अधीन एक-एक ट्रैकिंग फोर्स सहित कुल 6 ट्रैकिंग फोर्स तैयार किए गए हैं. इनमें 6 अधिकारी और 50 कर्मचारी शामिल हैं. दो सी-60 दल तथा बम खोजी व नाशक दल भी तैनात रहेगा. सुरक्षा व्यवस्था में 320 पुरुष और 55 महिला होमगार्ड भी लगाए जाएंगे।

मूर्तियों को अंतिम रूप

नवरात्रोत्सव में अब कुछ ही दिन शेष रहने से मूर्तिकारों ने दुर्गा और शारदा माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. प्रतिमाओं की रंगाई-पुताई और सजावट का काम तेजी से चल रहा है. मूर्तिकार आकर्षक प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.

16 थानों की पुलिस रहेगी अलर्ट

नौ दिवसीय उत्सव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिले के 16 पुलिस थानों के अधिकारी और कर्मचारी अलर्ट रहेंगे. शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बंदोबस्त लगाया जाएगा. करीब 2 हजार से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे.

32 स्थानों पर गरबा-दांडिया

नवरात्रोत्सव के दौरान धार्मिक आयोजनों के साथ युवाओं में गरबा और दांडिया का उत्साह भी देखने को मिलेगा. शहर सहित जिले में करीब 32 स्थानों पर गरबा-दांडिया कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. सार्वजनिक मंडलों के अलावा विभिन्न मैदानों में भी आयोजन की तैयारी की जा रही है.

खराब सड़क में फंसा 12 चक्का ट्रक

अर्जुनी मोरगांव-महागांव-बोरी मार्ग बदहाल - बस सेवा बंद होने से विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ी

पदमेश न्यूज। गोंदिया। अर्जुनी मोरगांव से महागांव, बोरी और मांडोखाल को जोड़ने वाले मार्ग की बदहाल स्थिति अब वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है. सोमवार सुबह करीब 10 बजे सड़क की खराब स्थिति के कारण 12 चक्का ट्रक क्र. एमएच 27 - बीएक्स 6654 सड़क से नीचे उतरते ही फंस गया. गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया।

जानकारी के अनुसार, ट्रक महागांव से चावल लेकर बोरी स्थित सोंदरकर राइस मिल की ओर जा रहा था. इसी दौरान सामने से स्कूल बस आने पर उसे रास्ता देने के लिए चालक ने ट्रक को सड़क के किनारे नीचे उतारा. सड़क के किनारे की खराब और दलदली स्थिति के कारण ट्रक फंस गया. काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया.

अर्जुनी मोरगांव-महागांव-बोरी-मांडोखाल मार्ग खराब होने के कारण मोरगांव से महागांव मार्ग पर बस फेरियां भी बंद हैं. फिलहाल बसें ईटखेडा मार्ग से संचालित की जा रही हैं. निलज, मालकनपुर और माहुरकुडा से महागांव आने वाले विद्यार्थियों के लिए नियमित आवागमन का कोई विकल्प नहीं बचा है. कई विद्यार्थी निजी साधनों से आने-जाने को मजबूर हैं. ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क की केवल डागडुजी करने के बजाय अर्जुनी मोरगांव से मांडोखाल तक मार्ग का नए सिरे से निर्माण किया जाए, ताकि नागरिकों और विद्यार्थियों को राहत मिल सके।

जल जीवन मिशन की 250 से अधिक योजनाएं अधूरी

पदमेश न्यूज। गोंदिया। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन की जिले में रफ्तार धीमी पड़ गई है. वर्ष 2021-22 और 2022-23 में जिले में करीब 494 योजनाओं को मंजूरी दी गई थी. इनमें से आधे से अधिक योजनाएं साढ़े चार साल बाद भी अधूरी होने का दावा किया जा रहा है. परिणामस्वरूप कई गांवों के लोगों को आज भी पानी के लिए भटकना पड़ रहा है।

योजनाओं की निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित गांवों में जिला परिषद पदाधिकारियों और सदस्यों के बड़े-बड़े बैनर लगाए गए तथा धूमधाम से भूमिपूजन समारोह भी आयोजित किए गए थे. लेकिन भूमिपूजन के बाद काम अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सका. कई स्थानों पर पानी के स्रोत की पर्याप्त जांच किए बिना पाइपलाइन बिछाने के लिए गांव की अच्छी सड़कों को खोद दिया गया. वहीं, कुछ गांवों में पानी की टंकियां बनकर तैयार होने के बावजूद उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है. बताया जाता है कि विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों की संख्या कम होने के कारण कुछ ठेकेदारों के पास एक साथ पांच-छह योजनाओं का काम चला गया. इनमें कई निविदाएं कम दर पर मंजूर हुई थीं. काम मिलने के बाद कुछ ठेकेदारों ने उप-ठेकेदारों के माध्यम से काम शुरू किया, लेकिन बाद में अनेक स्थानों पर काम अधूरा रह गया. ग्रामीणों द्वारा काम की स्थिति के बारे में पूछताछ करने पर कई बार केंद्र सरकार से निधि उपलब्ध नहीं होने के कारण काम बंद होने की जानकारी दिए जाने की बात सामने आई है. लेकिन, योजनाएं अधूरी रहने से इसका सीधा असर ग्रामीणों की पेयजल सुविधा पर पड़ रहा है।

केंद्र-राज्य से निधि उपलब्ध कराने की मांग

पूर्व जिला परिषद सदस्य गंगाधर परशुरामकर ने कहा कि निर्धारित अवधि में काम पूरा नहीं होने के कारण केंद्र सरकार की ओर से राज्य के हिस्से की निधि जारी नहीं होने की चर्चा है. इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से जल जीवन मिशन की सभी अपूर्ण योजनाओं के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराने, अधूरे काम तत्काल पूरे करने तथा प्रत्येक पात्र गांव में नियमित शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है.

दो युवकों ने घड़ी व नकद लुटा

पदमेश न्यूज। गोंदिया। शहर थाने के तहत शास्त्री वार्ड स्थित आयरी हॉटेल के पास दो युवकों ने एक युवक के साथ विवाद कर उसकी घड़ी व नकद लुट लिया. जानकारी के अनुसार, गणेशनगर निवासी फिर्यादी अनुज रमेंद्र जायस्वाल (29) के साथ संजयनगर निवासी आरोपी गुरु राजाराम पटले (33) व विक्की राधेश्याम सूर्यवंशी (35) ने शास्त्री वार्ड स्थित आयरी हॉटेल के पास विवाद कर तु अपने आपको क्या समझता है, तुझे चिर दुंगा, जान से मार दुंगा, तेरी हॉटेल को जला दुंगा ऐसा कहते हुए गालीगलौज कर धमकी दी. साथ ही फिर्यादी 45 हजार 500 रु. कीमत की घड़ी व जेब से 4 हजार 500 रु. लुट लिया. फिर्यादी की शिकायत पर शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच सहायक पुलिस निरीक्षक संदीप मडावी कर रहे हैं।

सातगांव के चिकित्सा अधिकारी को निलंबित करने की सिफारिश

जिप सदस्य वंदना काले ने सीईओ व जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा पत्र

पदमेश न्यूज। गोंदिया। सालेकसा (त.सं). तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सातगांव के चिकित्सा अधिकारी डा. प्रशांत तेलसे को निलंबित करने की सिफारिश जिला परिषद सदस्य वंदना काले ने की है. उन्होंने इस संबंध में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र सौंपकर विभागीय जांच कराने की मांग की है.

पत्र में काले ने आरोप लगाया है कि डा. तेलसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्यालय में नहीं रहते और नागपुर से आना-जाना करते हैं. इसके अलावा ओपीडी के दौरान वे स्वयं मरीजों की जांच के लिए उपस्थित नहीं रहते तथा अन्य उपकेंद्रों के चिकित्सकों को मरीजों की जांच के लिए बुलाया जाता है. शिकायत मिलने के बाद काले ने ओपीडी के समय स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया, जहां डा. तेलसे अनुपस्थित मिले. काले ने पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि चिकित्सा अधिकारी की गैरमौजूदगी के कारण मरीजों को अपेक्षित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं. उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में पुरानी लोहे की खिड़कियों व ग्रिल की कथित रूप से बिना नीलामी बिक्री, निर्माण कार्य में हस्तक्षेप तथा ठेकेदार पर दबाव बनाने जैसे मामलों की भी जांच की मांग की है. काले ने संबंधित मामलों की विभागीय जांच कर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई तथा डा. तेलसे को तत्काल निलंबित करने की सिफारिश की है. पत्र की प्रतियां जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्वास्थ्य सभापति को भी दी गई हैं।

बूचड़खाने ले जाए जा रहे 10 मवेशी पकड़े

पदमेश न्यूज। गोंदिया। बूचड़खाने ले जाए जा रहे 10 मवेशियों से भरे बोलेरो पिकअप वाहन को डुग्गीपार पुलिस ने 6 अक्टूबर की तड़के कोहमारा में पकड़ा. कार्रवाई में वाहन समेत कुल 6 लाख रु. का माल जब्त किया गया. पुलिस को देखते ही वाहन में सवार चालक और उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की ओर फरार हो गए।

जानकारी के अनुसार, रात की गश्त के दौरान पुलिस नायक रामटेके को कोलारगांव-कोहमारा मार्ग से मवेशियों के अवैध परिवहन की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी की. तड़के करीब 2.45 बजे कोलारगांव से नवेगांवबांध मार्ग होते हुए कोहमारा की ओर जा रहे बोलेरो क्र. एमएच 40 - सीटी 5947 को रोकने का प्रयास किया गया. कुछ दूरी आगे जाकर चालक ने वाहन रोका. इसी दौरान वाहन से दो लोग उतरकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए खेत की ओर फरार हो गए. वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 10 मवेशियां मिली. पुलिस के अनुसार, मवेशियों को पर्याप्त जगह, चारा-पानी और आवश्यक देखभाल के बिना वाहन में ले जाया जा रहा था. कार्रवाई में करीब 5 लाख रु. कीमत का बोलेरो पिकअप तथा 1 लाख रु. कीमत के मवेशी सहित कुल 6 लाख रु. का माल जब्त किया गया. पुलिस सिपाही उदेभान रुखमोडे की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

10 लाख दहेज की मांग, शादी तोड़ने की धमकी

पदमेश न्यूज। गोंदिया। शादी के लिए 10 लाख रु. दहेज की मांग करने तथा रकम नहीं देने पर शादी तोड़ने की धमकी देकर युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में रामनगर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. 26 वर्षीय लड़की की शिकायत पर पार्थ कॉलोनी, कुड़वा निवासी अनमोल देवसिंग नागपुरे (29), देवसिंग जयपास नागपुरे (61), मोहिनी देवसिंग नागपुरे (53) व सांज देवसिंग नागपुरे (21) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार, फिर्यादी युवती और अनमोल नागपुरे का 9 अप्रैल 2026 को सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार विवाह तय हुआ था. आरोप है कि 7 सितंबर को शादी के कार्यक्रमों को लेकर युवती को बार-बार मानसिक रूप से परेशान किया गया. इसी दौरान चारों आरोपियों ने शादी के लिए 10 लाख रु. दहेज की मांग की और रकम नहीं देने पर शादी तोड़ने की धमकी दी. शिकायत में युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे और उसके परिवार के सदस्यों को अपमानजनक शब्द कहकर धमकाया गया तथा समाज में बदनाम करने का प्रयास किया गया. शिकायत के आधार पर रामनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच पुलिस उपनिरीक्षक भाग्यश्री चव्हाण कर रही हैं।

लॉन बुकिंग को लेकर भी बदला प्लान

शिकायत के अनुसार, शादी के कार्यक्रम के लिए पहले मयूर लॉन को 23, 24 और 25 नवंबर 2026 के लिए बुक किया गया था और 10 हजार रु. अग्रिम दिए गए थे. बाद में लड़के की मां को लॉन पसंद नहीं आने पर बुकिंग रद्द कर दी गई, लेकिन अग्रिम राशि वापस नहीं मिली. इसके बाद विशाल लॉन में 25 और 26 नवंबर के लिए 10 हजार रु. अग्रिम देकर बुकिंग की गई. आगे 24 नवंबर को अन्य बुकिंग होने की जानकारी मिलने पर योजना में बदलाव किया गया. सगाई के लिए रामदेवरा लॉन को 5 हजार रु. अग्रिम देकर बुक किया गया. लेकिन, बाद में पंडित द्वारा उस तारीख को लड़के की जान को खतरा होने की बात कहे जाने का कारण बताते हुए शादी की तारीख फरवरी 2027 तक आगे बढ़ाने की बात शिकायत में कही गई है।

खेत से 19,300 रु. का माल चोरी

पदमेश न्यूज। गोंदिया। रावणवाड़ी थाने के तहत पांजरा खेत परिसर से अज्ञात व्यक्ति ने सौर पंप के केबल व बिजली अरेस्ट चुरा लिया. जिसकी कीमत 19 हजार 300 रु. बताई गई है. जानकारी के अनुसार, पांजरा निवासी फिर्यादी गजानन दौलत मस्करे (51) के खेत से सौर पंप का 6 हजार 700 रु. कीमत का 100 फुट केबल व 3 हजार रु. कीमत का बिजली अरेस्ट साथ ही फिर्यादी के बाजू के खेत मालिक कोतिक साहेबलाल माहुले के खेत से 1 हजार 900 रु. कीमत का 45 फुट केबल व 3 हजार रु. कीमत का बिजली अरेस्ट, कमलेश प्यारेलाल माहुले के खेत से 1 हजार रु. कीमत का 20 फुट केबल, पांढुरंग रघुमानकर के खेत से 2 हजार 800 रु. कीमत का 40 फुट केबल ऐसा कुल 19 हजार 300 रु. का माल चुरा लिया. फिर्यादी की शिकायत पर रावणवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच हवलदार बर्वे कर रहे हैं.

चाकू लेकर घुम रहे युवक को पकड़ा

पदमेश न्यूज। गोंदिया। शहर थाने के तहत ग्राम भीमघाट के आगे पांगोली नदी रास्ते पर यादव चौक निवासी निखिल संजय मेश्राम (19) को चाकू लेकर घुमते हुए पकड़ा गया. फिर्यादी सहायक पुलिस निरीक्षक वैभव गेडाम की शिकायत पर शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच हवलदार कमलेश शहारे कर रहे हैं.

घर के पीछे उगाया गांजा, 97 पौधे जब्त

1.62 लाख रु. कीमत का 3.255 किलो गांजा जब्त

पदमेश न्यूज़। गोंदिया। चिचगढ़ थाना क्षेत्र के धमदीटोला में पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए घर के पीछे स्थित बाड़ में गांजे की खेती का मामला उजागर किया है. पुलिस ने मौके से गांजे के छोटे-बड़े कुल 97 पौधे जब्त किए. जब्त गांजे का वजन 3.255 किलो बताया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख 62 हजार 750 रु. बताई गई है।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि धमदीटोला/मिसीपीरी निवासी आत्माराम मधो माडावी (54) ने अपने घर के पीछे बाड़ में गांजे के पौधे लगा रखे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर जांच की. इस दौरान बाड़ में गांजे के 97 पौधे लगे हुए मिले. पुलिस ने सभी पौधों को जब्त कर लिया है. मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है तथा अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया जारी होने की जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है. यह कार्रवाई सहायक पुलिस निरीक्षक जनार्दन हेगडकर, पुलिस उपनिरीक्षक गव्हाणे, पुलिस उपनिरीक्षक वासुदेव, सहायक फौजदार ज्ञानिराम राऊत, कानपुरिया ने की।

घर के पीछे गांजे की खेती से खलबली

रहवासी घर के पीछे ही गांजे की खेती किए जाने का मामला सामने आने से क्षेत्र में खलबली मच गई है. चिचगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध गांजे की खेती और बिक्री करने वालों में भी हड़कंप मचा है.

खाड़ीपार में तेंदुए का आतंक

दो बकरियों का किया शिकार - पशुपालकों में दहशत

पदमेश न्यूज। गोंदिया। गोरेगांव तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत खाड़ीपार परिसर में तेंदुए ने गोठे में घुसकर बकरियों पर हमला कर दिया. हमले में दो बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य बकरियां गंभीर रूप से घायल हो गईं. घटना 6 अक्टूबर को सामने आने के बाद क्षेत्र के पशुपालकों और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, खाड़ीपार निवासी टोपशिंग पंधरे ने अपने घर से लगे गोठे में बकरियां बांधकर रखी थीं. सोमवार रात परिसर में घात लगाए बैठे तेंदुए ने गोठे में प्रवेश कर बकरियों पर हमला कर दिया. मंगलवार तड़के पंधरे ने बकरियों को देखने पहुंचे तो दो बकरियां मृत मिलीं, जबकि दो बकरियां घायल अवस्था में पड़ी थीं. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति देखी. ग्रामीणों के अनुसार, खाड़ीपार क्षेत्र में इससे पहले भी वन्यजीवों की आवाजाही देखी गई है. तेंदुए की मौजूदगी से रात के समय घरों से बाहर निकलने में भी लोग सतर्कता बरत रहे हैं. ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के साथ ही तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ट्रैप कैमरे लगाने की मांग की है. साथ ही तेंदुए को पकड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने तथा प्रभावित पशुपालक को नियमानुसार आर्थिक मुआवजा देने की मांग की गई है.

घर के आगे से मोटरसाइकिल चोरी

पदमेश न्यूज। गोंदिया। ग्रामीण थाने के तहत तुमखेड़ा (खुर्द) निवासी फिर्यादी महेंद्र अशोक बावने (28) के घर के आगे रखी शाईन मोटरसाइकिल को अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया. जिसकी कीमत 50 हजार रु. बताई गई है. फिर्यादी की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच हवलदार दसरिया कर रहे हैं।

फेयरवेल मैच के दौरान अर्जेंटीना की जर्सी में भावुक हुए...

मेसी की विजयी विदाई, पेनल्टी पर दागा अपने करियर का आखिरी गोल

ब्यूनस आयर्स,एजेंसी। फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ियों में शुमार लियोनेल मेसी के लिए अर्जेंटीना की नेशनल टीम की जर्सी में उनका आखिरी मुकाबला ऐतिहासिक उत्सव बन गया। ब्यूनस आयर्स के एस्टाडियो मोनुमेंटल स्टेडियम में बेनिन के खिलाफ खेले गए इस फेयरवेल फ्रेंडली मुकाबले में पूरा स्टेडियम नीले और सफेद रंगों में रंगा नजर आया, जहां हजारों फैंस अपने चहेते नंबर 10 को आखिरी बार देश के लिए खेलते देखने पहुंचे थे। इस खास मौके पर कोपा अमेरिका के बाद इंटरनेशनल संन्यास ले चुके एंजेल डि मारिया और फ्रांस के पूर्व दिग्गज स्ट्राइकर डेविड ट्रेजेगेट जैसी हस्तियां भी स्टैंड्स में मेसी को विदाई देने के लिए मौजूद थीं। मैच की शुरूआत से ही मेसी ने अपने चिर-परिचित अंदाज में खेल को नियंत्रित किया। 10वें मिनट में पूरा स्टेडियम और दोनों टीमों के खिलाड़ी उठकर खड़े हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मेसी के शानदार करियर को सलाम किया। हाफ-टाइम के बाद मेसी की बेहतरीन फ्री-किक पर अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे निकोलस ओटामेंडी ने शानदार गोल करके अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद निको पाज ने गोल दागकर स्कोर 2-0 कर दिया। 69वें मिनट में अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली। 39 साल के मेसी ने ठंडे दिमाग से गेंद को टॉप-राइट कॉर्नर में दागकर स्कोर 3-0 कर दिया। गोल होते ही पूरी टीम ने अपने कप्तान को हवा में उठाकर इस ऐतिहासिक पल का जश्न मनाया।

दर्शकों का भरपूर प्यार मिला, भावुक हुए मेसी- आंखों से छलके आंसू

मुकाबले से ठीक पहले स्टेडियम में एक विशालकाय 10 नंबर की जर्सी प्रदर्शित की गई, जिस पर धन्यवाद लिखा हुआ था। जब मेसी अपने बेटों थियागो, माटेओ और सिरो के साथ मैदान पर आए, तो पूरा मोनुमेंटल स्टेडियम आतिशबाजी और नारों से गूंज उठा। राष्ट्रगान के बजते ही मेसी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और बेहद भावुक हो गए। उनके साथ खड़े हेड कोच लियोनेल स्कालोनी और निकोलस ओटामेंडी भी इस ऐतिहासिक क्षण में अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सके।

एक युग का अंत, बिना किसी शिकायत के विदाई

मैच के अंतिम पलों में मेसी के पास अपना दूसरा गोल दागने और फ्री-किक से जादुई अंत करने के मौके मिले, लेकिन गेंद गोलपोस्ट के ऊपर से निकल गई। अंतिम सीटी बजते ही पूरा मोनुमेंटल स्टेडियम अपने सबसे बड़े नायक के नाम के नारे लगाने लगे। एक पेनल्टी गोल, एक असिस्ट, आंखों में आंसू और देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने वाले लियोनेल मेसी ने आखिरकार अपनी राष्ट्रीय टीम अर्जेंटीना को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।

21 साल बेमिसाल: 208 मैच, 126 गोल और 68 असिस्ट

मेसी ने अर्जेंटीना के लिए इंटरनेशनल फुटबॉल में अपना डेब्यू साल 2005 में किया था। 2021 में अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका का खिताब अपने नाम किया और मेसी के करियर का यह पहला बड़ा इंटरनेशनल खिताब रहा। साल 2022 में फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप के खिताब पर कब्जा जमाया। 2024 में मेसी ने अपनी अगुवाई में अर्जेंटीना को लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका का खिताब दिलाया। अपनी कप्तानी में मेसी ने अर्जेंटीना को चार बड़े खिताब दिलाए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेकर मेसी 39 साल की उम्र में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी बने। यह उनके करियर का छठा वर्ल्ड कप रहा। मेसी ने अपने करियर में कुल 208 मैच खेले और कुल 126 गोल और 68 असिस्ट किए। मेसी ने 8 बार बैलन डी'ओर जीता।

युवा चेहरों को मौका देने की रणनीति के तहत हरमनप्रीत को छोडनी पड़ी कप्तानी ?

मुम्बई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के अचानक इस्तीफे ने खेल जगत में हलचल मचा दी है। यह फैसला गुवाहाटी में भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया और मुख्य कोच अमूल मजूमदार के बीच हुई एक समीक्षा बैठक के ठीक एक दिन बाद आया, जिसमें हरमनप्रीत और उपकप्तान स्मृति मंधाना भी मौजूद थीं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि उस बंद कमरे में आखिर क्या हुआ, जिसने अगले ही दिन हरमनप्रीत को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से किनारा करने पर मजबूर कर दिया? क्या यह निर्णय पूरी तरह से उनका था या उन्हें कप्तानी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया?वहीं क्रिकेट हलकों में यह चर्चा आम है कि भारतीय महिला क्रिकेट बदलाव के दौर से गुजर रहा है। 37 वर्षीय हरमनप्रीत लगभग 17 सालों से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रही हैं और लंबे समय से टीम की अगुआई कर रही थीं। उनकी उम्र और लंबे कार्यकाल को देखते हुए, कप्तानी में युवा चेहरों को मौका देने की रणनीति को इस इस्तीफे के पीछे एक बड़ा कारण माना जा रहा है। टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने भी सार्वजनिक मंचों से कई बार कप्तानी संभालने की इच्छा जाहिर की है, जिससे इस अटकल को और बल मिला है।

गौरतलबह है कि हरमनप्रीत कौर भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। उनकी अगुआई में टीम ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतना प्रमुख है। दिलचस्प बात यह है कि हरमनप्रीत ने पहले 2028 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक तक टीम की कप्तानी करने की इच्छा जताई थी, जिसके लिए भारत पहले ही क्वालीफाई कर चुका है। उन्होंने एक दशक तक भारतीय टी-20 टीम की कप्तानी की, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। 2022 में उन्हें वनडे की कमान सौंपी गई और 2023 में वह सभी फॉर्मेट की कप्तान बन गईं।

यह भी माना जा रहा है कि हरमनप्रीत पर कप्तानी छोड़ने का दबाव था। इस साल की शुरुआत में टी-20 विश्व कप में भारत के जल्दी बाहर होने और हरमनप्रीत के बल्ले से रन न निकलने के बाद, डायना एडुल्जी जैसी पूर्व खिलाड़ियों ने खुले तौर पर स्मृति मंधाना को कप्तान बनाने की मांग की थी। हरमनप्रीत ने पांच टेस्ट, 51 वनडे और 155 टी20 मैचों में भारत की कप्तानी की है।

नमन धीर बोले, बल्लेबाजी का मौका मिला तो खुशी होगी

मुम्बइ। उभरते ऑलराउंडर नमन धीर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया। लखनऊ में खेले गए इस मैच में नमन ने अपनी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी से 31 रन देकर तीन महत्वपूर्ण विकेट लिए, जिससे भारतीय टीम वेस्टइंडीज को 171 रन पर सीमित करने में सफल रही। इस प्रभावशाली डेब्यू के बावजूद, नमन अब भी बल्ले से अपनी क्षमता दिखाने के मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसे वह अपनी मुख्य ताकत मानते हैं।

नमन धीर ने अपनी गेंदबाजी से वेस्टइंडीज की पारी को ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 12वें ओवर में कप्तान शाई होप (52) को अक्षर पटेल के हाथों डीप मिडविकेट पर कैच कराया। इसके बाद 14वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड (7) ने उन पर छक्का तो जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर वह लॉन्ग ऑफ पर तिलक वर्मा को कैच दे बैठे। नमन ने अपना तीसरा विकेट 16वें ओवर में शमर स्प्रींगर (9) को अक्षर पटेल के हाथों कैच कराकर हासिल किया।

मैच के बाद नमन ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, मैं अब भी बल्लेबाजी में अपने मौके का इंतजार कर रहा हूं और अगर मुझे बल्ले से मौका मिलता है तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं खुश हूं कि मैं गेंद से योगदान दे सका और टीम जीत गई।

अगरकर की विदाई पर भावुक हुए गंभीर

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का कार्यकाल समाप्त होने पर मुख्य कोच गौतम गंभीर ने उन्हें बधाई दी है, और उनके सफल कार्यकाल की सराहना की। गंभीर ने अगरकर की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में जीती गई तीन आईसीसी ट्रॉफियां इस बात का प्रमाण हैं कि उन्होंने हमेशा टीम को पहले रखा। अगरकर, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण मोड़ पर भारतीय चयन समिति की कमान संभाली थी, ने अपने नेतृत्व में तीन ऐसी टीमें चुनीं जिन्होंने प्रतिष्ठित आईसीसी ट्रॉफी जीतीं। इनमें टी20 विश्व कप 2024, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और टी20 विश्व कप 2026 शामिल हैं।

बीसीसीआई ने एक ही दिन में किये कई बड़े बदलाव

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने गत दिवस यहां हुई अपनी बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। जिनका भारतीय क्रिकेट पर प्रभाव पड़ना तय है। बीसीसीआई ने इसके तहत ही चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर को हट दिया और नए चयनकर्ता की खोज शुरु कर दी। आगामी अंतरराष्ट्रीय दौरों के लिए टीमों की घोषणा और चयन समिति में किया बदलाव है। इसी के तहत ही महिला टीम की कप्तानी से हरमनप्रीत कौर का इस्तीफा हुआ। इसके बाद, चयनकर्ताओं ने स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कप्तान घोषित किया। मंधाना अब तीनों प्रारूपों में टीम का नेतृत्व करेंगी, जबकि टी20 टीम की उपकप्तानी शेफाली वर्मा को और एकदिवसीय टीम की उपकप्तानी दीप्ति शर्मा को सौंपी गई है।

वहीं पुरुष क्रिकेट से की बात करें तो बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की टी20 टीम और इंडिया ए दल की भी घोषणा की है। इसमें श्रेयस अय्यर को टी20 टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं सबसे अधिक हैरानी की बात अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी रही। टीम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन और तिलक वर्मा जैसे स्थापित खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं, इंडिया ए टीम में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर) और कप्तान ध्रुव जुरेल सहित कई टेस्ट क्रिकेटरों को शामिल किया गया है।

बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे के खिलाफ आगामी टी20 और एकदिवयीय सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की भी घोषणा की है। इस टीम में हरमनप्रीत कौर को भी शामिल किया गया है, लेकिन अब वे नई कप्तान स्मृति मंधाना के नेतृत्व में खेलेंगी, जो टीम के भीतर एक नए समीकरण का प्रतीक है।

इसके अलावा बीसीसीआई ने प्रशासनिक स्तर पर भी दो अहम घोषणाएं कीं। पहला, बोर्ड ने चयन समिति में नए चयनकर्ता के लिए आवेदन मांगे हैं, क्योंकि अजीत अगरकर का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। यह पद भारतीय पुरुष टीम के चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरा, और संभवत: एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव यह है कि अब से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण भी सीनियर सिलेक्शन कमिटी की बैठकों में हिस्सा लेंगे। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने पुष्टि की कि इस कदम का उद्देश्य चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन के बीच संवाद की कमी को दूर करना और समन्वय को बेहतर बनाना है।

स्पेन ने क्रोएशिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया

मैड्रिड । स्पेन ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर नेशंस लीग फुटबॉल क्वार्टर फाइनल में जगह बनायी है। स्पेन ने एक रोमांचक मुकाबले में क्रोएशिया को 2-1 से हराया। इस मैच में एक गोल से पिछड़ने के बाद स्पेन ने अच्छी वापसी करते हुए अपने लगातार 42 मैचों से अजेय रहने के सिलसिल को बरकरार रखा है। इस जीत के साथ स्पेन ने अपने चारों ग्रुप मैचों में जीत हासिल कर लीग के अगले दौर में अपनी स्थिति बेहतर कर ली है।

मैच की शुरुआत में ही स्पेन ने गेंद पर कब्जे का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। क्रोएशिया ने भी पहले हाफ में अच्छी टक्करी दी। स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन ने मैच की शुरुआत से ही कई शानदार बचाव किए, उन्होंने जोसिप स्टैनिसिक और बाद में इगोर मटानोविच के प्रयासों को नाकाम किया। हालांकि, 20वें मिनट में इवान पेरिसिच ने रिबाउंड पर गोल कर एक गोल दागते हुए क्रोएशिया को 1-0 की बढ़त दिला दी।

वहीं स्पेन के कोच लुइस डे ला फुएंते ने हाफ-टाइम में एलेक्स बाएना की जगह मेरिनो को मैदान पर उतारा, और यह बदलाव सफल रहा।

मेरिनो ने 60वें मिनट में दानी ओल्मो के एक बेहतरीन पास पर गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर किया। इस गोल से पहले भी क्रोएशिया के गोलकीपर डोमिनिक लिवाकोविच ने यमल के एक प्रयास को नाकाम किया था। मैच के 78वें मिनट में, रोड्री की जगह मैदान पर आए मार्टिन जुबिमेंडी की एक गलती से पेरिसिच को मौका मिला, लेकिन साइमन ने एक बार फिर शानदार बचाव किया। एक मिनट बाद, मार्क कुकुरेला पर पीछे से खतरनाक तरीके से हमला करने के कारण पेरिसिच को दूसरा पीला कार्ड मिला और उन्हें मैदान से बाहर भेज दिया गया, जिससे क्रोएशिया 10 खिलाड़ियों पर सिमट गई। कमजोर पड़ती क्रोएशियाई टीम के खिलाफ, मेरिनो ने 88वें मिनट में जुबिमेंडी से मिले पास को लेकर, घूमते हुए टॉप कॉर्नर में शानदार शॉट मारा और स्पेन को 2-1 की निर्णायक बढ़त दिला दी, जिससे टीम की क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की हो गई। इसमें मेरिनो के दो गोल और गोलकीपर उनाई सिमोन के बेहतरीन बचावों की अहम भूमिका रही।

कप्तानी को लेकर उठने लगे थे मंधाना और हरमनप्रीत में मतभेद

मुम्बई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मंगलवार को अपनी नई कप्तान मिल गई, जब बीसीसीआई ने स्मृति मंधाना को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। यह नियुक्ति हरमनप्रीत कौर के तीनों प्रारूपों की कप्तानी से हटने के बाद हुई, जिन्होंने बीसीसीआई की समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला लिया था। सवाल यह उठता है कि क्या देश की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार मंधाना को यह नेतृत्व की बागडोर सौंपने में देर हो गई है। हरमनप्रीत, जिन्होंने 2016 में पहली बार भारत की कप्तानी की थी, हरमनप्रीत ने कप्तान के रूप में अपने शानदार कार्यकाल का अंत बेहतरीन अंदाज में किया, जिसमें जापान में भारत को लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल दिलाना भी शामिल है। 2013 में अंतरराष्ट्रीय पदार्पण करने वाली मंधाना अब खेल की शीर्ष बल्लेबाजों में से एक हैं, जो तीनों प्रारूपों में 10,000 से अधिक रन बना चुकी हैं। उनके कौशल और आक्रामक शैली ने उन्हें हमेशा अलग पहचान दिलाई है। यह कोई रहस्य नहीं था कि पिछले साल घरेलू मैदान पर वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद चयनकर्ताओं द्वारा कप्तानी में यथास्थिति बनाए रखने से स्मृति निराश थीं। उन्होंने हाल ही में अपनी कप्तानी की तैयारी जाहिर करते हुए एशियाई खेलों का गोल्ड जीतने के बाद कहा था कि भारत को इससे भी बड़े टूर्नामेंट जीतने का लक्ष्य रखना चाहिए। हरमनप्रीत और स्मृति के बीच कप्तानी को लेकर मतभेद भी एक जटिल मुद्दा बन गया था, जबकि वे पहले काफी अच्छी तरह से घुलती-मिलती थीं।

प्रसिद्ध कृष्णा का न्यूजीलैंड दौरे के शुरुआती मैचों में खेलना संभव नहीं

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा चोटिल होने के कारण करीब तीन सप्ताह के लिए खेल से बाहर हो गये है। इससे वह इसी माह शुरु हो रहे न्यूजीलैंड दौरे मे शायद ही खेल पायें। इससे भारतीय टीम प्रबंधन की परेशानी बढ़ गयी है। कृष्णा को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय मैच के दौरान चोट लगी थी, जिसके बाद वह सिर्फ पांच ओवर ही गेंदबाजी कर पाए थे। इसके चलते वह तीसरे और अंतिम मुकाबले में भी नहीं खेल पाए थे। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रसिद्ध को पूरी तरह ठीक होने में कम से कम तीन सप्ताह का समय लग सकता है, जो न्यूजीलैंड दौरे से ठीक पहले आया है। भारतीय टीम को इसी महीने न्यूजीलैंड का दौरा करना है, जिसमें पांच टी20, पांच एकदिवीसयस और दो टेस्ट मैचों की लंबी सीरीज खेलनी है। प्रसिद्ध कृष्णा इस समय भारतीय तेज गेंदबाजी सेटअप के एक महत्वपूर्ण सदस्य माने जाते

हैं, और उनकी अनुपस्थिति से टीम संयोजन पर सीधा असर पड़ेगा। चयनकर्ताओं को अब उनकी जगह किसी और विकल्प पर विचार करना पड़ सकता है, जिससे टीम की गहराई और बेंच स्ट्रेंथ की परीक्षा होगी।

टीम इंडिया में लगातार चोटिल हो रहे खिलाड़ियों को लेकर कप्तान शुभमन गिल भी चिंतित हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय के बाद उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। चोट, व्यस्त कार्यक्रम और आस-पास हो रहे दूसरे मैचों की वजह से हम अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी लाइनअप के साथ नहीं खेल पा रहे हैं, जिससे हम खेलना चाहते हैं। वहीं अब हमारे पास प्रयोग करने के लिए अब बहुत ही कम समय बचा है। हम जिस संयोजन के साथ खेलना चाहते हैं, उम्मीद है कि अगली सीरीज से हमें उसके लिए सभी खिलाड़ी मिल जाएंगे। उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि वे विश्व कप में जिस संयोजन के साथ खेलना चाहते हैं, उसी के साथ अभी से खेलना शुरू करना चाहते हैं।

भारतीय टीम पिछले कुछ महीनों से चोट की गंभीर परेशानियों से जूझ रही है, जिससे उसके प्रदर्शन और तैयारियों पर लगातार असर पड़ रहा है। हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती और नितीश रेड्डी जैसे कई खिलाड़ी इस दौरान चोटिल हुए हैं, जो टीम प्रबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। प्रसिद्ध कृष्णा की यह चोट इस समस्या को और गहरा करती दिख रही है, और न्यूजीलैंड जैसे महत्वपूर्ण दौरे से पहले यह टीम इंडिया के लिए एक चिंता का सबब बन गई है।

न्यूजीलैंड दौरे के लिए ऋषभ-राहुल सहित कई दिग्गज खिलाड़ी इंडिया ए टीम में शामिल

मुम्बई । भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआईद्ध) ने आगामी न्यूजीलैंड दौरे के लिए इंडिया ए टीम की घोषणा कर दी है। इस 15 सदस्यीय टीम में केएल राहुल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल और वॉशिंगटन सुंदर जैसे कई अनुभवी खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जो न्यूजीलैंड की कठिन परिस्थितियों में खुद को ढालने और अपनी फॉर्म साबित करने का प्रयास करेंगे। यह दौरा भारतीय क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत की मुख्य टीम इसी महीने न्यूजीलैंड में कुल 15 मैच खेलेगी, जिसमें पांच टी20, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच शामिल हैं। हालांकि, बीसीसीआई ने अभी सिर्फ टी20 सीरीज और इंडिया ए टीम का ही एलान किया है। मुख्य वनडे और टेस्ट टीमों की घोषणा अभी बाकी है। इंडिया ए टीम में कुल 11 ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला है, जिससे यह साफ होता है कि चयनकर्ता भविष्य के लिए एक मजबूत टीम तैयार करना चाहते हैं। चोट के बाद अपनी फिटनेस हासिल कर चुके साई सुदर्शन को भी टीम में जगह मिली है, जो उनकी टेस्ट क्रिकेट में वापसी की राह को और मजबूत करेगी। इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच पहला चार दिवसीय मुकाबला 24 से 28 अक्टूबर के बीच लिंकन में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मैच 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक क्राइस्टचर्च में आयोजित होगा, जबकि तीसरा और अंतिम मैच 7 से 10 नवंबर के बीच फिर से लिंकन में खेला जाएगा। ये मुकाबले खिलाड़ियों को लंबे प्रारूप में अपनी क्षमताओं को परखने और विदेशी पिचों पर अपनी तकनीक को निखारने का महत्वपूर्ण अवसर देंगे।

भुवनेश्वर की तरह ही शमी की भी भारतीय टीम में हो सकती है वापसी

मुम्बई । भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने पिछने चार साल से भारतीय टीम से बाहर चल रहे अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल कर सभी को हैरान कर दिया। वहीं अब कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से भुवनेश्वर की वापसी हुई है अब उसी तरह से अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की भी भारतीय टीम में वापसी हो सकती है।

भुवनेश्वर की टी20 टीम में वापसी जहां करीब चार साल बाद हुई है, वहीं गेंदबाज शमी भी लंबे समय से टीम से बाहर हैं। इस तेज गेंदबाज ने अंतिम बार मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था। इसके बाद फिटने और प्रदर्शन में गिरावट के कारण चयन समिति ने उनके नाम पर विचार नहीं किया था। हालांकि, शमी ने घरेलू क्रिकेट खेलते हुए कई बार दावा किया है कि वे पूरी तरह फिट हैं और किसी ने भी उनसे भारतीय टीम से खेलने के लिए संपर्क नहीं किया है। वहीं तब मुख्य चयनकर्ता रहे अजीत अगरकर ने कहा था कि शमी फिट नहीं हैं और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) से उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

इन सबके बावजूद, मोहम्मद शमी लगातार घरेलू क्रिकेट में सक्रिय रहे हैं और वर्तमान में भी वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह

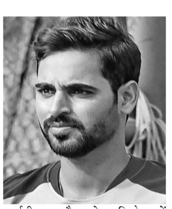

आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बल पर भुवनेश्वर कुमार ने राष्ट्रीय टीम में वापसी की है, उसी तरह शमी को भी दोबारा मौका मिल सकता है। भारतीय टीम प्रबंधन 2027 में होने वाले विश्व कप के लिए अलग-अलग संयोजन पर विचार कर रहा है और एक परफेक्ट गेंदबाजी संयोजन की तलाश में है। अंतरिम मुख्य चयनकर्ता प्रज्ञान ओझा के नेतृत्व वाली चयन समिति न्यूजीलैंड दौरे पर शमी को आजमा सकती है। इस दौरे पर भारत को पांच एकदिवसीय और उसके ठीक बाद दो टेस्ट मैच खेलने हैं।

संभावना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया जाएगा, जिससे शमी के लिए टीम में जगह बनाने का रास्ता खुल सकता है। यदि उन्हें एकदिवसीय या टेस्ट सीरीज के लिए चुना जाता है, तो यह उनके लिए टीम में अपनी जगह स्थायी करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। ठीक उसी तरह, भुवनेश्वर कुमार के लिए भी न्यूजीलैंड के खिलाफ यह टी20 सीरीज अपनी उपयोगिता साबित करने और आगामी महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों के लिए अपना दावा मजबूत करने का शायद आखिरी बड़ा मौका होगा।

टी20 टीम इस प्रकार है

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव।

अभिषेक ने तोड़ा रोहित का रिकॉर्ड

मुम्बई । भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अब इस प्रारुप में पहले ही ओवर में भारतीय टीम के लिए सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गये हैं। अभिषेक ने इसी के साथ ही अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभिषेक ने ये उपलब्धि वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच में हासिल की। इस मैच में भारतीय टीम को 8 विकेट से जीत मिली।

अभिषेक अब टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय टीम की ओर से पहले ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले

खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने अपने पहले ओवर की 168 गेंदों का सामना करते हुए अब तक कुल 13 छक्के लगाए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 में हासिल की, जहां उन्होंने 10 गेंदों में 21 रन बनाये। इसमें तीन चौके और एक छक्का शामिल था। यह खास छक्का भारतीय पारी के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर मैथ्यू फोर्ड की गेंद पर लगा। इस ओवर में फोर्ड ने कुल 15 रन दिए।

अभिषेक ने इसी के साथ ही रोहित के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा, जिनके नाम पहले ओवर में 401 गेंदों पर 12 छक्के थे। रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं और अब सिर्फ एकदिवसीय में सक्रिय हैं। इस सूची में ईशान किशन 114 गेंदों पर 8 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि संजू सैमसन ने 110 गेंदों पर 7 छक्के लगाए हैं। वीरेंद्र सहवाग और यशस्वी जायसवाल ने भी पहले ओवर में 4-4 छक्के लगाये हैं, जबकि केएल राहुल के नाम 2 छक्के हैं।

संघ बोला कार्रवाई नहीं रुकी तो काम नहीं करेंगे

देवास के बाद प्रदेशभर में पटवारियों पर एक्शन,स्वामित्व योजना में रजिस्ट्री नहीं करने पर निलंबन-बर्खास्तगी

भोपाल। देवास में दो प्रोबेशनर पटवारियों की सेवा समाप्ति के बाद अब प्रदेश के अन्य जिलों में भी पटवारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। आगर मालवा में तीन पटवारियों को बर्खास्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। गुना में चार पटवारियों को निलंबित कर जिले के सभी 52 पटवारियों को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया है। सतना में भी एक पटवारी को निलंबित किया गया है। कार्रवाई के विरोध में मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने प्रदेशभर में कलेक्टरों को ज्ञापन देने और ऑनलाइन राजस्व कार्यों से अलग रहने का ऐलान किया है।

मप्र पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र बघेल ने बताया कि सीधी में संघ के पदाधिकारियों के साथ पटवारियों के खिलाफ सेवा समाप्ति, निलंबन और अन्य दंडात्मक कार्रवाई के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया है। संघ ने प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग और कलेक्टर सीधी को पत्र भेजकर कार्रवाई वापस लेने की मांग की है। संघ के अनुसार, प्रदेश संगठन के निर्णय के तहत 7 अक्टूबर 2026 से पटवारी संवर्ग ऑनलाइन राजस्व कार्यों से अलग रहेगा। पटवारी सभी शासकीय समूहों से भी बाहर रहेंगे। संघ का कहना है कि यह निर्णय दंडात्मक कार्रवाई वापस लिए जाने तक जारी रहेगा।

स्वामित्व योजना के काम को लेकर कार्रवाई का विरोध

पटवारी संघ ने कहा कि देवास में 'स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026' सहित अन्य कार्यों को आधार बनाकर पटवारियों की सेवा समाप्त की जा रही है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी निलंबन और दूसरी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। संघ का कहना है कि स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी विधिक और व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी शासन को पहले ही दी जा चुकी है। इसके बावजूद कार्रवाई किया जाना चिंताजनक है।

गुना में 4 सस्पेंड, 52 को टर्मिनेशन नोटिस

गुना कलेक्टर किशोर कान्याल ने बताया कि जिले में चार पटवारियों को सस्पेंड किया गया है। वहीं शासकीय कार्य नहीं करने के मामले में सभी 52 पटवारियों को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया है। पटवारी संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक देवास में दो और आगर मालवा में तीन पटवारियों की बर्खास्तगी की जानकारी मिली है। इससे पहले स्वामित्व योजना में निष्पादक की भूमिका का विरोध करने पर रायसेन और मंडला में भी पटवारियों पर कार्रवाई सामने आ चुकी है।

कार्रवाई हुई तो बिना सूचना राजस्व काम छोड़ने की चेतावनी

पटवारी संघ ने चेतावनी दी है कि भविष्य में प्रदेश के किसी भी जिले में पटवारियों के खिलाफ इसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई हुई तो सभी पटवारी बिना पूर्व सूचना के सभी राजस्व कार्यों से अलग होने के लिए बाध्य होंगे।

मप्र में 7 पटवारियों की सेवा समाप्ति, संघ अध्यक्ष समेत 4 सस्पेंड

मध्य प्रदेश में शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने वाले कर्मचारियों पर प्रशासन ने अब तक का सबसे कड़ा रुख अपनाया है। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली 'स्वामित्व योजना' के अंतर्गत अधिकार अभिलेखों के निष्पादन एवं पंजीयन

कार्य में शून्य प्रगति दर्ज कराने, अपने हल्के में न रहने और असहयोग का रवैया अपनाने पर देवास जिले में 3 परिवीक्षाधीन पटवारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं।

देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने सोनकच्छ तहसील के घिचलाय में पदस्थ नितिन विश्वकर्मा, देवास ग्रामीण के अजय नागर और टोंकखुर्द के विशाल टईया को एक माह का अग्रिम वेतन देकर सेवा से पृथक करने संबंधी आदेश जारी किए हैं। इन तीनों को फरवरी 2024 में 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया गया था। जांच और अनुविभागीय अधिकारियों के प्रतिवेदन में सामने आया कि ये पटवारी अपने हलके में निवास नहीं कर रहे थे, समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे थे और बीते 6 माह में इनकी राजस्व वसूली भी अत्यधिक असंतोषजनक पाई गई।

गुना में पटवारी संघ अध्यक्ष समेत 4 सस्पेंड, 4 पटवारियों की सेवा समाप्त

दूसरी ओर गुना जिले में भी 'स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026' में निर्धारित काम न करने और घोर लापरवाही बरतने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। गुना जिले में इस योजना के तहत अब तक एक भी रजिस्ट्री न होने के कारण जिले की रैंकिंग मध्य प्रदेश में फिसलकर 54वें स्थान पर पहुंच गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने 4 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जिसमें जिला पटवारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र किरार भी शामिल हैं।

सभी विभाग समय सीमा में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक करें

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया परिपत्र

भोपाल। राज्य शासन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के अनुसार अनिवार्य रूप से अधीनस्थ कार्यालयों को समय-सीमा में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैँ जिससे पात्र लोक सेवकों को समय पर पदोन्नति प्राप्त हो सके। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सम्बन्ध मे सभी विभागों, संभागायुक्तों, विभागध्यक्ष एवं कलेक्टर्स को विस्तृत निर्देश दिए हैँ।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के नियम 6 के अनुसार प्रत्येक चयन वर्ष के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किए जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रत्येक चयन वर्ष के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उसके पूर्ववर्ती वर्ष में सामान्यत: माह सितम्बर से माह नवम्बर के मध्य आयोजित की जाना अनिवार्य है। इस बैठक में आगामी चयन वर्ष की 31 दिसम्बर के पूर्वान्ह तक की स्थिति में उपलब्ध उद्भूत होने वाली समस्त संभावित एवं अप्रत्याशित रिक्तियों के लिए पदोन्नति के लिए लोक सेवकों की उपयुक्तता पर विचार किया जाएगा।

पूर्व में 31 दिसम्बर, 2025 के पूर्वान्ह तक की रिक्तियों के लिये एक विशेष विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक इस नियम के प्रवृत्त होने के उपरांत की गई थी,जिसके आधार पर वर्ष 2026 में पदोन्नति की कार्यवाही की गई है अथवा प्रचलन में है।

परिपत्र में कहा गया है कि वर्ष 2025 में पुन: माह सितम्बर से माह नवम्बर के मध्य वर्ष 2026 में उत्पन्न हुई कोई अप्रत्याशित रिक्ति जो प्रतीक्षा सूची से भी नहीं भरी जा सकी हो एवं चयन वर्ष अर्थात 31 दिसम्बर 2026 के पूर्वान्ह तक की प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की जानी थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए हैं। कि विभागों द्वारा 31 दिसंबर 2026 के पूर्वान्ह तक की प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये यदि बैठक आयोजित नहीं की गई हो तो बैठक आयोजित की जाए। विभाग द्वारा यदि विशेष विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 31 दिसंबर 2025 के पूर्वान्ह तक की प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के साथ ही 31 दिसंबर 2026 के पूर्वान्ह तक की प्रत्याशित रिक्तियों को भरने की कार्यवाही की जा चुकी हो तो बैठक के आयोजन की आवश्यकता नहीं होगी। परिपत्र के अनुसार वर्ष 2026 में उत्पन्न हुई कोई अप्रत्याशित रिक्ति जो प्रतीक्षा सूची से भी नहीं भरी जा सकी हो एवं आगामी चयन वर्ष अर्थात 31 दिसम्बर 2027 के पूर्वान्ह तक की प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक भी इसी वर्ष माह सितम्बर से नवम्बर के मध्य किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

विशेष न्यायालय सबलगढ़ ने विद्युत चोरी के आरोपी को दोषसिद्ध होने पर दण्डित किया

आरोपी पर 23,937 रुपये का अर्थदण्ड एवं 15,958 रुपये का सिविल दायित्व अधिरोपित

ग्वालियर/मुरैना। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सबलगढ़ अंतर्गत विद्युत चोरी के मामले में विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम), सबलगढ़ के विशेष जिला न्यायाधीश श्री अजय कुमार चौहान ने आरोपी रतीराम धाकड़, निवासी उचाड को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास तथा विद्युत चोरी से प्राप्त वित्तीय लाभ के तीन गुना के बराबर 23,937 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 05 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 15,958 रुपये का सिविल दायित्व भी अधिरोपित किया है। सिविल दायित्व की राशि जमा होने के उपरांत नियमानुसार अपील अवधि समाप्त होने पर उक्त राशि परिवादी विद्युत कंपनी को वापस की जाएगी।

गौरतलब है कि ग्राम उचाड़ निवासी आरोपी रतीराम धाकड़ द्वारा 03 अगस्त 2023 को 25 के.व्ही.ए. वितरण ट्रांसफार्मर से अवैध रूप से विद्युत चोरी कर 03 एचपी के मोनो ब्लॉक पंप के द्वारा सिंचाई का कार्य किया जा रहा था। कंपनी के जॉच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान विद्युत चोरी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत चोरी एवं विद्युत के अवैध उपयोग के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

करोड़ो की फसल बीमा क्लेम राशि हड़पने वाला राजेश विश्वकर्मा गिरफ्तार

3 करोड़ 62 लाख से अधिक की रकम रिश्तेदारो के खातो में की ट्रांसफर

भोपाल। थाना एमपीनगर पुलिस ने साढ़े तीन करोड़ की ठगी के मामले में करीब छह महीनो से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी जिय हिन्द शर्मा से मिली जानकारी के अनुसार 27 मार्च 26 को फरियादी दीपक पुंडलीक पाटिल ने आरोपपी राजेश विश्वकर्मा सहित अन्य के खिलाफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया में 3 करोड़ 62 लाख 62 हजार 422 से अधिक की रकम की धोखाधड़ी करने के संबंध में लिखित शिकायत की थी।

- जॉच में हुए चौकांने वाले खुलासे

कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक पाटिल की आधिकारिक शिकायत के अनुसार, शुरुआती जांच में एनसीआइपी पोर्टल पर अनधिकृत तरीके से लॉगिन करके 10 अलग-अलग खातों में 45.79 लाख रुपये ट्रांसफर किए जाने का मामला सामने आया था। जब इसकी गहराई से आगे जांच की गई, तो यह हेराफेरी की राशि बढ़कर सीधे 77.04 लाख रुपये हो गई। इस अवैध काम के लिए कुल 13 विभिन्न बैंक खातों का गलत इस्तेमाल किया गया था। आरोप है कि किसानों के असली बैंक खातों में दर्ज जानकारी बदलकर बीमा क्लेम की पूरी रकम चालाकी से अन्य खातों में डाइवर्ट कर दी गई।

- हेराफेरी में 29 बैंक खातों का हुआ इस्तेमाल

कंपनी की इंटरनल जांच में पे-प्रो सिस्टम के माध्यम से 2.85 करोड़ रुपये की अतिरिक्त हेराफेरी किए जाने का भी खुलासा हुआ। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुल 29 बैंक खातों में अवैध रूप से रकम जमा कराई गई। शातिर आरोपी ने किसानों के नाम से फर्जी ई-मेल आईडी तैयार करके और वरिष्ठ अधिकारियों के जाली पत्र, फर्जी मुहर तथा दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर भुगतान अन्य खातों में करवाने की साजिश रची थी।

- रिश्तेदारो परिचितो 32 खातो में भेजी करोड़ो की रकम

कंपनी की शिकायत में बताया गया कि इन दोनों माध्यमों से कुल 32 अलग-अलग खातों में कुल 3.62 करोड़ रुपये की भारी रकम ट्रांसफर की गई है। कंपनी के अनुसार, लगभग छह महीने तक लगातार क्लेम की राशि न मिलने पर जब किसानों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, तब जाकर इस पूरे घोटाले का खुलासा हुआ और आंतरिक जांच शुरू की गई। आवेदन की जॉच के बाद एमपीनगर थाने में राजेश विश्वकर्मा सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने की भनक लगने पर राजेश फरार हो गया था। उसकी लगातार तलाश में जुटी पुलिस टीम को बुधवार 7 अक्टूबर को उसकी लोकेशन भोपाल में मिली। इसके बाद टीम ने फरार जालसाज - राजेश विश्वकर्मा पिता. संतोष विश्वकर्मा (32) निवासी न्यू आरटीओ के सामने राजधानी परिसर ट्रांसपोर्ट नगर थाना बिलखिरिया से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही में जुटी है।

जीआईएस से पहले निवेश जुटाने की कवायद तेज, आज मुंबई में उद्योगपतियों से मिलेंगे मुख्यमंत्री

भोपाल। मध्य प्रदेश में जनवरी 2027 में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) से पहले सरकार ने निवेशकों से सीधा संपर्क बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 8 अक्टूबर को मुंबई में देश के प्रमुख उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। मुंबई के लोअर परेल स्थित द सेंट रेजिस होटल में होने वाले निवेश संवाद में मुख्यमंत्री उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन बैठकें करेंगे। मुंबई देश के बड़े औद्योगिक और कारोबारी समूहों का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में मुख्यमंत्री का उद्योगपतियों से सीधे संवाद का मकसद मध्य प्रदेश में उपलब्ध निवेश अवसरों की जानकारी देने के साथ ही कंपनियों की जरूरत और उनके निवेश प्रस्तावों को समझना भी है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति, निवेश के अवसर, औद्योगिक अधोसंरचना और अलग-अलग क्षेत्रों में विकसित हो रहे औद्योगिक क्लस्टर्स की जानकारी दी जाएगी। औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर प्रस्तुतीकरण देंगे। सरकार की ओर से निवेशकों को प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और लॉजिस्टिक्स से जुड़े फायदे भी बताए जाएंगे। मध्यप्रदेश देश के मध्य में होने के कारण बड़े बाजारों तक पहुंच के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा उद्योगों की जरूरत के मुताबिक अधोसंरचना और निवेश सुविधा तंत्र को मजबूत करने की जानकारी भी साझा की जाएगी।

आठ साल बाद भी जीएसटी पोर्टल की दिक्कतें बरकरार

भोपाल। जीएसटी लागू हुए आठ साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन करदाताओं और कर सलाहकारों की पोर्टल संबंधी परेशानियां अब भी पूरी तरह दूर नहीं हुई हैं। जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक से पहले प्रदेश के कर विशेषज्ञों ने पोर्टल की तकनीकी खामियों को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कई मामलों में कर का भुगतान समय पर होने के बावजूद केवल रिटर्न में दर्ज जानकारी की त्रुटि सुधारने पर पोर्टल ब्याज की मांग निकाल रहा है।

एमपी टैक्स लॉ बार एसोसिएशन (एमपीटीएलबी) और कमर्शियल टैक्स प्रैक्टिनर्स एसोसिएशन (सीटीपीए) ने इस संबंध में जीएसटी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर पोर्टल में आवश्यक बदलाव करने की मांग की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक कई मामलों में करदाता की गलती टैक्स भुगतान से जुड़ी नहीं होती, बल्कि रिटर्न में किसी शब्द, विवरण या अन्य जानकारी की एंट्री में होती है। इसके बावजूद सिस्टम ऐसी स्थिति को कर देयता में देरी मानकर ब्याज की गणना कर देता है।

आईटीसी उपलब्ध होने के बावजूद ब्याज की गणना

कर विशेषज्ञों ने एक अन्य तकनीकी समस्या भी उठाई है। उनका कहना है कि कुछ मामलों में संबंधित अवधि में करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पर्याप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) उपलब्ध रहता है। बाद में यदि किसी अवधि की कर देयता का भुगतान किया जाता है, तो उपलब्ध आईटीसी से उसका समायोजन किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी स्थिति में सरकार के पास उपलब्ध क्रेडिट पहले से मौजूद होता है और वास्तविक रूप से अतिरिक्त नकद भुगतान की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बावजूद पोर्टल धारा 50 के तहत ब्याज की गणना कर देता है। उनका तर्क है कि जहां पर्याप्त आईटीसी उपलब्ध था और राजस्व को वास्तविक आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, वहां उस सीमा तक ब्याज नहीं लगाया जाना चाहिए।

पोर्टल में अलग व्यवस्था की मांग

एमपीटीएलबी और सीटीपीए ने मांग की है कि पोर्टल में ऐसी तकनीकी व्यवस्था विकसित की जाए, जो वास्तविक कर भुगतान में देरी और केवल रिटर्न में जानकारी सुधारने के मामलों के बीच अंतर कर सके। इससे उन करदाताओं पर ब्याज का बोझ नहीं पड़ेगा, जिन्होंने समय पर कर का भुगतान कर दिया है, लेकिन बाद में किसी तकनीकी या शाब्दिक त्रुटि को ठीक किया है।

एक लाख नौकरियां देंगे तो विभाग, पद और समयसीमा बताएं

पटवारी ने रोजगार-भर्ती के रोडमैप से लेकर पेपर लीक और कर्ज तक सरकार को घेरा; बोले

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के यूथ कॉन्क्लेव के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर एक साथ कई मोर्चों पर हमला बोला। रोजगार, सरकारी भर्ती, युवा नीति, परीक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण, कर्ज और यूथ कॉन्क्लेव के आयोजन को लेकर उन्होंने सरकार से जवाब मांगा। पटवारी ने तंज कसते हुए कहा कि जिस सरकार की पटवारी नहीं सुनते, वो खटारा नहीं तो क्या है? पटवारी ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए लगातार घोषणाएं कर रही है, लेकिन इन घोषणाओं का जमीन पर क्या परिणाम निकलेगा, इसका स्पष्ट रोडमैप सामने नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री की अगले साल एक लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि ये नौकरियां किन विभागों में, कितने पदों पर और किस समयसीमा में दी जाएंगी।

पटवारी ने कहा कि सरकार पहले ढाई लाख और फिर पांच लाख रोजगार देने की बात कर चुकी है। अब एक लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की गई है। ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि रोजगार का आंकड़ा किस आधार पर तय किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। सरकार को विभागवार रिक्त पदों की सूची, भर्ती का कैलेंडर और नियुक्तियों की समयसीमा सार्वजनिक करनी चाहिए। केवल रोजगार का आंकड़ा बताने से युवाओं की समस्या हल नहीं होगी। पटवारी ने रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं का हवाला देते हुए कहा कि जब रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में युवा पंजीकृत हैं, तब एक लाख रोजगार के बाद बाकी युवाओं के लिए सरकार की क्या योजना है, यह भी बताया जाना चाहिए। पीएससी की परीक्षा साल में दो बार कराने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर भी पटवारी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए सिर्फ परीक्षा की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। असली सवाल यह है कि कितने पद खाली हैं, कितने पदों पर भर्ती होगी और परीक्षा से नियुक्ति तक की प्रक्रिया कितने समय में पूरी होगी। उन्होंने पिछली परीक्षाओं के परिणाम और नियुक्तियों में हुई देरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि युवाओं को परीक्षा, परिणाम, दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति तक पूरी प्रक्रिया की समयसीमा मिलनी चाहिए।

तीन लाख शिक्षक पद खाली होने का दावा

पटवारी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि स्कूल-कॉलेजों में बड़ी संख्या में शिक्षक पद खाली हैं। उनके मुताबिक विश्वविद्यालयों में भी पद रिक्त हैं और शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवा वर्ष की बात की है, लेकिन युवाओं के भविष्य से सीधे जुड़े शिक्षा और रोजगार के सवालों का समाधान किए बिना केवल आयोजन करने से स्थिति नहीं बदलेगी।

पेपर लीक पर भी सरकार से जवाब

प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा की पारदर्शिता का मुद्दा उठाते हुए पटवारी ने कहा कि युवा परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार को बताना चाहिए कि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उन्होंने व्यापमं का नाम बदलने के बावजूद परीक्षा व्यवस्था से जुड़े विवाद खत्म नहीं होने का आरोप लगाया। पटवारी ने परीक्षा संबंधी मामलों में कार्रवाई और उसके बाद होने वाली नियुक्तियों पर भी सरकार से जवाब मांगा।

'ये राहुल गांधी के नहीं, छात्रों के सवाल'

पटवारी ने इंदौर में कांग्रेस के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि युवाओं ने वहां जो सवाल उठाए, वे राहुल गांधी के व्यक्तिगत सवाल नहीं हैं। ये प्रदेश के छात्रों और युवाओं के सवाल हैं।

भूमि नामांतरण के एवज में रिश्वत मांगने वाले जावर के पटवारी धर्मेन्द्र सिंह राठौर के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति

भोपाल। राजस्व प्रशासन में अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामलों में जिला स्तर पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर सीहोर श्री बालागुरु के. ने जावर तहसील में पदस्थ पटवारी धर्मेन्द्र सिंह राठौर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की है। यह कार्रवाई लोकायुक्त में दर्ज शिकायत और जांच में सामने आए तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की गई है। जारी आदेश के अनुसार, पटवारी धर्मेन्द्र सिंह राठौर के विरुद्ध शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया था कि पटवारी द्वारा भूमि नामांतरण के एवज में 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है।

शिकायत के सत्यापन में 8 हजार रुपये रिश्वत मांगने की पुष्टि

जारी आदेश के अनुसार शिकायत के सत्यापन के लिए निरीक्षक मुकेश तिवारी द्वारा शिकायतकर्ता को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर उपलब्ध कराया गया।रिकॉर्डिंग के दौरान पटवारी द्वारा 8 हजार रुपये रिश्वत लेने पर सहमति व्यक्त की गई। इसके बाद स्वतंत्र पंच साक्षियों की उपस्थिति में रिकॉर्डेड वार्तालाप का अवलोकन कर प्रारंभिक पंचनामा तैयार किया गया और जावर जाकर ट्रेप की कार्रवाई की गई।

80 हजार शिक्षकों की पेंशन पर सरकार बनाम कोर्ट आमने-सामने

- हाईकोर्ट ने संविलियन को नई नियुक्ति नहीं माना, पुरानी सेवा गिनकर ओपीएस देने के निर्देश - तीन महीने बाद भी अमल नहीं, अब रिव्यू की तैयारी

भोपाल । मध्य प्रदेश में करीब 80 हजार शिक्षकों की पुरानी पेंशन का मामला अब सरकार और कर्मचारियों के बीच प्रशासनिक विवाद से निकलकर कानूनी टकराव की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। जबलपुर हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा पूर्व शिक्षाकर्मियों की सेवा को निरंतर मानते हुए पुरानी पेंशन का लाभ देने के आदेश के करीब तीन महीने बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग ने इसका पालन नहीं किया है। इसके बजाय अब सरकार इस फैसले को चुनौती देने के लिए रिव्यू याचिका और आगे डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रही है। मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 के संविलियन को नई नियुक्ति मानने के शासन के तर्क को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने माना कि शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में शामिल होना सेवा का नया प्रारंभ नहीं, बल्कि संविलियन और पदनाम परिवर्तन की प्रक्रिया थी। ऐसे में उनकी पूर्व सेवा को पेंशन की गणना से बाहर नहीं किया जा सकता।

1998 की नियुक्ति से शुरू हुआ विवाद

मामले में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 22 अगस्त 1998 को जिला पंचायत के माध्यम से शिक्षाकर्मी वर्ग-2 के पद पर हुई थी। बाद में पंचायत अध्यापक संवर्ग नियम, 2008 के तहत वे अध्यापक और फिर वरिष्ठ अध्यापक बने। इसके बाद 15 फरवरी 2019 को उन्हें उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर पदस्थ किया गया। विवाद तब पैदा हुआ, जब शासन ने वर्ष 2018 के सेवा भर्ती नियमों के नियम 18.1 और 18.2 का हवाला देते हुए इस प्रक्रिया को नई नियुक्ति माना और पूर्व सेवा को पेंशन के लिए स्वीकार नहीं किया। इसी आधार पर संबंधित कर्मचारियों को नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के दायरे में रखा गया।

कोर्ट ने कहा- सेवा में ब्रेक नहीं तो नई नियुक्ति कैसे?

हाईकोर्ट ने शासन के इस तर्क को खारिज करते हुए 2008 के अध्यापक संवर्ग नियमों के नियम 5 का हवाला दिया। कोर्ट के मुताबिक शिक्षाकर्मियों को अध्यापक संवर्ग में शामिल किया जाना संविलियन था। जब कर्मचारी की सेवा में एक दिन का भी व्यवधान नहीं आया, तो केवल संवर्ग और पदनाम बदलने से इसे नई नियुक्ति नहीं माना जा सकता। अदालत ने पेंशन के लिए संविलियन से पहले की सेवा अवधि को भी जोडने़ और पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के निर्देश दिए।

आदेश के बाद भी लागू नहीं हुआ फैसला

हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों को उम्मीद थी कि सरकार पेंशन संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। लेकिन करीब तीन महीने गुजरने के बावजूद विभाग ने आदेश पर अमल नहीं किया है। अब विभाग की ओर से फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है। मामले को लेकर 5 अक्टूबर को जबलपुर में स्कूल शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों की महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ बैठक भी प्रस्तावित की गई, जिसमें आगे की कानूनी रणनीति पर चर्चा की जानी है।

सरकार के सामने 80 हजार कर्मचारियों का सवाल

इस मामले का असर उन करीब 80 हजार शिक्षकों और संविदा शिक्षकों पर पड़ सकता है, जिनकी नियुक्ति प्रदेश में नई पेंशन योजना लागू होने से पहले हुई थी। एनपीएस की जगह ओपीएस लागू होने पर सरकार को इन कर्मचारियों की पुरानी सेवा को पेंशन लाभ के लिए जोडऩा पड़ेगा।

मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री से मिलीं विधायक अनुभा मुंजारे

महिला के साथ थाने में हुई मारपीट और किसानों के मुद्दे रखे

आगामी बजट में क्षेत्र को प्राथमिक से शामिल कराने का आग्रह
धान फसल में रोग से नुकसान और उपार्जन पंजीयन की अवधि बढ़ाने की मांग

पदमेश न्यूज। बालाघाट। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को गति देने और किसानों से जुड़े मुद्दों को शासन के समक्ष प्रमुखता से रखने के लिए विधायक अनुभा मुंजारे ने भोपाल प्रवास के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की। विधायक ने मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री तथा बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से उनके निज निवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों तथा आगामी बजट में क्षेत्र की प्राथमिक आवश्यकताओं को शामिल कराने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। विधायक की ओर से विभिन्न विकास कार्यों को बजट में शामिल करने के संबंध में मंत्री को पत्र भी सौंपा गया।

मुलाकात के दौरान बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की सड़क, अधोसंरचना, पुल-पुलिया सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने की मांग रखी गई। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में कई विकास कार्य लंबे समय से अपेक्षित हैं, जिनके लिए शासन स्तर से आवश्यक वित्तीय स्वीकृति और बजट उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के तीव्र एवं संतुलित विकास के लिए आगामी बजट में प्राथमिकता वाले कार्यों को स्थान देने का आग्रह किया। विधायक के अनुसार प्रभारी मंत्री के साथ क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई है और शासन से आवश्यक सहयोग मिलने की उम्मीद है। इसी क्रम में विधायक अनुभा मुंजारे ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात कर बालाघाट जिले और विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उनके समक्ष रखे। विधायक ने मुख्यमंत्री को किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए धान की फसल में माहू और ब्लास्ट रोग के प्रकोप से हुए नुकसान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि जिले के कई क्षेत्रों में फसल प्रभावित होने से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल फसल सर्वे कराकर वास्तविक नुकसान का आकलन किया जाए और पात्र किसानों को उचित मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराई जाए। धान उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन में आ रही दिक्कतों का मुद्दा भी विधायक ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान उपार्जन पंजीयन की निर्धारित अवधि बढ़ाने की मांग की, ताकि तकनीकी अथवा अन्य कारणों से कोई पात्र किसान पंजीयन से वंचित न रह जाए। विधायक ने कहा कि बालाघाट कृषि प्रधान जिला है और यहां बड़ी संख्या में किसान धान की खेती पर निर्भर हैं। इसलिए किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए पंजीयन प्रक्रिया में आ रही समस्याओं का समय रहते समाधान जरूरी है। विधायक ने किरनापुर क्षेत्र के ग्राम टिमकी टोला निवासी सावित्री बाई चौधरी के साथ हुई घटना का विषय भी मुख्यमंत्री के सामने रखा और मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई तथा पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग की। इसके अलावा बालाघाट-लालबर्रा विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण, पुल-पुलिया, विद्यालयों के उन्नयन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं से संबंधित विकास कार्यों को लेकर भी मुख्यमंत्री से चर्चा की गई। विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं और विकास की आवश्यकताओं को लेकर वह लगातार शासन स्तर पर आवाज उठा रही हैं। उनका प्रयास है कि क्षेत्र में जरूरी विकास कार्यों के लिए स्वीकृति और पर्याप्त बजट उपलब्ध हो तथा किसानों की समस्याओं का भी समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास से जुड़े विषयों को सदन से लेकर शासन स्तर तक लगातार उठाया जाता रहेगा।

पीछे से आई तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने साइकिल को मारी टक्कर

साइकिल सवार गंभीर- आंख बाहर निकली और पैर हुआ फेक्चर
फर्नीचर का काम कर घर लौट रहे 55 वर्षीय सालिकराम सड़क पर तड़पते मिले, हालत गंभीर-हायर सेंटर रेफर

पदमेश न्यूज। बालाघाट। शहर से अपने गांव लौट रहे एक 55 वर्षीय साइकिल सवार के लिए बुधवार की शाम जिंदगी की सबसे दर्दनाक शाम बन गई। गोंदिया रोड पर नवेगांव हुंडई एजेंसी के पास पीछे से तेज रफ्तार में आई मोटरसाइकिल ने साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि साइकिल सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में उसकी दाहिनी आंख बाहर निकल गई जबकि दाहिने पैर में गंभीर फ्रैक्चर हो गया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घायल व्यक्ति सालिकराम पिता मायाराम उपवंशी 55 वर्ष ग्राम खुरसोडी थाना ग्रामीण नवेगांव बालाघाट निवासी है जिसे जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार कोमल पिता नकुल कोलते 25 खुरसोडी निवासी भी घायल हुआ है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। बताया गया की घटना के दौरान यह युवक शराब के नशे में था।

रोज साइकिल से आता था बालाघाट, बुधवार को हादसे ने बदल दी जिंदगी

बताया गया है कि सालिकराम खेती-किसानी के साथ फर्नीचर का काम भी करते हैं। परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं। दोनों बेटे अलग-अलग रहते हैं। जबकि सालिकराम अपनी पत्नी के साथ गांव में रहते हैं। फर्नीचर के काम के सिलसिले में वे प्रतिदिन साइकिल से बालाघाट आते-जाते हैं बुधवार 7 अक्टूबर को भी सालिकराम रोज की तरह सुबह साइकिल से बालाघाट आए थे। दिनभर फर्नीचर का काम करने के बाद शाम करीब 7:30 बजे वे साइकिल से अपने गांव खुरसोडी के लिए रवाना हुए। उन्हें क्या पता था कि घर पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले ही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल उनकी जिंदगी को गंभीर संकट में डाल देगी।

पीछे से मारी जोरदार टक्कर

सालिकराम गोंदिया रोड पर नवेगांव हुंडई एजेंसी के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से तेज रफ्तार में आ रही मोटरसाइकिल ने उनकी साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही सालिकराम साइकिल समेत सड़क पर जा गिरे। हादसे में उनके चेहरे और पैर में गंभीर चोटें आई। दाहिनी आंख बाहर निकलने और पैर बुरी तरह टूटने से उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई। वहीं मोटरसाइकिल सवार कोमल कोलते भी सड़क पर गिरकर घायल हो गया। बताया गया है कि यह युवक घटना के दौरान शराब के नशे में था। उसे भी उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है।

डायल 112 ने पहुंचाया अस्पताल, पुलिस जांच में जुटी

हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट पहुंचाया। चिकित्सकों ने सालिकराम का प्राथमिक उपचार करने के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों मोटरसाइकिल की रफ्तार और हादसे की परिस्थितियों की जांच कर रही है।

एक तरफ रोजी-रोटी के लिए साइकिल से शहर आने वाला एक मेहनतकश व्यक्ति गंभीर जिंदगी-मौत की जंग लड़ रहा है तो दूसरी तरफ सड़क पर तेज रफ्तार और लापरवाही एक परिवार को गहरे संकट में डाल गई है।

सड़क हादसे के बाद घायल युवक को घेरे-मारपीट कर वसूले 1000 रुपए

मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त होने का हवाला देकर युवकों ने दी जान से मारने की धमकी, बहन के कमरे से दिलवाए रुपए

पदमेश न्यूज। बालाघाट। नगर के सरस्वती नगर रोड पर चेतक एजेंसी के सामने दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत के बाद घायल हुए युवक के साथ मारपीट कर एक हजार रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। आरोप है कि हादसे के बाद दूसरी मोटरसाइकिल सवार युवक ने अपने चार-पांच साथियों को बुला लिया और घायल युवक से मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त होने के एवज में रुपए की मांग की। रुपए नहीं होने की बात कहने पर उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। घायल युवक दीपक पिता खेलू नगपुरे 22 वर्ष ग्राम बगदरा ग्रामीण थाना बालाघाट निवासी है जिसका जिला अस्पताल में उपचार कराया गया है।

बहन से मिलने जैन अस्पताल जा रहा था दीपक

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बगदरा थाना ग्रामीण निवासी दीपक नगपुरे निजी काम करता है। उसकी बहन जैन अस्पताल में नर्सिंग का कोर्स कर रही है और अस्पताल के पास ही एक कमरे में रहती है। 6 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे दीपक अपनी मोटरसाइकिल से बहन से मिलने जैन अस्पताल जा रहा था। इसी दौरान सरस्वती नगर रोड स्थित चेतक एजेंसी के पास सामने से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल दीपक की मोटरसाइकिल से टकरा गई। टक्कर के बाद दीपक मोटरसाइकिल सहित सड़क पर गिर गया और उसे चोटें आई।

हादसे के बाद बुलाए साथी-शुरू कर दी मारपीट

बताया गया कि दूसरी मोटरसाइकिल सवार युवक ने फोन कर अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया। कुछ ही देर में चार-पांच युवक वहां पहुंच गए। उन्होंने दीपक से कहा कि उनकी मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई है। इसलिए उसे रुपए देने होंगे। दीपक ने रात होने का हवाला देते हुए तत्काल रुपए नहीं होने की बात कही। आरोप है कि इसके बाद युवकों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देने लगे।

बहन के कमरे पर ले जाकर दिलवाए 1000 रुपए

दीपक ने युवकों से कहा कि उसकी बहन जैन अस्पताल के पास रहती है और वहां से रुपए दिलवा सकता है। इसके बाद दीपक इन युवकों को अपनी बहन के कमरे पर ले गया जहां से एक हजार रुपए दिलवाए गए। घटना में दीपक की मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई और उसे चोटें भी आईं थी।

कोतवाली पहुंचा,- पुलिस ने कराया उपचार

घटना के बाद दीपक अपनी बहन के साथ रात में ही शिकायत करने कोतवाली पहुंचा पुलिस ने उसे पहले उपचार कराने की सलाह दी। इसके बाद दीपक जिला अस्पताल पहुंचा और अपना उपचार कराया। मारपीट करने वाले युवकों में एक युवक का नाम राहुल बताया गया है जो महारानी कलेक्शन में काम करता है जिला अस्पताल पुलिस ने घायल दीपक के बयान दर्ज कर मामले को आगे की कार्रवाई के लिए कोतवाली पुलिस को भेज दिया है। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गर्भवती महिला प्रकरण के बाद किरनापुर थाने में बड़ा फेरबदल

चार पुलिसकर्मी पहले ही निलंबित, आपराधिक प्रकरण दर्ज, अब करीब दो दर्जन कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू

पदमेश न्यूज। बालाघाट। किरनापुर पुलिस थाना इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। पिछले माह गर्भवती महिला के साथ कथित मारपीट के मामले में पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए चार पुलिस कर्मचारियों को निलंबित कर पुलिस लाइन अटैच किया गया था। इसके बाद थाने के घेराव और प्रदर्शन के पश्चात निलंबित किए गए चारों पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस प्रशासन ने किरनापुर थाने में पदस्थ करीब दो दर्जन पुलिस कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

गर्भपात के बाद भ्रूण हत्या का मामला भी दर्ज

बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया था। जहां उसका गर्भपात हो गया। इसके बाद इस मामले में भ्रूण हत्या का प्रकरण भी दर्ज किया गया है। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस प्रशासन ने किरनापुर थाने में पदस्थ पुलिसकर्मियों की तैनाती को लेकर भी व्यापक स्तर पर बदलाव की कार्रवाई शुरू कर दी है।

थाने के कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू

मामले को लेकर लगातार उठ रहे सवालों और कार्रवाई के बीच अब किरनापुर थाने में पदस्थ करीब दो दर्जन पुलिस कर्मचारियों को हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन कर्मचारियों के स्थान पर पुलिस लाइन के साथ-साथ जिले के अन्य पुलिस थानों में पदस्थ कर्मचारियों को किरनापुर थाने में तत्काल प्रभाव से पदस्थ करने की कार्रवाई की जा रही है।

कार्रवाई से पुलिस महकमे में हलचल

एक ही प्रकरण के बाद किरनापुर थाने में लगातार हो रही कार्रवाई से पुलिस महकमे में भी हलचल है। पहले चार कर्मचारियों का निलंबन फिर उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण और अब थाने में बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया ने इस पूरे घटनाक्रम को और महत्वपूर्ण बना दिया है पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही इस कार्रवाई को थाने की कार्यप्रणाली में बदलाव और मामले के बाद प्रशासनिक स्तर पर उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल नए पुलिसकर्मियों की पदस्थापना की प्रक्रिया जारी है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक उमेश बागरेचा द्वारा पद्मेश पब्लिकेशन, वार्ड नं.9, गुजरी चौक, बालाघाट (म.प्र.) से मुद्रित कराकर दैनिक बालाघाट एक्सप्रेस कार्यालय, काली पुतली चौक, बालाघाट(म.प्र.) से प्रकाशित,
प्रधान संपादक : उमेश बागरेचा, मो.नं. :**9425138710**, , ई-मेल- balaghatexpress@gmail.com पंजीयन क्रं. MPHIN/2009/32311, न्यायालयीन क्षेत्राधिकार बालाघाट